सिविल सर्विसेस मासिक

— अप्रैल 2020 —

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020
- ऑपरेशन SHIELD
- ई–नाम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताएं
- आईआर कोड बिल
- अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की बिक्री बढ़ी
- कोविड–19 महामारी के बीच शिक्षा
- करमी–बॉट रोबोट
- स्वास्थ्य संस्थान को साइबर हमलों का खतरा
- सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हुआ
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग
- ICH की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा क मामलों में बढ़ोतरी
- भारत में आर्थिक संकुचन
- मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्युट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड ऐनलिसीस
- कुरुक्षेत्र अप्रैल 2020
- योजना अप्रैल 2020

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

नीति एवं शासन

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 1
बीटीएडी में राज्यपाल शासन 2
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 2020 2
ऑपरेशन SHIELD 4
स्वछता–मोहु (MoHUA)ऐप 5
शक्ति परीक्षण राज्यपाल का विवेक है 8

अर्थव्यवस्था

ई–नाम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताएं 9
किसान रथ मोबाइल एप 9
आईआर कोड बिल 11
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के तहत बैंकिंग 13
कोविड–19 से लड़ने के लिए RBI के उपाय 14
कोरोना बॉंड 18
अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की बिक्री बढ़ी 20

समाज एवं स्वास्थ्य

विद्यादान 2.0 20
स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट – 2020 21
कोविड–19 महामारी के बीच शिक्षा 22
समाधान 23

विज्ञान एवं तकनीक

सोडियम हाइपोक्लोराइट 24
प्रचुर मात्रा में लिथियम से युक्त लाल दानव तारा 26
कोविड–19 का सामुहिक परीक्षण 27
करमी–बॉट रोबोट 29
अटल टिंकरिंग लैब्स में CollabCAD 30
सत्यम कार्यक्रम 31

आंतरिक सुरक्षा

पिच ब्लैक रद्द 32
स्वास्थ्य संस्थान को साइबर हमलों का खतरा 33

भूगोल एवं पर्यावरण

वर्चुअल पीट्र्सबर्ग जलवायु संवाद 34
सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हुआ 37
असम हाथी रिजर्व में खनन के लिए वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी 38

अंर्तराष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग 38
ऑपरेशन संजीवनी 40

कला एवं संस्कृति

दक्षिण भारत में नववर्ष का स्वागत 40
ICH की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ 41
बोहाग या रोंगालीबिहू 42

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी 44
खाद्यान्न की कमी का खतरा – यूएन, एफएओ एवं डब्ल्यूटीओ 45
भारतीय प्रवासी और चुनौतियां 47
जीआई टैग 48

सामान्य अध्ययन II

मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) एवं वेतन में कटौती 51
केरल और कर्नाटक के बीच राजमार्ग युद्ध 52
विधान परिषद के चुनाव 53
पालघर लिंचिंग 54
भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों को कड़ा किया 58

सामान्य अध्ययन III

भारत में आर्थिक संकुचन 60
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट 64
बौद्धिक संपदा अधिकार 65
साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम (CSS) 66
सिपरी रिपोर्ट 69
आर्मीवर्म हमला 72

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्युट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड ऐनलिसीस 72

कुरुक्षेत्र अप्रैल 2020 74

योजना अप्रैल 2020 81

प्रारंभिक परीक्षा

नीति एवं शासन

विश्व प्रस स्वतंत्रता सूचकांक 2020

समाचार –

- मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोटर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया है। यह रिपोर्ट 2002 से प्रकाशित हो रही है।
- यह मीडिया की स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है।
- सूचकांक बहुलतावाद, मीडिया स्वतंत्रता, प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया स्वतंत्रता के उल्लंघन के स्तर के संकेतक को दर्शाता है।
- सूचकांक 180 देशों में कानूनी ढांचे की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा को भी मापता है।
- नॉर्वे लगातार चौथे साल पहले स्थान पर है।
- फिनलैंड और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे।
- भारत दो स्थान गिरकर 142 वें स्थान पर रहा।
- देश में 2018 में 6 पत्रकारों की हत्याओं के विरूद्ध, 2019 में, देश में पत्रकारों की हत्या नहीं हुई।
- यह दर्शाता है कि देश की मीडिया की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है।

प्रेस स्वतंत्रता पर कोविड–19 का प्रभाव

- मीडिया स्वतंत्रता और बहुलवाद मौलिक अधिकारों के यूरोपीय चार्टर और मानव अधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन में परिकल्पित अधिकारों और सिद्धांतों का हिस्सा हैं।
- लेकिन यह हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक और निरंकुश सरकारों के उदय के कारण लोकतांत्रिक और गैर–लोकतांत्रिक देशों में सुर्खियों में आया है।
- इसलिए इस सूचकांक 2020 में, यह तर्क दिया गया है कि मीडिया की स्वतंत्रता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अगले दशक को महत्वपूर्ण माना जाएगा।
- मीडिया की स्वतंत्रता के लिए इस खतरे को अक्सर कई विश्व–नेताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो मुक्त समाज के बुनियादी पहलू के बजाय, मुक्त मीडिया को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं।
- मीडिया स्वतंत्रता समर्थकों ने आगाह किया है कि दुनिया भर की सरकारें स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नए, कड़े प्रतिबंधों को लागू करने और प्रेस सेंसरशिप के विस्तार के बहाने कोरोनोवायरस आपातकाल का उपयोग कर सकती हैं।
- कई देशों में, इस तरह के कारणों से संकट का सामना किया है, राजनीतिक नेताओं ने मीडिया स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंधों के औचित्य के रूप में इसका उपयोग किया है।
- कुछ सरकारों ने संकट का उपयोग मीडिया सीमाओं को लागू करने के लिए किया है जो कि सामान्य समय में असंभव होगा।
- काउंसिल ऑफ यूरोप (CoE) प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने आगाह किया है कि कोविड–19 महामारी के बीच मीडिया स्वतंत्रता पर नए हमले ने पहले से ही निराशाजनक मीडिया स्वतंत्रता दृष्टिकोण को खराब कर दिया है।

खुली अदालत में मामलों की सुनवाई

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अदालत की सुनवाई में भाग लेने, पर प्रतिबंध लगाया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों को लागू करके खुली अदालत प्रणाली पर जोर दिया।
- शीर्ष अदालत ने माना कि सभी लगाए गए प्रतिबंध वैध हैं।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि खुली अदालत प्रणाली सामाजिक सुरक्षा मानदंड और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कोविड–19 महामारी के मद्देनजर न्याय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
- अदालतों की सीमाओं के भीतर पारंपरिक संचालन को कम करना उस दिशा में एक उपाय है।
- अदालत ने कहा कि सार्वजनिक हित प्रथाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका को 'वीडियोकॉनफ्रेंसिंग तकनीकों' पर भारी सुधार करना और जारी रखना होगा।
- यह विवेक का नहीं बल्कि कर्तव्य का विषय है और इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति और संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वायरस के संचरण को कम करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों के कार्यान्वयन में सहयोग करे।

- यह आवश्यक है कि सभी स्तर पर अदालतें सोशल डिस्टेंसींग का आह्वान करे और यह सुनिश्चित करें कि अदालत परिसर वायरस के प्रसार में योगदान न करें।
- कोविड–19 की अगुवाई में चुनौतियों को संबोधित किया जाना चाहिए, जो इसे चाहने वालों को न्याय प्रदान करने और उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को संरक्षित करते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतंत्र में कानून के शासन को संरक्षित करने के लिए न्याय तक पहुंच मौलिक है।
- अनुच्छेद 142 (भाग V) उच्चतम न्यायालय को किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक किसी भी आदेश को पारित करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 142 (1) – अपने अधिकार क्षेत्र के अभ्यास में सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के निर्णय को पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है।
- ऐसा किया गया कोई भी फरमान या पारित किया गया आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में इस तरह लागू किया जा सकता है, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, जब तक कि इसका प्रावधान तैयार नहीं हो जाता है, तब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसे निर्धारित किया सकता है।

बीटीएडी में राज्यपाल शासन

समाचार –

- बोडोलैंड टेरिटोरियल जनरल काउंसिल के कार्यकाल का 5 वर्ष का कार्यकाल 27 अप्रैल, 2020 को समाप्त हो गया।
- कोविड–19 महामारी के बीच नए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं।
- इस प्रकार, इसे पहली बार राज्यपाल के शासन में रखा गया है।
- यह सत्ताधारी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के लिए एक झटका है।
- सत्तारूढ़ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, जल्द से जल्द कार्यकाल या चुनाव का विस्तार चाहता था।
- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) प्रशासन चार जिलों (कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी और बक्सा) को कवर करता है और सामूहिक रूप से बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स (BTAD) कहलाता है।
- राज्य का राज्यपाल बीटीएडी का संवैधानिक प्रमुख है जो संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है और बीटीसी द्वारा प्रशासित है।
- छठी अनुसूची के अनुसार, 4 राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) में जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों से तकनीकी रूप से भिन्न हैं।
- हालांकि ये क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ विधायी और न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के लिए जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक जिला एक स्वायत्त जिला है और राज्यपाल अधिसूचना द्वारा उक्त जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को संशोधित कर सकते हैं।

बीटीसी के बारे में

- बीटीसी भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- दो बोडो समझौते (1993 और 2003) हुए हैं और दूसरे ने बीटीसी का गठन किया।
- दूसरे BODO समझौते ने सशस्त्र आंदोलन के अंत को चिह्नित किया।
- हाल ही में, जनवरी 2020 में, केंद्र, असम सरकार और बोडो समूहों, जिसमें आतंकवादी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सभी गुट शामिल हैं, ने शांति और विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- BTC के चुनाव पहली बार 2005 में हुए थे और तब से बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) द्वारा शासित है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 2020

समाचार –

- प्रतिवर्ष, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिन 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने (24 अप्रैल, 1993 से लागू होने) के बाद से मनाया जाता है।
- जमीनी स्तर पर समस्या को समझने के लिए, जो कठिन कार्य था, यह निर्णय लिया गया कि लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए।

- पूर्व भारतीय पीएम राजीव गांधी को पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है।
- इस वर्ष, भारत के प्रधानमंत्री ने गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए दो वेब पोर्टल ई–ग्राम स्वराज और स्वमित्व योजना शुरू की।
- ई–ग्राम स्वराज ऐप गांवों में परियोजनाओं को पूरा करने की योजना को पूरा करने में मदद करेगा।
- यह पंचायतों को विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक एकल इंटरफेस प्रदान करेगा।
- गांवों में संपत्तियों के मानचित्रण में ड्रोनों का उपयोग करके संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।

पंचायती राज –

- 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की।
- 1959 में पंचायत राज स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था।
- इसके बाद उसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी इसे अपनाया गया।
- इसके बाद, अधिकांश राज्यों ने प्रणाली को अपनाया।

- भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में उल्लिखित है।

- ग्राम पंचायत गाँव स्तर पर टियर की सबसे निचली इकाई है और गाँव स्तर की जिम्मेदारियों को देखती है। इसके सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पाँच वर्षों के लिए किया जाता है। प्रत्येक पंचायत एक राष्ट्रपति या सरपंच और एक उप–राष्ट्रपति या उपसरपंच का चुनाव करता है। वह पंचायत समिति में एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है।

- पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है जिसमें एक खंड विकास अधिकारी होता है जो गांवों के एक समूह की देखभाल करता है। इसमें क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर 20 से 10 गांव शामिल हैं। समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसे ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों से और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से दो महिला सदस्यों और एक सदस्य को चुना जाता है।

- जिला स्तर पर जिला परिषद सबसे ऊपर है।
- सभी खंड विकास अधिकारी जिला परिषद के प्रति जवाबदेह हैं।
- यह स्तरीय पंचायत समिति की सहायता से जिला स्तर पर विकास योजनाएँ बनाती है।
- जिला परिषद का अध्यक्ष इसके सदस्यों में से चुना जाता है।
- अधिकांश भाग के लिए, जिला परिषद समन्वय और पर्यवेक्षी कार्य करता है।
- यह पंचायत समितियों की गतिविधियों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाता है।
- कुछ राज्यों में, जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट को भी मंजूरी देती है।

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को संज्ञेय तथा गैर–जमानती अपराध बनाने के लिए अध्यादेश पारित

- कोविड–19 मामलों के परीक्षण या उपचार में लगे डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है।
- उनके वाहन उन लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे, जिन्हें उनके द्वारा संक्रमित होने की आशंका थी।
- एक अध्यादेश में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों पर हमले को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध बनाया गया है।
- इसमें इन अपराधों की जांच में तेजी लाने और सात साल तक की सजा पाने वालों को कैद करने का प्रावधान करेगा।
- इसमें बर्बरता और संपत्ति के नुकसान पर कठोर दंड का प्रावधान है।
- इसने महामारी रोग अधिनियम, 1897 में भी संशोधन किया है।
- ओडिशा सरकार ने कोविड 19 के प्रसार से निपटने के लिए एक अध्यादेश भी लागू किया है।
- ओडिशा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 में संशोधन करके ऐसा किया है।
- जो कोई भी अधिनियम के तहत किए गए किसी भी दिशानिर्देश या अनुरोध को टालता है, वह दो साल तक की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों के लिए जिम्मेंदार होगा है।
- अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे।
- 1897 अधिनियम के तहत किए गए किसी भी नियम की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दंडनीय माना गया था।
- कोविड–19 प्रकोप के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की विशेष खरीद के लिए अध्यादेश में भी प्रावधान किया गया है।
- ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भी नियमों को तैयार किया है जिसमें दो प्रावधान हैं।
- पहला प्रावधान यह है कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनना अपराध माना जाएगा।

CHAHAL ACADEMY

- दूसरा प्रावधान यह है कि मास्क न पहनने के पहले तीन मामलों के लिए जुर्माना 200 रुपये रखा गया है इसके बाद प्रत्येक बार इसे ना पहनने पर जुर्माना 500 रुपये होगा।

ऑपरेशन SHIELD

दिल्ली प्रशासन ने कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए ऑपरेशन SHIELD की घोषणा की है।

SHIELD का पूर्ण रूप है –

S – भौगोलिक अंकन के बाद तत्काल क्षेत्र की **सीलिंग।**

H – क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के हाऊस क्वेरेंटाईन।

I – पहले और दूसरे संपर्क वाले लोगों का **आईसोलेशन**।

E – **एसेंशीयल** (आवश्यक) वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

L – अधिकारियों द्वारा **लोकल** क्षेत्र की स्वच्छता।

D – क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए **डोर टू डोर** स्वास्थ्य जांच।

मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (पीएमआरयू)

समाचार

- मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (PMRU) ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की स्थापना की।
- वर्तमान स्थिति, जब देश कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तब दवाओं की कमी /जमाखोरी के स्थानीय मुद्दों की पहचान करने और कारणों की पहचान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है।
- जम्मू–कश्मीर इसे स्थापित करने वाला 12 वां राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
- NPPA द्वारा पहले से ही 11 राज्यों केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में PMRU स्थापित किए जा चुके हैं।

पीएमआरयू के कार्य –

- एनपीपीए, राज्य ड्रग्स कंट्रोलर और राज्य ड्रग इंस्पेक्टरों के बीच दवा की कीमतों की निगरानी के लिए एक क्षेत्र–स्तरीय लिंक की अनुपस्थिति के कारण, पीएमआरयू स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।
- यह एक पंजीकृत संस्था है।
- यह जम्मू और कश्मीर के राज्य ड्रग कंट्रोलर के तत्काल नियंत्रण और निगरानी के अधीन कार्य करता है।
- यह एनपीपीए और राज्य ड्रग कंट्रोलर को सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- यह सभी के लिए दवाओं की उपलब्धता और सार्मथ्य के क्षेत्रों में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य जानकारी, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों का आयोजन करतर है।
- एनपीपीए द्वारा इसकी आवर्ती और गैर–दोहराई जाने वाली लागतों के लिए वित्त पोषित।
- यह दवाओं के नमूने एकत्र करता है, जानकारी इकट्ठा करता है और जांच करता है।
- यह दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) की व्यवस्था के तहत दवाओं की उपलब्धता और अधिक कीमत के संबंध में रिपोर्ट बनाता है।

पीएमआरयू की संरचना –

- राज्य के स्वास्थ्य सचिव – अध्यक्ष
- ड्रग कंट्रोलर – सदस्य सचिव।
- सदस्य – एक राज्य सरकार, निजी दवा कंपनियों और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के प्रतिनिधि।
- कार्यकारी समिति – ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा संचालित।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण –

- एक सरकारी नियामक एजेंसी।
- दवा दवाओं की लागत को नियंत्रित करता है।
- 29 अगस्त 1997 को गठित।
- डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची I में सूचीबद्ध आवश्यक दवाओं की छत की कीमतें तय करता है।
- अन्य – राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण नीति (एनपीपीपी) – मूल्य नियंत्रण करती है।
- **दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO)** – मूल्य नियंत्रण को लागू करता है, राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण नीति – 2018 – दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक नियामक ढांचा है।

आदिवासी शिक्षकों के लिए 100 प्रतिशत कोटा नहीं – उच्चतम न्यायालय

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय की पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में आदिवासी शिक्षकों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण देना असंवैधानिक है।
- न्यायालय ने यह भी पाया कि आदिवासी द्वारा आदिवासी को पढ़ानाएक 'अप्रिय विचार' है।
- यह मामला, 10 जनवरी, 2000 के आदेश, तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य की एक बेंच द्वारा दिये गये निर्णय को दी गई कानूनी चुनौती से उत्पन्न हुआ है।
- इस फैसले में अदालत ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए अजजा आवेदकों (जिनमें से 33.33 प्रतिशत महिलाएं होंगी) को 100 प्रतिशत आरक्षण दिया।
- अदालत ने कहा कि वर्ष 2000 का आदेश 'अनुचित और मनमाना' था।
- नागरिकों के पास समान अधिकार हैं।
- भारत के संविधान के संस्थापक पिताओं द्वारा एक वर्ग के लिए बनाए गए अवसरों से दूसरों के अहित के बारे में नहीं सोचा था।
- अदालत ने पाया कि 100 प्रतिशत आरक्षण भेदभावपूर्ण है।
- सार्वजनिक रोजगार का अवसर अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकार नहीं है।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण ने अजा और अपिव को उनके उचित प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया है।
- अदालत ने इंदिरा साहनी के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षण 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था।
- यह फैसला इस तरह के कार्यक्रमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन समाज के बाकी हिस्सों के लिए हानिकारक तरीके से उन्हें लागू करने के प्रति सावधानी है।
- डॉ. आर. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में समानता खंड पर बहस के दौरान पाया था कि कोई भी आरक्षण सामान्यतः 'सीटों के अल्पसंख्यक' के लिए होना चाहिए।
- यह अभी तक कुल आरक्षण पर न्यायालय द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत कैप, भले ही विशेष परिस्थितियों में कुछ भत्ता या छूट के साथ, के पक्ष में चर्चा का विषय है।
- यह अभी भी बहस का विषय है कि क्या यह सीमा सही है या इसे हटाया जाना चाहिए।
- इस तरह की चर्चा इस विचार से नहीं करना चाहिए कि अजा के एक बड़े भाग के कार्यवाही हो रही है। (विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची असामान्य विनियमन के तहत प्रदेशों में रहने वाली।)

गन्ना मूल्य निर्धारण

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय की पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संविधान की समवर्ती सूची के तहत गन्ने के मूल्य को तय करने की शक्ति रखती हैं।
- बेंच ने कहा कि हालांकि एक राज्य 'न्यूनतम मूल्य' तय नहीं कर सकता है, भले ही केंद्र ने इसे ठीक कर दिया हो, राज्य, सलाह दी गई कीमत या पारिश्रमिक मूल्य को ठीक करने के लिए लगातार स्वतंत्र है।
- यह मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार न्यूनतम मूल्य से अधिक होगा, जो उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 16 के तहत जारी किया गया था।
- जब सलाह दी गई कीमत न्यूनतम मूल्य से कम है, तो न्यूनतम मूल्य प्रबल होगा।
- जब तक सलाह दी गई कीमत न्यूनतम मूल्य से अधिक है तब तक इसे संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत समतुल्य नहीं माना जा सकता है।
- **अनुच्छेद 254** – संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से संबंधित है।

स्वछता–मोहु (MoHUA)एप

समाचार –

- वर्तमान स्वछता का संशोधित संस्करण – आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा MoHUA ऐप लॉन्च किया गया है।
- ऐप में कोविड–19 संबंधित मदद मांगों को शामिल किया गया है जिसमें फोगिंग/स्वच्छता, भोजन, आश्रय और संगरोध/लॉकडाउन के रिपोर्टिंग उल्लंघन शामिल हैं।
- यह स्वच्छ भारत मिशन का आधिकारिक मंच है।

- यह एक व्यवहार्य डिजिटल उपकरण (ई–गवर्नेंस) के रूप में काम करता है, जो नागरिकों को उनके शहरों के स्वच्छता में एक कार्यशील भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के संबंध में जवाबदेही बढ़ाता है।
- ऐप एक नागरिक को नागरिक–संबंधित मुद्दे जैसे लैंडफिल, सार्वजनिक शौचालय की सफाई इत्यादि पर पोस्ट करने का अधिकार देता है।
- शिकायत तब संबंधित नगर निगम को भेजी जाती है और उस बिंदु से विशिष्ट वार्ड के सेनेटरी इंस्पेक्टर को सौंपी जाती है।
- शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) इस ऐप पर पोस्ट की गई सभी शिकायतों को हल करने में सक्षम हैं।
- नई कोविड–19 श्रेणियों के तहत पोस्ट की गई शिकायतें महत्वपूर्ण हैं, ULBs को शिकायतों को सीधे हल करने या संबंधित विभागों के साथ नागरिक को जोड़ने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।
- यूएलबी को शिकायतों की स्थिति की जांच करने और उसी के समाधान की गारंटी देने की आवश्यकता है।

निःशुल्क परीक्षण और उपचार

समाचार –

- एक अभूतपूर्व संकट कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में, निजी क्षेत्र को एक प्रमुख साथी और हितधारक के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोविड–19 का निःशुल्क परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया है।
- यह मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के तहत प्रदान किया जाएगा।
- ये परीक्षण ICMR द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार और ICMR द्वारा अनुमोदित/पंजीकृत निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाएंगे।

उद्देश्य –

- परीक्षण और उपचार सुविधाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के दिशा–निर्देशों के अनुसार AB–PMJAY के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोप–वे तक पहुँच बढ़ाने के लिए।

- आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी राज्य समर्थित स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में देखा जाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) देश भर में एबी–पीएमजेएवाई के डिजाइन, रोल–आउट, निष्पादन और प्रबंधन के लिए जवाबदेह शीर्ष सरकारी एजेंसी है।
- राज्यों ने पहले ही निजी क्षेत्र के अस्पतालों को केवल कोविड–19 अस्पतालों में बदलने के लिए सूचीबद्ध किया है।
- अस्पताल अपनी अनुमोदित परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं या योजना के लिए अनुमोदित परीक्षण सुविधा के साथ जुड़ सकते हैं।
- निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 परीक्षण के लिए ICMR दिशानिर्देशों के अनुसार, परीक्षण को एक प्रयोगशाला द्वारा निर्देशित किया जाना है जिनमें राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के लिए रियल टाईम पोलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए NABL द्वारा मान्यता है।
- नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) देश में गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है।

निःशुल्क परीक्षण का महत्व –

- भारत भर में नामित निजी अस्पतालों में निःशुल्क परीक्षण और समय पर और मानक उपचार का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान प्राप्तकर्ताओं की सहायता होती है।
- सरकार की क्षमताओं का विस्तार होता है और गरीब लोगों पर इस महामारी के विरोधी प्रभाव को दूर करने में सहायता मिलती है।
- कोरोनोवायरस रोगियों को परीक्षण और उपचार प्रदान करने के लिए अधिक निजी क्षेत्र के खिलाड़ी आकर्षित होंगे।

थोक दवा निर्माताओं और बिचौलियों को ईआईए से छूट दी गई

समाचार –

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 तक पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) से कोविड–19 के इलाज के लिए थोक दवाओं के निर्माताओं और बिचौलियों को छूट दी थी।
- यह संशोधन 30 सितंबर 2020 तक प्राप्त सभी प्रस्तावों पर लागू है।

CHAHAL ACADEMY

- राज्यों को भी इस तरह के प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए सलाह जारी की गई है।
- विभिन्न बीमारियों का सामना करने के लिए निर्मित, बड़े पैमाने पर दवाओं और बिचौलियों के संबंध में सभी परियोजनाओं या गतिविधियों को वर्तमान श्रेणी 'ए' से 'बी 2' श्रेणी में फिर से आदेशित किया गया है।
- बी 2 श्रेणी के तहत परियोजनाओं को बेस लाइन डेटा, ईआईए अध्ययन और सार्वजनिक परामर्श के संग्रह की आवश्यकता से मुक्त किया गया है।

महत्व –

- राज्य स्तर पर मूल्यांकन के विकेंद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने ताकि इस प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक किया जा सके में महत्वपूर्ण।
- कम समय के भीतर देश में महत्वपूर्ण दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में मदद।
- दिए गए समय–सीमा के भीतर प्रस्तावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों को सूचना प्रौद्योगिकी (वीडियो सम्मेलन) का उपयोग करने की भी सलाह दी है।
- यह इस तथ्य पर विचार करते हुए किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सभाओं के माध्यम से सिफारिशों का मूल्यांकन संभव नहीं है।

कोविड–19 के बीच फंडिंग

समाचार –

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने पीएम–केयर फंड में राष्ट्रीयताओं से परे विदेश से धन योगदान स्वीकार करने का फैसला किया है।
- अब विदेशी सरकारें, गैर सरकारी संगठन और देशवासी इस कोष में योगदान दे सकते हैं।
- पीएम–केयर फंड का निरीक्षण भारत के पीएम सहित इसके ट्रस्टियों द्वारा चुने गए मूल्यांकनकर्ताओं के एक स्वतंत्र दल द्वारा किया जाएगा।
- यह कहा गया है कि पीएम केयर्स में योगदान 'सहायता(aid)' नहीं है। इसमें विदेशी योगदान 'केवल' प्रधान मंत्री–कोष के लिए प्रासंगिक है और प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरह किसी अन्य निधि के लिए नही।
- पीएम–केयर फंड को FCRA अधिनियम के सभी प्रावधानों के संचालन से छूट मिली है और अब वे विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान स्वीकार कर सकते हैं।
- यह दान विदेशी क्रेडिट/डेबिट कार्ड और वायर ट्रांसफर/स्विफ्ट के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है।
- इस उद्देश्य के लिए एक अलग बैंक खाता खोला गया है।
- यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि दानकर्ता ऑनलाइन पोर्टल से औपचारिक दान रसीदें डाउनलोड कर सकेंगे।
- गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राज्यों को बेघर लोगों को, जिनमें फंसे हुए प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, 'अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल, आदि' प्रदान करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) का उपयोग करने के लिए अधिकृत करें।
- सरकार ने कोविड–19 को 'अधिसूचित आपदा' के रूप में माना है।

फंडिंग की पिछली घटनाएँ

- सरकार ने 2018 में बाढ़ग्रस्त केरल में विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया।
- सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वह दिसंबर 2004 में निर्धारित आपदा सहायता नीति का पालन कर रही थी।
- दिसंबर 2004 में भारत में सुनामी की चपेट में आने के बाद, प्रशासन को लगा कि यह अकेले ही सामना कर सकता है।
- तब से, भारत ने विदेशी सरकारों से सहायता स्वीकार नहीं करने की नीति का पालन किया है।
- हालिया कदम एक बड़ा नीतिगत बदलाव है क्योंकि भारत ने पिछले 16 वर्षों में किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया है।

प्रधान मंत्री कोष (प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत)

- इसे 27 मार्च, 2020 को पंजीकृत ट्रस्ट डीड के साथ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की आपातकालीन, आपदा या संकट से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता के लिए है, या तो मानव निर्मित या प्राकृतिक है।
- इसमें हेल्थकेयर या फार्मास्युटिकल सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन, प्रासंगिक अनुसंधान या किसी अन्य प्रकार की सहायता शामिल है।
- फंड के लिए दान 100 प्रतिशत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

PM-CARES की संरचना

- प्रधानमंत्री चेयरपर्सन के रूप में
- रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री,
- प्रधान मंत्री द्वारा नामित तीन ट्रस्टी 'जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे'।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)

- एसडीआरएफ को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शामिल किया गया है।
- यह राज्य सरकार के साथ अधिसूचित आपदाओं के लिए सुलभ राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक निधि है।
- केंद्र ने सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसडीआरएफ आवंटन में 75 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90 प्रतिशत का योगदान दिया है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय अंशदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।
- एसडीआरएफ के तहत आने वाली आपदाएं – चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला, ठंड और ठंडी लहरें हैं।
- राज्य सरकार एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध धन का 10 प्रतिशत तक का उपयोग आपदाओं जिन्हें वे 'आपदा' मानते हैं और जिन्हें गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं किया गया है, के हताहतों को तुरंत राहत देने के लिए कर सकती है।

शक्ति परीक्षण राज्यपाल का विवेक है

समाचार –

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गवर्नर यदि वह वास्तव में सत्ता में सरकार के बारे महसूस करता है कि उसने सदन में बहुमत खो दिया है तो किसी भी समय शक्ति परीक्षण के लिए बुला सकता है।
- अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विश्वास मत के लिए राज्यपाल की आवश्यकता स्पीकर के समक्ष लंबित किसी भी अयोग्यता अंकन कार्यवाही को 'शॉर्ट–सर्किट' नहीं करती है।
- अदालत ने यह कहा कि एक राज्यपाल को विश्वास मत की आवश्यकता से पहले बागी विधायकों के इस्तीफे पर अध्यक्ष की पसंद का इंतजार नहीं करना चाहिए।
- वे विधायक होते है, न कि राज्यपाल, जिन्होंने अंतिम आह्वान किया था कि सरकार को सत्ता में रहना चाहिए या नहीं।
- राज्यपाल की शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने की क्षमता केवल चुनाव के तुरंत बाद राज्य सरकार की स्थापना से पहले ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान जारी रहती है।

शक्ति परीक्षण –

- शक्ति परीक्षण एक प्रस्ताव है जो सरकार द्वारा यह जानने के लिए शुरू किया गया है कि क्या इसे विधायिका के विश्वास का आनंद प्राप्त है।
- इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री को विधान सभा में बहुमत साबित करने के लिए संपर्क किया जाएगा।
- जब शक्ति परीक्षण किया जाता है, तो मुख्यमंत्री विश्वास मत हासिल करेंगे और साबित करेंगे कि उनके पास बहुमत का समर्थन है।
- यदि शक्ति परीक्षण विफल हो जाता है, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा।
- संवैधानिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में शक्ति परीक्षण के पूरे विचार को शामिल किया गया है।

विश्लेषण –

- विश्वास मत को अंतर्निहित करने का विचार निर्वाचित सरकार की राजनीतिक जवाबदेही को राज्य विधानमंडल तक बनाए रखना है।
- एक विश्वास मत के समन्वय में, राज्यपाल एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेता है।
- यह अपरिहार्य है कि एक विश्वास मत के विशेष समय में बहुमत रखने वाली पार्टी के प्रति संतुलन को झुकाया जा सकता है।
- सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से अपने निर्वाचित विधायकों का समर्थन खोने का खतरा है, जैसे कि विधायकों को मतदाताओं के वोट खोने का खतरा है।
- इस प्रकार संसदीय शासन की प्रणाली संचालित होती है।
- विश्वास मत के पीछे का उद्देश्य सक्षम होना था

अविश्वास प्रस्ताव –

- अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास मत, किसी भी सदन सदस्य द्वारा यह व्यक्त करने के लिए मांगे जा सकते हैं कि उन्हें अब सरकार में विश्वास नहीं है।

शक्ति परीक्षण –

- यह बहुमत के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री) के बहुमत के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है।
- गठबंधन सरकार के मामले में, मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करने और बहुमत जीतने के लिए कहा जा सकता है।

अर्थव्यवस्था

ई–नाम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताएं

समाचार –

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने किसानों द्वारा कृषि विपणन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एनएएम) मंच की नई विशेषताओं को लॉन्च किया।
- यह प्रयास अपनी फसल बेचने के लिए किसानों के शारीरिक रूप से थोक मंडियों में आने की आवश्यकता को कम कर देगा।
- ये कार्यक्रम किसानों को मंडियों में आए बिना अपने खेत के गेट के करीब पारिश्रमिक कीमतों पर अपनी उपज बेचने में मदद करेंगे।
- राज्यों को मंडियों में जाए बिना बड़े पैमाने पर खरीददारों/प्रोसेसर और बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रत्यक्ष खरीद की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- लॉजिस्टिक मॉड्यूल का संवर्धित संस्करण भी जारी किया गया है।
- जिससे परिवहन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के एग्रीगेटर्स सवार हुए हैं जो उपयोगकर्ताओं को अपनी उपज के परिवहन के लिए ट्रैक करने योग्य परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
- ई–एनएएम को 14 अप्रैल 2016 को पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था, जो राज्यों में एपीएमसी को जोड़ता था।
- 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी रूप से 585 मंडियों को इस पोर्टल पर समन्वित किया गया है।
- ई–एनएएम ने किसी भी समय भुगतान के लिए मोबाइल–आधारित संपर्क रहित दूरस्थ बोली को समायोजित किया जा सकता है, जिसके लिए व्यापारियों को मंडियों या बैंकों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है।
- ई–एनएएम अच्छी तरह से एक ही समय में किसानों की मदद करते हुए निर्णायक मंडियों में कोविड–19 की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस प्रयोजन के लिए, ई–एनएएम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए तीन मॉड्यूलों का अनुसरण किया गया है।

नीगोशीएबल वेयरहाऊस रसीद (ई–एनडब्ल्युआर) मॉड्यूल	एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल	लॉजिस्टिक मॉड्यूल
भुगतान संबंधी सुविधाओं के साथ वेयरहाऊस ट्रेडिंग मॉड्यूल छोटे एवं सीमांत किसानों को भंडारित अनाज को WDRA पंजीकृत वेयरहाऊस पर बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान WDRA पंजीकृत वेयरहाऊस में अपने सामान को रख सकते हैं।	दुरस्थ बोली लगाने वालों के लिए बोली लगाने से पहले उत्पाद को देखने में मदद करने के लिए FPO को उत्पाद एवं गुणवत्ता पेरोमीटर की फोटो अपलोड करने में सक्षम बनाया गया है।	व्यापारीयों द्वारा लॉजिस्टक जरूरतों के क्वांटम रिसपोंस के लिए बड़े लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स को लिंक करने के प्रावधान है जिसस उपयोगकर्ताओं को विकल्प उपलब्ध होते हैं। व्यापारी लॉजिस्टिक प्रोवाईडर की वेबसाईट पर जा सकते हैं एवं ऊचित सेवाओं का चयन कर सकते हैं। इन सुविधाओं के साथ लॉजिस्टि प्रोवाईडरों की तरफ से 3,75,000 से अधिक ट्रक लॉजिस्टिक उद्धेश्यों से जोड़े जा सकते हैं।
लाभ डिपॉज़ीटर अधिक लॉजिस्टिक खर्चों को बचा सकता है एवं अधिक आय प्राप्त कर सकता है। किसान मंडी में जाने की अफरी तफरी से बचकर संपूर्ण देश में फसलों को बेच सकते हैं एवं बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं। किसान WDRA वेयरहाऊस में अपनी फसलों को रख सकते हैं तथा आवश्यकता होने पर प्लेज लोन ले सकते हैं। मांग एवं पूर्ति को पूर्ण करते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रख सकते हैं।		इससे कृषि उत्पादों के यातायात में मदद मिलेगी। इससे ई–नाम के अंर्तगत विभिन्न खरीददारों को यातायात सुविधा उपलब्ध करवाकर अंर्तराज्यीय व्यापार में वृद्धि की जा सकती है।

किसान रथ मोबाइल एप

समाचार –

- कृषि मंत्रालय ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।
- यह लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और खराब हो सकने वाले खाद्यान्नों के परिवहन की सुविधा के लिए है।

- यह मोबाइल एप्लिकेशन किसानों और व्यापारियों को कृषि और बागवानी उत्पादन के लिए परिवहन की खोज करने के लिए सहायता करता है।
- यह ऐप भारत में किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह एक उपयुक्त परिवहन सुविधा का पता लगाने में मदद करेगा।
- यह उनकी कृषि उपज को फार्म गेट से बाजारों में स्थानांतरित करने में मदद करेगा।

ड्राफ्ट बिजली अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020

समाचार –

- विद्युत मंत्रालय ने 2014 के बाद से बिजली (संशोधन) विधेयक का चौथा मसौदा प्रदान किया, जिसका उद्देश्य विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) स्थापित करना है।
- मसौदे के अनुसार ईसीईए के पास बिजली उत्पादन कंपनियों (गेनस) और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बीच बिजली खरीद या बिक्री से संबंधित अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित मामलों की जांच करने का एकमात्र अधिकार होगा।
- ईसीईए के फैसले को अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
- वर्तमान में, राज्य विद्युत नियामक आयोग और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग क्रमशः राज्य–स्तरीय और अंतर–राज्य पीपीए विवादों का निपटारा करते हैं।
- ईसीईए की स्थापना से राज्य और केंद्रीय नियामक आयोगों की शक्ति कम हो जाएगी।
- डिस्कॉम और जेनकोस के बीच PPA (पावर परचेज एग्रीमेंट्स) से संबंधित बिजली के मामलों का कमजोर पड़ना।
- मंत्रालय ने अलग कैरिएज के लिए 2014 में लोकसभा में पहला मसौदा पेश किया और बिजली वितरण व्यवसाय का विरोध किया।
- बिल उपभोक्ताओं को अपने सेवा प्रदाताओं को बदलने का विकल्प दे सकता था।
- लेकिन लोकसभा के विघटन के बाद बिल लैप्स हो गया।
- दूसरा और तीसरा ड्राफ्ट क्रमशः 2018 और 2019 में प्रसारित किया गया था।
- विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि विद्युत अधिनियम पूरे देश पर लागू होगा, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।
- यह यह भी बताता है कि क्रॉस (पावर) सीमा व्यापार भारत और किसी अन्य देश से बिजली के आयात या निर्यात को कवर करेगा।
- भारत के माध्यम से बिजली के लेन–देन से संबंधित लेनदेन को दो अन्य देशों के बीच पारगमन के रूप में माना जाएगा।
- मसौदा कानून बिजली वितरण उप–लाइसेंसधारी या फ्रेंचाइजी की शुरुआत के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे राज्य आयोग से अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
- उनके बारे में जानकारी प्रदान करना पर्याप्त होगा।
- यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति बनाने का भी आह्वान करता है।
- यह नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को अतिरिक्त भूमिका प्रदान करता है जिसमें अनुबंधों के अनुसार देश भर में बिजली का समय–निर्धारण और प्रेषण शामिल है।
- बिल कहता है कि जब तक अनुबंध के अनुसार भुगतान की पर्याप्त सुरक्षा नहीं होगी तब तक बिजली का कोई शेड्यूल या डिस्पैच नहीं होगा।
- विधेयक राज्य और केंद्रीय बिजली नियामकों को खुली पहुंच के तहत ट्रांसमिशन लागत को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- इससे पहले, दोनों कार्य केवल केंद्रीय आयोग के पास थे।

संप्रभु स्वर्ण बॉंड्स

समाचार –

- भारिबैं द्वारा जारी संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड या SGB सोने की लागत के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और एक निश्चित ब्याज दर की पेशकश करते हैं।
- परिपक्वता के समय, बांड के मालिक को सोने की वर्तमान लागत के अनुसार बांड का मूल्य मिलता है।
- सोने की मांग को भौतिक बचत के रूप में सोने की मांग को वित्तीय बचत में बदलने के लिए पेश किया गया है।
- गोल्ड बॉन्ड में निवेश का ऑनलाइन तरीका निवेशकों की सभी श्रेणियों के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल निवासी व्यक्तियों के लिए ही सीमित है, जिनमें व्यक्ति HUF, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ प्रतिष्ठान शामिल हैं।

कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक जारी किया

समाचार –

- कमोडिटी बाजार आउटलुक 2020 विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है।
- यह ऊर्जा, धातु, कृषि, कीमती धातुओं और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण वस्तु समूहों के लिए बाजार विश्लेषण दिखाता है।
- रिपोर्ट में तेल सहित 46 प्रमुख वस्तुओं की कीमतें हैं।
- यह आउटलुक मूल रूप से अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित होता है।

झलकियाँ –

- कमोडिटी बाजारों पर महामारी का पूर्ण प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यह कितनी गंभीर है, यह कब तक चलती है और देश तथा विश्व समुदाय इस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं।
- महामारी में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में स्थायी परिवर्तन करने की क्षमता है।
- यह परिवर्तन विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित होगा जो उन वस्तुओं को दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक ले जाती हैं।
- प्रभाव नाटकीय रूप से, विशेष रूप से परिवहन से संबंधित वस्तुओं में होगा।
- तेल की कीमतों में गिरावट आई है और 2020 में मांग में अभूतपूर्व कमी आने की उम्मीद है।
- जबकि अधिकांश खाद्य बाजार सभी उपलब्ध कराए गए हैं, खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि देश व्यापार प्रतिबंधों की घोषणा करते हैं और अति–खरीद में संलग्न होते हैं।
- आर्थिक गतिविधियों में ठहराव ने औद्योगिक वस्तुओं जैसे तांबा और जस्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- इस साल धातु की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है।
- कमोडिटी–निर्भर उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं महामारी के आर्थिक प्रभावों के लिए सबसे कमजोर होंगी।

आईआर कोड बिल

समाचार –

- श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने औद्योगिक संबंध संहिता की सिफारिशें की हैं।
- कोड ट्रेड यूनियनों अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है।
- दूसरी पीढ़ी के श्रम सुधारों की स्थापना के लिए, एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना लोगों को बंद करने या इकाइयों को बंद करने के लिए 300 कर्मचारियों के साथ कंपनियों को अनुमति देने के विचार को बढ़ावा दिया।
- यह वर्तमान सीमा से तिगुनी वृद्धि थी।
- इस संदर्भ में, समिति नोट करती है कि राजस्थान जैसी कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही 300 कर्मचारियों तक सीमा बढ़ा दी है।
- मंत्रालय के अनुसार इसके परिणामस्वरूप रोजगार में विस्तार हुआ है और छंटनी में गिरावट आई है।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके 2014 के अंत में राजस्थान इस तरह का परिवर्तन करने वाला पहला राज्य था।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को लागू करने के लिए राज्यों को विचार के महीनों के बाद छोड़ दिया गया।
- राज्य ने विचार किया था कि इस कदम से रोजगार के अवसरों का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
- इसने केंद्र सरकार को औद्योगिक संबंध (आईआर) कोड बिल में इस छूट को स्पष्ट करने की सलाह दी है।
- यह भी सलाह दी जाती है कि इसे कार्यकारी आदेशों के माध्यम से संसद में बिल पारित होने के बाद नियम–निर्माण के दौरान निर्धारित किए जाने के लिए खुला नहीं छोड़ा जाए।
- रिपोर्ट में श्रम सुधारों पर व्यापक राजनीतिक आम सहमति दिखाई गई है।

अन्य सुझाव –

- केंद्र को एक औपचारिक और अनुकूल औद्योगिक संबंध ढांचा तैयार करना चाहिए।
- केंद्र कोड में विभिन्न प्रावधानों को मजबूत करके ऐसा करना चाहता है।
- प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक कि उद्योग की फिर से स्थापना नहीं हो जाती है।
- कानून को समझदार होना चाहिए, ऐसे मामलों में सरकार द्वारा उद्योगों के लिए कुछ सहायता प्रदान करना और उन्हें व्यापक बनाना है।

- कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अधिकारों को रेखांकित करने के लिए एक अलग और एक विशेष अध्याय बनाया जाना चाहिए।
- यह ILO सम्मेलनों पर आधारित औद्योगिक संबंधों से संबंधित सिद्धांतों से युक्त होना चाहिए।
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय को आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, आदि जैसे श्रमिकों के लिए योजना को शामिल करना चाहिए।
- सरकार को कार्यकर्ता/कर्मचारी की एक समेकित और विलय की परिभाषा प्रदान करनी चाहिए।
- मिलाई गई परिभाषाओं के माध्यम से पर्यवेक्षक, प्रबंधक आदि अपनी जगह उसमें खोज सकते हैं।

आगे को राह –

- यदि सरकार पैनल के सुझाव को मान लेती है, तो इसे व्यवसायों द्वारा एक साहसिक श्रम सुधार के रूप में देखा जाएगा लेकिन श्रमिक यूनियनों द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं –

- नियम ट्रेड यूनियनों की मान्यता, हड़ताल एवं लॉक–आउट के लिए नोटिस, स्थायी आदेश और औद्योगिक विवादों के समाधान प्रदान करता है।
- ट्रेड यूनियन जिसमें कम से कम 10 प्रतिशत श्रमिकों की सदस्यता है या 100 श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। एक प्रतिष्ठान में 75 प्रतिशत श्रमिकों के साथ संघ एकमात्र बातचीत करने वाला संघ होगा। अन्यथा, यूनियनों की एक वार्ता परिषद बनाई जाएगी।
- एक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता है जब तक कि वह हड़ताल करने से पहले छह सप्ताह के भीतर और इस तरह के नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर हड़ताल के लिए नोटिस न दे।
- श्रमिकों के लॉक–आउट के लिए समान प्रावधान मौजूद हैं।
- 100 श्रमिकों के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों पर स्थायी आदेश तैयार करना होगा और उन्हें प्रमाणित करना होगा।
- फैक्टरियों, खानों या बागानों जिसमें 100 या अधिक श्रमिकों को काम पर रखा जाता है, अपने कर्मचारियों को लेटने या पीछे हटने से पहले केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है।
- संहिता औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान करती है।
- प्रत्येक औद्योगिक न्यायाधिकरण में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होगा।

पाम तेल के आयात पर अंकुश

- 13 अप्रैल, 2020 को भारत ने कोविड–19 महामारी के बीच शिपमेंट के प्रबंधन के लिए ताड़ के तेल के आयात पर अंकुश लगा दिया था।
- नई शर्तों के तहत, ताड़ के तेल के आयात के लिए प्राधिकरण को पूर्व खरीद समझौते और मूल के प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए जिसे अनिवार्य बनाया गया है।
- यह प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि माल कहाँ से आता है।
- ताड़ के तेल का आयात लाइसेंस भी 18 महीने के स्थान पर 6 महीने कर दिया गया है।
- मूल प्रमाण पत्र के नियम उन देशों के लिए आवश्यक हैं जिनके साथ भारत के व्यापार समझौते हैं।
- भारत वनस्पति तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है और सालाना लगभग 15 मिलियन टन खरीदता है।
- मलेशिया और इंडोनेशिया भारत को भी पाम तेल का निर्यात करते हैं।
- मलेशिया और इंडोनेशिया एक साल में क्रमशः 19 मिलियन और 43 मिलियन टन ताड़ के तेल का उत्पादन करते हैं।
- जनवरी 2020 में, भारत (शीर्ष वैश्विक पाम तेल खरीदार) ने परिष्कृत पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
- यह मलेशिया की कश्मीर और सीएए, 2019 में भारत के कार्यों की आलोचना के प्रतिशोध में था।

खुदरा महंगाई दर में कमी

समाचार –

- खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट पर मार्च 2020 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2020 में 5.91 प्रतिशत तक कम हो गई।
- मार्च 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति 8.76 प्रतिशत थी जो फरवरी 2020 में 10.81 प्रतिशत हो गई।
- डेटा को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया गया था।
- जबकि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण कुछ डेटा गायब था।
- पिछले साल नवंबर के बाद यह पहली बार है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के लक्षित ऊपरी बैंड 6 प्रतिशत से नीचे आ गई है।

पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के तहत बैंकिंग

समाचार –

- बैंकिंग उद्योग को 21 अप्रैल 2020 को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है।
- कोरोनोवायरस महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत श्रम मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।
- यह तात्पर्य है कि बैंकिंग क्षेत्र में कानून के संचालन के दौरान कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई भी हड़ताल नहीं होगी।

भारतीय बैंक संघ –

- बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय।
- इसे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ के रूप में स्थापित किया गया था और यह मुंबई में स्थित है।
- इसे 1946 में भारत में 22 बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रारंभिक सदस्यता के साथ बनाया गया था।
- इसका गठन भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय और मजबूती के लिए किया गया था।
- यह नए तरीकों के कार्यान्वयन और सदस्यों के बीच मानकों को अपनाने सहित विभिन्न तरीकों से सदस्य बैंकों की मदद करता है।
- आईबीए वर्तमान में भारत में कार्यरत 237 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
- आईबीए का प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान प्रबंध समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 मानद सचिव और 26 सदस्य होते हैं।
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक IBA के सदस्य हैं।
- कुछ सबसे पुराने विदेशी बैंक HSBC, StanChart और Citi Bank भी इसका हिस्सा हैं।
- नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के ऋणदाता जैसे कोटक बैंक, इंडसल्ड बैंक और यस बैंक IBA मानदंडों के दायरे से बाहर हैं।

प्रेषण में गिरावट

समाचार –

- विश्व बैंक ने आगाह किया था कि 2020 में वैश्विक प्रेषण में लगभग 20 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।
- ऐसा नए कोरोनवायरस और देश भर में बंद के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण हुआ है।
- कोविड–19 द्वारा लाई गई निरंतर मौद्रिक मंदी नकदी घर भेजने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।
- विश्व बैंक जी–20 देशों और दुनिया भर में नेटवर्क के साथ काम कर रहा है ताकि प्रेषण लागत को कम किया जा सके और गरीब लोगों के लिए वित्तीय समावेशन में सुधार किया जा सके।

झलकियाँ

- विप्रेषण गरीबी को कम करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह शिक्षा पर अधिक खर्च और व्याकुल परिवारों में बाल श्रम को कम करने में भी मदद करता है।
- प्रेषणों में गिरावट से इन क्षेत्रों पर खर्च करने की परिवारों की क्षमता प्रभावित होती है क्योंकि उनके वित्त का अधिक उपयोग भोजन की कमी और तत्काल आजीविका की जरूरतों को हल करने के लिए किया जाएगा।
- विप्रेषण परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
- आर्थिक मंदी शायद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों से दक्षिण एशिया में प्रेषण बहिर्वाह को प्रभावित करने वाली है।
- तेल की कीमतें गिरने से खाड़ी देशों से प्रेषण बहिर्वाह पर भी असर पड़ेगा।
- 2019 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, दक्षिण एशिया के लिए विप्रेषण इस वर्ष 22 प्रतिशत घटकर 109 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए प्रेषण में मंदी वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रेरित है।
- वैश्विक आर्थिक मंदी कोरोनोवायरस प्रकोप के साथ–साथ तेल की कीमत में गिरावट के कारण है।
- भारत, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान और मैक्सिको दक्षिण एशिया में प्रेषण के प्रमुख रिसीवर हैं।
- भारतीय राज्यों में, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रेषण के प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं।

CHAHAL ACADEMY

- हाल के इतिहास में अनुमानित गिरावट सबसे तेज थी।
- प्रवासी श्रमिकों को एक मेजबान देश में इस आर्थिक संकट के दौरान रोजगार और मजदूरी के नुकसान की अधिक संभावना थी।
- कमजोर और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) को प्रेषण में 19.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो कई कमजोर घरों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण जीवनरेखा के नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।

कविड–19 से लड़ने के लिए RBI के उपाय

समाचार –

- RBI ने अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को कम करने और उन क्षेत्रों में तनाव को कम करने के उपायों की घोषणा की जहां दर्द तीव्र होता जा रहा है।
- ऐसे खंड वित्त, एनबीएफसी, सूक्ष्म–वित्त संस्थान, वाणिज्यिक अचल संपत्ति और आवास जैसे थे।
- एनबीएफसी में लक्षित 50,000 रुपये का 25 बेसिस प्वाइंट रिवर्स रेपो कट, टीएलटीआरओ (लक्षित दीर्घकालिक पुनर्वित्त विकल्प)। परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों में छूट। आरबीआई ने राज्यों के लिए वेज़ एंड मीन्स एडवांस (डब्लूएमए) के तहत सीमा बढ़ा दी है ताकि मौजूदा सीमा का 60 प्रतिशत तक अल्पकालिक निधि प्राप्त हो सके। डब्ल्यूएमए की बढ़ी हुई सीमा ऐसे समय में आती है जब सरकारी खर्च बढ़ने की उम्मीद होती है क्योंकि यह फैलने वाले कोरोनावायरस के पतन से लड़ता है। इन निधियों की उपलब्धता से सरकार को दीर्घावधि के बाजार उधार के ऊपर और ऊपर अल्पकालिक व्यय करने के लिए कुछ जगह मिलेगी।
- क्षेत्रीय क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की गई – यह विशेष रूप से नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों की तरलता को बढ़ावा देने के लिए है।
- 90 दिनों के एनपीए (नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स) मानदंडों में ढील दी गई है।
- RBI ने बैंकों के लिए काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (CCyB) के कार्यान्वयन को भी टाल दिया है। यह निर्णय लिया है कि एक वर्ष या उससे पहले की अवधि के लिए CCyB को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।
- CCyB एक बैंक द्वारा रखी जाने वाली पूंजी है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक चक्र संबंधी जोखिमों को पूरा करना है। इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रों में मंदी जैसे परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बैंकिंग क्षेत्र की रक्षा करना है। यह बासेल III मानदंडों का एक महत्वपूर्ण विषय है।

एनबीएफसी के साथ समस्याएं

- एनबीएफसी को कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये संस्थाएँ अपने ग्राहकों को स्थगन प्रदान कर रही हैं, फिर भी उन्हें बैंकों और अन्य उधारकर्ताओं को चुकाना जारी रखना है।
- बैंक NBFC द्वारा लिए गए टर्म लोन पर कोई मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। इसने कई एनबीएफसी की तरलता प्रोफाइल पर महत्वपूर्ण दबाव डाला है।
- जबकि कुछ बैंक एनबीएफसी ऋणों पर रोक लगाने की पेशकश कर रहे हैं, कुछ बड़े बैंकों ने ऐसी किसी भी सुविधा से इंकार किया है।
- एनबीएफसी पहले से ही आईएल एंड एफएस और डीएचएफएल संकट के कारण तरलता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- एनबीएफसी क्षेत्र के लिए कुल बैंक ऋण बकाया जनवरी 31, 2020 के रूप में 7,37,198 करोड़ रुपये था, जो वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 32.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- लॉकडाउन, इकाइयों को बंद करने और नौकरी के नुकसान के कारण ग्राहकों के संग्रह में गिरावट आई है।
- लगभग 60 प्रतिशत एनबीएफसी उधार गैर–बैंक स्रोतों से हैं और ऋण सर्विसिंग में निरंतरता की आवश्यकता है।
- न्यूनतम संग्रह के साथ, एनबीएफसी केवल अपने नकदी भंडार और बैंकों से किसी भी बैकअप क्रेडिट लाइनों पर निर्भर कर सकते हैं, अगर इस तरह के ऋण की सेवा के लिए उपलब्ध है।

विश्लेषण –

- आरबीआई की तरलता बढ़ाने के उपायों में, महत्वपूर्ण फैसलों में राज्य सरकारों की डब्ल्यूएमए सीमा में बढ़ोतरी और रिवर्स रेपो दर में कमी शामिल है। दोनों उपायों का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को उत्प्रेरित करना है।
- रिवर्स रेपो दर में कमी से बैंकों को उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने में मदद मिलेगी।

- एनपीए के मानदंडों को आसान बनाने से बैंकों का ऋण देने का विश्वास बढ़ सकता है। TLTRO के माध्यम से, RBI कॉरपोरेट्स को ऋण देने के लिए सस्ता पैसा प्रदान करेगा। लेकिन अतीत में, इसके साथ अनुभव यह रहा है कि बैंक सबसे अच्छी क्रेडिट योग्य कंपनियों को देते हैं।
- आरबीआई की तरलता इंजेक्शन रियल एस्टेट क्षेत्र में मदद कर सकता है, जो सबसे बड़े रोजगार निर्माताओं में से एक है।
- 31 जुलाई, 2020 तक किए गए निर्यात आय की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन की समय अवधि, जो निर्यातकों को विस्तारित अवधि के भीतर विशेष रूप से कोविड–19 प्रभावित देशों से, उनकी प्राप्तियों का एहसास करने और निर्यातकों को भविष्य में बातचीत करने के लिए अधिक लचीलापन देने में सक्षम बनाएगी। विदेश में खरीदारों के साथ निर्यात अनुबंध।
- राज्य सरकारों की डब्लूएमए (तरीके और साधन अग्रिम) सीमा में वृद्धि से राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसमें राज्य अपने लंबित भुगतान कर सकते हैं।
- डब्ल्यूएमए एक ऐसी योजना है जो सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में बेमेल को पूरा करने में मदद करती है। इसमें, एक सरकार RBI से तत्काल नकद का लाभ उठा सकती है।
- लॉकडाउन की अवधि ऋणदाताओं के लिए दर्द का कारण होगी, विशेष रूप से एमएसएमई, एयरलाइंस, रियल एस्टेट, ऑटो डीलरों, जवाहरात और आभूषणों, धातुओं सहित क्षेत्रों के ऋण खातों में।
- बैंक MSME के ऋणों और उन विनिर्माण क्षेत्रों के लिए चिंतित हैं, जैसे कि ऑटो, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि जहां ताजा एनपीए कम हो रहे हैं।
- यह इस तथ्य के बावजूद है कि आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में ताजा तरलता को इंजेक्ट किया है और बैंकों को ऋण खातों में संभावित तनाव से निपटने के लिए ऋण दिया है।

क्या ये उपाय कारगर होंगे?

- प्रभावशीलता अधिकारियों के प्रतिक्रिया कार्यों की विश्वसनीयता के हितधारकों की धारणा पर निर्भर करती है।
- पहले से ही कमजोर आर्थिक व्यवस्था के लिए झटका एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था, पहला काम अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है।

आगे की राह –

- RBI द्वारा किए गए उपायों से अगले तीन महीनों के दौरान बैंकों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बुरे ऋणों का निर्माण अपरिहार्य लगता है। जबकि अधिस्थगन उधारकर्ताओं को अस्थायी राहत प्रदान करता है और उस अवधि के दौरान एनपीए की जांच करने में मदद करता है।
- जैसे ही भारत ने कोविड–19 के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज की, आरबीआई संकट का जवाब देने और मुद्दों को लक्षित करने में लगने वाले समय में शीर्ष धावक बन गया।

विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा विश्लेषण –

- **मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस** – यह आर्थिक गतिविधि में व्यवधान के कारण बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट की उम्मीद करता है। इसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दृष्टिकोण को स्थिर से नकारात्मक में बदल दिया है।
- **क्रिसिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट** – परिसंपत्ति वर्गों को उधारकर्ताओं के कमजोर प्रोफाइल और केवल क्रमिक आर्थिक सुधार की उम्मीद के कारण संपत्ति की गुणवत्ता पर निरंतर दबाव दिखाई देगा। विनिर्माण और सेवाओं दोनों से 35 क्षेत्रों के अध्ययन में, कोविद–19 परिदृश्य के बाद लचीलापन में तेज बदलाव है।
- **उच्च लचीलो श्रेणी** – फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG), उर्वरक, तेल रिफाइनरियां, बिजली और गैस वितरण और ट्रांसमिशन में लगभग 44 प्रतिशत ऋण शामिल हैं।
- **मध्यम लचीलो श्रेणी** – एक और 52 प्रतिशत ऋण ऑटोमोबाइल निर्माताओं, बिजली जनरेटर, सड़कों और निर्माण जैसे क्षेत्रों में है।
- **कम लचीली श्रेणी** – माल और सेवाओं के विवेकाधीन स्वरूप और कमजोर बैलेंस शीट को देखते हुए एयरलाइंस, रत्न और आभूषण, ऑटो डीलर और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में लगभग 4 प्रतिशत ऋण।

वैश्विक व्यापार की मात्रा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमी

समाचार –

- विश्व व्यापार संगठन ने 2020 में वैश्विक व्यापार के 13 प्रतिशत से 32 प्रतिशत के बीच तक कहीं गिरने का अपना दृष्टिकोण जारी किया।

- व्यापार और विकास रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने अपने व्यापार और विकास रिपोर्ट में पाया है कि 2020 में कोविड–19 के कारण आर्थिक अनिश्चितता की संभावना की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लागत 1 ट्रिलियन डॉलर होगी।
- यह अवलोकन UNCTAD द्वारा जारी वर्ल्ड ईकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2020 रिपोर्ट पर पर आधारित है।

वैश्विक व्यापार –

- विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि यह अधिक निश्चित है कि व्यापार के लिए विघटन और परिणामी झटका सभी संभावनाओं में होगा और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट द्वारा लाई गई मंदी से भी बदतर होगा। अभी एक महामारी की चपेट में आई दुनिया में एकमात्र निश्चितता, गुप्त–अनिश्चितता, है।
- आईएमएफ ने पाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में तेजी से सिकुड़ने के लिए तैयार है, जिसमें दुनिया भर में अरबों को प्रभावित करने वाली महामारी से लड़ने के लिए 'लॉकडाउन की जरूरत है'।
- डब्ल्यूटीओ को उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों में इस साल निर्यात और आयात में दोहरे अंक की गिरावट आएगी और इसके 'आशावादी परिदृश्य' के तहत भी आयात किया जाएगा, जो दूसरी छमाही में शुरू होने वाली वसूली को नियंत्रित करता है।
- विश्व व्यापार संगठन और आईएमएफ ने इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि मंदी के विपरीत जो वैश्विक वित्तीय संकट एक दशक पहले था से परे वर्तमान डाउनटर्न अद्वितीय है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जटिलता में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उत्पादों जैसे उद्योगों में, उन्हें वर्तमान व्यवधानों के लिए विशेष रूप से कमजोर बना दिया गया है, उन देशों के साथ जो इन मूल्य संपर्कों का एक हिस्सा हैं जो व्यापार को और अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए निर्धारित हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था

- इस वर्ष के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2 प्रतिशत से कम की मंदी की परिकल्पना की गई है, जिसकी कीमत शायद 1 ट्रिलियन डॉलर होगी।
- निजी खपत, निवेश और निर्यात में मामूली कमी और सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ, वैश्विक विकास 2020 में घटकर 1.2 प्रतिशत हो जाएगी।
- चीन से आपूर्ति–श्रृंखला में रुकावट और प्रमुख उत्पादकों के बीच तेल की अनिश्चितता के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार–चढ़ाव जारी है।
- सबसे कम विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था कच्चे माल की बिक्री से संचालित होती है, उन्हें भी कठिन परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
- भारी–भरकम विकासशील देशों, विशेष रूप से कमोडिटी निर्यातकों, एक मजबूत अमेरिकी डॉलर से जुड़े कमजोर निर्यात रिटर्न के कारण एक विशिष्ट खतरे का सामना करते हैं।

आगे की राह –

- यदि राष्ट्र महामारी के बाद माल, सेवाओं और लोगों के आंदोलन में नए अवरोध पैदा नहीं करते हैं तो विश्व को सर्वाधिक लाभ होगा।
- एक स्थानीय स्वास्थ्य मंदी को वैश्विक आर्थिक मंदी में बदलने से रोकने के लिए समर्पित नीति प्रतिक्रियाओं और संस्थागत सुधारों की एक श्रृंखला की आवश्यकता है।
- आने वाले समय में अधिक नुकसानदायक मंदी को रोकने के लिए सरकारों को अब खर्च करने की आवश्यकता है।
- 2021 में अपेक्षित पुनर्प्राप्ति के अनुमान समान रूप से अनिश्चित हैं, परिणाम प्रकोप की अवधि और नीति प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता पर काफी हद तक निर्भर करते हैं।

कटाई के मौसम पर कोविड–19 लॉकडाउन का प्रभाव

समाचार –

- भारत में कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के बाद, भारत के चावल निर्यात की आपूर्ति श्रृंखला निलंबित कर दी गई थी।
- मार्च–जून के दौरान एकत्र किए जा रहे गैर–टिम्बर वन उत्पाद (NTFP) की बिक्री में बाधा उत्पन्न करके, इसने ओडिशा के आदिवासियों के लाखों लोगों को प्रभावित किया था।
- एकत्रित किए गए प्रमुख एनटीएफपी में जंगली शहद, इमली, आम, तेंदू के पत्ते, साल के पत्ते, महुआ के बीज, नीम के बीज, करंज (पोंगामिया) के बीज, महुआ के फूल और तेजपत्ता (तेज पत्ता) शामिल हैं।
- वन उत्पाद प्रकृति में मौसमी हैं और आदिवासी मार्च से जून के महीनों में अपनी प्रमुख आय (60 प्रतिशत – 80 प्रतिशत) कमाते हैं।

- इन महीनों के दौरान अर्जित कठिन नकदी मानसून के मौसम के दौरान उनके भरण–पोषण के लिए महत्वपूर्ण होती है जब रोजगार सूख जाते हैं।
- यहां तक कि भारतीय व्यापारियों ने भी विदेशी खरीदारों को उद्धरण देना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि वे अपने माल को जहाजों पर लादने में सक्षम होंगे।
- लदान बंद होने के कारण परिवहन धीमा हो गया है।
- भारत के निर्यात की मात्रा में चार से पांच गुना की कमी आई थी।
- मार्च–अप्रैल डिलीवरी के लिए लगभग 400,000 टन गैर–बासमती चावल और 100,000 टन बासमती चावल या तो लॉकडाउन के कारण बंदरगाहों पर या रास्तों में फंस गए हैं।
- भारत मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल, बेनिन और सेनेगल को गैर–बासमती चावल और ईरान, सऊदी अरब और इराक को प्रीमियम बासमती चावल का निर्यात करता है।
- भारतीय चावल निर्यात में ठहराव ने थाईलैंड जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों को अल्पावधि में शिपमेंट बढ़ाने की अनुमति दी है।

श्रम मुद्दा

- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य कटाई के लिए पूर्वी भारत के खेत मजदूरों पर निर्भर हैं।
- वायरस के डर से 25 मार्च को शुरू हुए तालाबंदी के बाद अधिकांश मजदूर अपने गाँव लौट आए।
- उन्हें मजदूरी में व्यवधान का सामना करना पड़ा।
- श्रम की भारी कमी भारत की सर्दियों की फसलों की कटाई को प्रभावित करेगी।
- किसानों को चिंता है कि अभूतपूर्व श्रम की कमी से यांत्रिक हार्वेस्टर को खेतों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा या और वह यहां तक कि हाथ की फसलों को भी खो देगा।
- ज्यादातर किसान केवल थोक बाजारों में उपज बेचते हैं।
- जो बदले में, अनाज की बड़ी मात्रा को उतारने, तौलने और पैक करने के लिए मजदूरों की सेनाओं पर निर्भर करता है।
- इससे किसानों को उपज के भुगतान में भी देरी हो सकती है।
- किसानों की अगली समस्या उपज को बाजार में ले जाने का संघर्ष है, जिसमें कुछ ट्रक बड़े मात्रा में ले जाने के लिए उपलब्ध हैं।

आगे को राह

- राज्य सरकार को तुरंत संग्रह केंद्र स्थापित करना और सुनिश्चित करना चाहिए।
- यह संग्रह केंद्र वन धन विकास केंद्र योजना के तहत कार्य कर सकते हैं।
- वन धन विकास केंद्र योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक वन उपज (MST) के संग्रह में शामिल आदिवासियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- इस योजना को एमएफपी–समृद्ध जिलों में एक स्थायी एमएफपी–आधारित आजीविका प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यूनिसेफ SHG केंद्रों को डिजिटल मल्टीमीडिया सामग्री, वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए वेबिनार, सोशल मीडिया अभियान और वान्या रेडियो के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
- ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के #iStandWithHumanity Initiative के साथ एक स्टैंड टू ट्राइबल फैमिली घटक को शामिल करने के लिए भी पहुँच बनाई है।
- यह आदिवासी समुदाय के अस्तित्व के लिए भोजन और राशन प्रदान करेगा।
- डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एसएचजी को वन धन सामाजिक सुरक्षा जागरूकता सह आजीविका केंद्रों के रूप में बढ़ावा देना।
- योजना में 3.6 लाख से अधिक आदिवासी एकत्रित होंगे।
- आदिवासी विकास सहकारी निगम ओडिशा (TDCCO) को भी कोविड–19 द्वारा बनाई गई स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए।
- TDCCO आदिवासी उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करता है।
- चूंकि कोविड–19 के कारण इटली और स्पेन को भारी मौत का सामना करना पड़ा था और उन्होंने असाधारण स्थिति को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ से आर्थिक उपायों की मांग की।
- गलती से रूढ़िवादी यूरोपीय संघ ने जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड जैसे इस विचार का विरोध किया, जिसे 'फ्रुगल फोर' के रूप में भी जाना जाता है।
- ये बांड यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को जारी किए जाने वाले संयुक्त ऋण बांड हैं।
- यह यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया ऋण होगा। धन यूरोपीय निवेश बैंक से आएगा।

TRIFED द्वारा वेबिनार

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (विष्व स्वास्थ्य संगठन) के सहयोग से कोविद –19 प्रतिक्रिया और बुनियादी निवारक उपायों पर मूल अभिविन्यास पर ट्राइफेड प्रशिक्षकों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के आभासी प्रशिक्षण के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय इकट्ठाकर्ता अपने कार्य को सुरक्षित रूप से कर सकें।
- सहयोग ने डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल संचार रणनीति विकसित करने और सामाजिक दूरी के महत्व को उजागर करने में मदद की।
- आदिवासियों और उनकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कुछ सक्रिय उपायों को शुरू करने की आवश्यकता है।
- यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह कई क्षेत्रों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) और एनटीएफपी के संग्रह और फसल के लिए पीक सीजन है।
- यह उन लोगों के लिए निर्वाह और नकद आय प्रदान करता है जो जंगलों में या उसके आसपास रहते हैं। वे अपने भोजन, फलों, दवाओं और अन्य उपभोग की वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और बिक्री के माध्यम से नकद आय भी प्रदान करते हैं।

वेबिनार के उद्देश्य –

- सामाजिक भेद और पालन किए जाने वाले कदमों के बारे में समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना।
- नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन (NTFP) के संग्रह के दौरान क्या करें और क्या न करें।
- व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, कैशलेस प्रथाओं को अपनाने आदि के लिए विचारोत्तेजक प्रथाएं प्रदान करना।
- 18,000 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंचने और सभी 27 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए।

कोरोना बॉंड

समाचार –

- कोरोना बांड कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितयों का सामना करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा जारी किए जाने के लिए इतालवी प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
- वित्तीय रूढ़िवादी यूरोपीय संघ ने इस विचार का विरोध किया जैसे जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड, जिसे 'फ्रुगल फोर' के रूप में भी जाना जाता है।
- ये बांड संयुक्त ऋण बांड हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को जारी किये जाते हैं। यह यूरोपीय संघ के सभी देशों द्वारा सामुहिक रूप से लिए गए ऋण है।
- यह धन यूरोपीय निवेश बैंक से आएगा।

यूएस फेड के साथ डॉलर स्वैप लाइन

समाचार –

- भारत, यूएसए के साथ एक डॉलर स्वैप लाइन को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है जो उसके बाहरी खाते के प्रभावी प्रबंधन में मदद करेगा।
- भारत को बड़े पैमाने पर बाजारों से धन के जारी बहिष्कार से उत्पन्न किसी भी चुनौती से उबरने की उम्मीद है।
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ एक स्वैप लाइन विदेशी मुद्रा बाजारों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है।
- यहां तक कि जैसे ही शेयर बाजारों में पहले के निचले स्तरों से एक उतार–चढ़ाव देखा गया है, यह अनुमान लगाया गया है कि कोविड–19 का आर्थिक प्रभाव लंबी अवधि तक रहेगा।
- अर्थव्यवस्था में शायद ही कोई वी–आकार की वसूली होगी।
- इसका मतलब है कि सरकार और RBI अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और बाहरी खाते पर अपने पहरे को कम नहीं कर सकते हैं।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार –

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्च 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 487.23 बिलियन डॉलर से लगभग 13 बिलियन डॉलर कम हो कर अप्रैल की 2020 में 474.66 बिलियन डॉलर हो गया।

- वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आयात में कमी के बावजूद, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है।
- यह कमी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के परिणामस्वरूप होने वाले निधियों के तेज बहिर्वाह के कारण है जो मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित हैवन्स की तलाश कर रहे हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 63.7 प्रतिशत विदेशी मुद्रा आस्तियाँ विदेशी प्रतिभूतियों में, मुख्यतः अमेरिकी खजाने में हैं।
- इस स्तर पर देश के भंडार किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

स्वैप सुविधा का कार्य

- स्वैप व्यवस्था में, यूएस फेड एक विदेशी केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जो उसी समय, फेड को, लेनदेन के समय बाजार विनिमय दर के आधार पर, अपनी मुद्रा में समान धनराशि प्रदान करता है।
- पार्टियां भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर अपनी दो मुद्राओं की इन मात्राओं को वापस स्वैप करने के लिए सहमत हैं।
- यह अगले दिन या तीन महीने बाद भी हो सकता है, पहले लेन–देन में उसी विनिमय दर का उपयोग करके।
- ये स्वैप ऑपरेशन कोई विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं उठाते हैं, क्योंकि लेनदेन की शर्तें पहले से निर्धारित होती हैं।
- विनिमय दर जोखिम की अनुपस्थिति इस तरह की सुविधा का प्रमुख लाभ है।

भारत की स्वैप लाइनें

- 2019 में, भारत ने जापान के साथ 75 बिलियन डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉलर भंडार है।
- यह सुविधा भारत को BoP के एक उपयुक्त स्तर को बनाए रखने के लिए किसी भी समय इन भंडारों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।
- RBI सार्क क्षेत्र को $2 बिलियन के समग्र कोष के भीतर एक स्वैप व्यवस्था प्रदान करता है।
- अन्य देश यूएसए डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में धनराशि निकाल सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका स्वैप लाइन्स

- संयुक्त राज्य अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के केंद्रीय बैंकों के साथ अस्थायी स्वैप व्यवस्था है।
- यूएसए में बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान और स्विस बैंक के साथ स्थायी स्वैप व्यवस्था है।
- भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं – जी –20 समूह के सभी भागों की वर्तमान में यूएसए के साथ मुद्रा स्वैप लाइन नहीं है।

गैर–यूरिया उर्वरकों के लिए सब्सिडी में कटौती

समाचार –

- केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए फास्फोरस, पोटाश, सल्फर जैसे गैर–यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी कम कर दी है।
- यह एक ऐसा कदम है, जो कोविड–19 के प्रकोप के बीच, सरकारी खजाने पर बोझ को घटाकर 22,186. 55 करोड़ रुपये कर देगा।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने NBS योजना के तहत अमोनियम फॉस्फेट नामक एक जटिल उर्वरक को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने 2010 में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) कार्यक्रम शुरू किया था।
- इस कार्यक्रम के तहत, एक वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि, यूरिया को छोड़कर, उनमें मौजूद पोषक तत्व के आधार पर, सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर प्रदान की जाती है।
- गैर–यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमतें जैसे डी–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), मुरीट ऑफ पोटाश (एमओपी) और एनपीके को डिक्रोल्ट किया जाता है और निर्माताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि केंद्र प्रत्येक वर्ष एक निश्चित सब्सिडी देता है।
- सरकार निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर यूरिया और 21 ग्रेड पीएंडके खाद उपलब्ध करा रही है।
- सरकार यूरिया के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करती है।
- उत्पादन लागत और एमआरपी के बीच का अंतर निर्माताओं को दिया जाता है।

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की बिक्री बढ़ी

समाचार –

- मार्च 2020 में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आरईसी) की बिक्री 79 प्रतिशत से बढ़कर 8.38 लाख यूनिट हो गई, जबकि मार्च 2019 में 4.68 लाख की आपूर्ति के कारण अच्छी आपूर्ति हुई।
- बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए आरईसी एक बाजार आधारित उपकरण है।
- एक आरईसी का विकास तब होता है जब एक मेगावाट बिजली एक अक्षय ऊर्जा के एक योग्य स्रोत से उत्पन्न होती है।
- आरईसी सौर, पवन और अन्य हरी ऊर्जा के लिए ट्रैकिंग तंत्र के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे पावर ग्रिड में प्रवाहित होते हैं।
- आरईसी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें ग्रीन टैग, ट्रेडेबल रिन्यूएबल सर्टिफिकेट (टीआरसी), रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट या रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट शामिल हैं।
- नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) के तहत डिस्कॉम जैसे खुले खरीदारों, आरईसी के एक निश्चित अनुपात को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं और कैपेसिटिव उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता होती है।
- वे अक्षय ऊर्जा उत्पादकों से आरईसी खरीद सकते हैं।
- 2011 में आरपीओ की स्थापना की गई थी।
- यह एक ऐसा जनादेश है जिसके लिए नवीकरणीय स्रोतों से अपनी बिजली का पूर्व निर्धारित अंश खरीदने के लिए बड़े बिजली खरीददारों की आवश्यकता होती है।
- उपयोगिताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात केंद्र द्वारा और साथ ही राज्य बिजली नियामक आयोगों द्वारा तय किया गया है।
- भारत में, RECs का कारोबार दो पावर एक्सचेंजों – इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL) पर किया जाता है।
- आरईसी की लागत बाजार की मांग से निर्धारित होती है।
- इसमें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्दिष्ट फ्लोर प्राइस (न्यूनतम मूल्य) और फॉरविबयरेंस प्राइस' (अधिकतम मूल्य) के बीच समाहित था।

समाज एवं स्वास्थ्य

विद्यादान 2.0

समाचार –

- अच्छी गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री की बढ़ती आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 पेश किया था।
- कार्यक्रम का उद्देश्य ई–शिक्षण सामग्री योगदान का स्वागत करना है।
- विद्यादान 2.0 ई–लर्निंग सामग्री के विकास और योगदान के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- कार्यक्रम स्कूल पाठ्यक्रम में समायोजित ई–लर्निंग सामग्री के साथ मजेदार बनाने और योगदान करने के लिए शिक्षाविदों और संगठनों को एकजुट करता है।
- योगदानकर्ता निर्धारित प्रारूप में व्याख्यात्मक वीडियो, एनिमेशन, शिक्षण वीडियो, पाठ योजना, मूल्यांकन और प्रश्न बैंकों के रूप में ई–लर्निंग सामग्री के वर्गीकरण में योगदान कर सकते हैं।
- सामग्री को शैक्षणिक विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा जांचा जाएगा।
- लाखों बच्चों को कभी भी और कहीं भी सीखने के लिए सहायता करने के लिए DIKSHA ऐप पर उपयोग के लिए सामग्री का निर्वहन किया जाएगा।

विश्व छगास रोग दिवस

समाचार –

- 14 अप्रैल 2020 को पहली बार विश्व छगास रोग दिवस मनाया गया।

छगास रोग के बारे में –

- इसे मूक रोग कहा जाता है क्योंकि यह धीरे–धीरे विकसित होता है।
- बहुत हद तक यह उन गरीब लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास राजनीतिक आवाज और उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल की कमी है।
- इस बीमारी का नाम डॉ. कार्लोस रिबेरो जस्टिनो छगास के नाम पर रखा गया था।
- जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का निदान किया।
- इसे एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (NTD) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- यह बिमारी दुनिया भर के विकासशील देशों में कम आय वाली आबादी को प्रभावित करती है।
- इसे अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस कहा जाता है।
- इस वेक्टर जनित बीमारी सबसे ज्यादा गरीब त्रस्त समुदायों की मृत्यू होती है, खासकर लैटिन अमेरिका में।
- एक परजीवी प्रोटोजोआ जिसे ट्रिपैनोसोमा क्रेजी कहा जाता है इस वेक्टर–जनित बीमारी का कारण बनता है।
- प्रोटोजोआ सामान्य रूप से ट्राईटोमाईन कीड़ों या किसींग कीड़े के मल और मूत्र द्वारा फैलता है जो मूलतः असेसिन बग के परिवार से संबंधित है।
- यह रोग दूषित भोजन, अंग प्रत्यारोपण, रक्त या रक्त उत्पाद आधान और नवजात शिशुओं को संक्रमित माताओं द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है।
- जागरूकता की कमी और लक्षणों की उपेक्षा के कारण विशेष रूप से गरीब घरों में, बहुत गंभीर लक्षण और यहां तक कि मृत्यु भी होती है।
- लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई, पेट या सीने में दर्द और लसीका ग्रंथि में सुजन शामिल है। ष्साइलेंट चागास रोगष के बारे में जानकारी शामिल है।
- 72 वें विश्व स्वास्थ्य सभा ने 24 मई 2019 को चगास रोग दिवस के पदनाम को मंजूरी दी।

स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट – 2020

समाचार –

- विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट – 2020, विष्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स तथा ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान, सरकारों तथा व्यापक भागीदारों की सहायता से विकसित किया गया है।
- रिपोर्ट विश्व स्तर पर नर्सिंग कार्यबल के मूल्य पर एक सम्मोहक उदाहरण प्रदान करती है।
- शिक्षा, नौकरियों और नेतृत्व में निवेश अभूतपूर्व परिणाम देता है।
- इसी समय, हमारी आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता का कोविड–19 प्रकोप और थोक जनसंख्या विस्थापन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।
- नर्स इन परिस्थितियों में से प्रत्येक में महत्वपूर्ण देखभाल देती हैं।
- 2020 में नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- इस रिपोर्ट के साक्ष्य का लाभ उठाने और जो 2030 के लिए एक एजेंडा बनाने का सही समय है।

मुख्य निष्कर्ष

1. विश्व स्तर पर, लगभग 10,000 लोगों में 36.9 नर्सें हैं, जिनके सभी क्षेत्रों में असमानता है।
2. अफ्रीकी क्षेत्र की तुलना में अमेरिका में लगभग 10 गुना अधिक नर्सें हैं।
3. 2030 तक, वैश्विक स्तर पर 5.7 मिलियन से अधिक नर्सों की कमी होगी।
4. निरपेक्ष संख्या में सबसे बड़ी कमी दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र में है।
5. अमेरिका और यूरोप में, समस्या अलग है, वे उम्रदराज नर्सिंग कर्मचारियों का सामना कर रहे हैं।
6. इसके अलावा, यूरोप में कई उच्च आय वाले देश, पूर्वी भूमध्य और अमेरिकी क्षेत्र 'विशेष रूप से' प्रवासी नर्सों पर निर्भर हैं।
7. जैसे कि नर्स एवं अन्य चिकित्साकर्मिया इस महामारी के समय अग्रिम पंक्ति के योद्धा है वे कुछ प्रमुख समस्याओं का सामना करते हैं जैसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), फेस मास्क, नेत्र सुरक्षात्मक गियर और दस्ताने इत्यादि की कमी। कुछ मेडिकल स्टाफ मनोवैज्ञानिक तनाव का भी सामना करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

- प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
- 2020 की थीम – नर्स और दाइयों की सहायता करें।
- इस वर्ष, इस दिन ने नर्सों और दाइयों के काम का जश्न मनाया गया तथा विश्व के नेताओं दुनिया को स्वस्थ रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
- विष्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साथी नर्सिंग और मिडवाइफरी कार्यबल को मजबूत करने के लिए सिफारिशों की एक श्रृंखला बनाएंगे।
- कोविड–19 की प्रतिक्रिया में नर्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबसे आगे हैं।
- वे उच्च गुणवत्ता, सम्मानजनक उपचार और देखभाल प्रदान करते हैं, डर और सवालों के समाधान के लिए अग्रणी सामुदायिक संवाद और नैदानिक अध्ययन के लिए डेटा एकत्र करते हैं।
- विष्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
- वर्षों से, यह मानसिक स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु देखभाल और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों को प्रकाश में लाया है।
- इसके विचार की कल्पना 1948 में प्रथम स्वास्थ्य सभा में की गई थी और 1950 यह लागू हुई।

विश्व मलेरिया दिवस

समाचार –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (fo'o LokLF; laxBu) द्वारा 25 अप्रैल 2020 को विश्व मलेरिया दिवस 2020 मनाया गया।
- इस वर्ष के लिए थीम 'जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी' है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा, विष्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय लेने वाले निकाय के 60 वें सत्र द्वारा 2007 में 25 अप्रैल को इस दिवस की स्थापना की गई थी।
- 'जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी' में जमीनी स्तर के अभियान में समाज के सभी सदस्य शामिल हैं।
- इनमें राजनीतिक नेता शामिल हैं जो सरकार के नीतिगत फैसलों और बजट को नियंत्रित करते हैं, अतिरिक्त संसाधन जुटाते है, निजी क्षेत्र की कंपनियां जो मलेरिया मुक्त कार्यबल से लाभान्वित होंगी तथा मलेरिया से प्रभावित समुदाय भी शामिल हैं, जिनके मलेरिया नियंत्रण हस्तक्षेपों की खरीद और स्वामित्व सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

मलेरिया

- यह बिमारी एक प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो आमतौर पर एक निश्चित प्रकार के मच्छर को संक्रमित करता है जो मनुष्यों पर पलता है।
- मादा एनोफिलीज मच्छर परजीवी स्पोरोजोइट्स को मानव शरीर की त्वचा में जमा करते हैं।
- यह रोके जाने योग्य बिमारी है जिसमें तीव्र ज्वर आता है।
- सबसे ज्यादा मलेरिया के मामले और मौतें उप–सहारा अफ्रीका में होती हैं।
- दक्षिण–पूर्व एशिया, पूर्वी भूमध्यसागरीय, पश्चिमी प्रशांत और अमेरिका के विष्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र भी जोखिम में हैं।

DRDO द्वारा विकसित COVSACK

समाचार –

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने COVSACK (कोविद–19 नमूना संग्रह कियोस्क) बनाया है।
- COVSACK ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), हैदराबाद में डॉक्टरों से परामर्श करके बनाया गया है।
- यह पीपीवी किट की आवश्यकता के बिना, सीओवीआईडी–19 संदिग्ध रोगियों से परीक्षण कराने में मदद करेगा।
- इसके उपयोग के दौरान, रोगी कियोस्क केबिन में चला जाता है और केबिन के बाहर से एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर नाक/मुँह के साथ नमूने इकट्ठा करता है।
- रोगी के केबिन से बाहर निकलने के बाद, 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक धुंध को लगभग 70 सेकंड तक स्प्रे करते हैं।
- इसके अलावा, केबिन को पानी और यूवी प्रकाश कीटाणुशोधन से प्रवाहित किया जाता है, जिससे यह प्रक्रिया संक्रमण से मुक्त हो जाती है।
- इससे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लगातार पीपीई परिवर्तन की आवश्यकता कम हो जाती है।
- सिस्टम अगले उपयोग के लिए 2 मिनट से भी कम समय में तैयार हो जाता है।
- COVSACK की लागत लगभग 1 लाख रुपये है।
- वर्तमान में, बाहर से एक चिकित्सा पेशेवर कीटाणुनाशक के साथ प्रणाली को फ्लश करता है। ऐसा करना उसे वायरस के संक्रमण के संदर्भ में एक कमजोर स्थिति में डाल देता है।
- इसे इसलिए बनाया गया है ताकि कियोस्क को मानव की मदद के बिना अपने आप कीटाणुरहित किया जा सके।

कोविड–19 महामारी के बीच शिक्षा

समाचार –

- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और इकॉवेशन के साथ, एक सामाजिक शिक्षण मंच, ने उन्नयन – मेरा मोबाइल, मेरा विद्यालय नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया था।
- इसके अंर्तगत कक्षा छठी से बारहवीं के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कक्षा–वार और विषय–वार अध्ययन सामग्री के ऑडियो प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के साथ एक स्लॉट बुक करने का इरादा है।
- इसकी वजह से 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को कोविड–19 लॉकडाउन के कारण नुकसान नहीं होगा।
- केंद्र अंग्रेजी और हिंदी में समर्पित टीवी और रेडियो चैनलों के माध्यम से दूरी मोड में कक्षाएं फिर से शुरू करने का इरादा रखता है।

CHAHAL ACADEMY

- बीईपीसी ने दीक्षा जैसे ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल के उपयोग के लिए भी छात्रों को प्रोत्साहित किया था।
- DIKSHA प्लेटफॉर्म पर NCERT की किताबें कक्षा 1 से 12 तक के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं।
- DIKSHA प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पाठ्यपुस्तकों को ऑडियो–विजुअल मीडिया के साथ एकीकृत किया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने भारत पडे ऑनलाइन अभियान और YUKTI वेब–पोर्टल भी शुरू किया था।
- इन्हें भारत में ऑनलाइन शिक्षा ढांचे में सुधार और अवलोकन के लिए लॉन्च किया गया था।
- केंद्र अगले शैक्षणिक वर्ष को वस्तुतः शुरू करने की योजना बना रहा है।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) को कक्षा–वार संरचित कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया है। ऐसा NCERT के साथ उनके सिलेबस का उपयोग करके किया जा रहा है।
- सामग्री NIOS या CBSE पाठ्यक्रम के बाद स्कूलों द्वारा उपयोग के लिए तैयार होगी।

चुनौतियां

- ई–लर्निंग में शिक्षकों, छात्रों और उनके माता–पिता को प्रौद्योगिकी तक पहुंच के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है।
- सभी छात्रों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं हैं।
- माता–पिता घर से काम करने के लिए कंप्यूटर/लैपटॉप का भी उपयोग करते हैं इससे बच्चों को इसका उपयोग करने का मौका नही मिल पाता।
- शिक्षक विचलित करने वाले ऐप्स के कारण स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले छात्रों के बारे में चिंतित हैं।
- शिक्षकों को भी तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और यदि शिक्षक सुसज्जित भी हैं, तो संस्थानों के लिए भी ऐसा निश्चित तौर पर नही कहा जा सकता है।
- लॉकडाउन ने उन लोगों के लिए इसे बदतर बना दिया, जिनके उपकरणों में तकनीकी समस्याएं हैं।
- यह माता–पिता अपने आप को ऑनलाइन प्रणाली में समायोजित करने में मुश्किल पा रहे हैं।
- घरेलू सहायकों की अनुपस्थिति के कारण जुड़ा घरेलू काम उनकी समस्या को बढ़ाता है।
- अधिकांश विषयों जैसे सौंदर्य, संस्कृति, फैशन डिजाइन और सिलाई, कार्यालय प्रबंधन, यात्रा और पर्यटन, वेब डिजाइन इत्यादि के लिए व्यावहारिक सीख की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें दूरस्थ मोड के माध्यम से सिखाना मुश्किल है।
- बिहार और अन्य राज्यों में, दूरस्थ शिक्षा ने सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल और शैक्षिक असमानताओं से उपजी चुनौतियों को भी उजागर किया है।

आगे की राह –

- शिक्षकों के पास एक संरचित योजना होनी चाहिए जो उन पर बोझ न बने और छात्रों को भी जोड़े रखें।
- सभी संस्थानों को एक बुनियादी ढांचा योजना तैयार करनी होगी, जिसका उपयोग इस तरह के संकट में किया जा सकता है।
- शिक्षकों को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि बच्चों को कैसा लगता है ताकि समझ विकसित की जा सके।

समाधान

समाचार –

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के इनोवेशन सेल ने एक मेगा ऑनलाइन चुनौती, SAMADHAN शुरू की है।
- यह फोर्ज और InnovatioCuris के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है।
- InnovatioCuris हेल्थकेयर विशेषज्ञता से संबंधित एक संगठन है।
- छात्रों मे नवाचार की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है।
- इस प्रतियोगिता में, भाग लेने वाले छात्र कोविड–19 के खिलाफ उपायों की खोज करेंगे और उनका विकास करेंगे।
- यह कोविड–19 तरह के महामारी के त्वरित समाधान के लिए सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों और अन्य सेवाओं के लिए उपलब्ध है।
- इस कार्यक्रम की सफलता तकनीकी और व्यावसायिक रूप से समाधान खोजने की क्षमता वाले प्रतिभागी प्रतियोगियों के विचारों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।
- प्रतियोगिता छात्रों और संकाय को नए प्रयोगों और खोजों के लिए प्रेरित करेगी जो एक मजबूत आधारभूत प्रयोग दे रही है।
- यह चुनौती नागरिकों में जागरूकता भी पैदा करेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने, संकटों को रोकने और आजीविका प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रेरित करेगी।

कोविड–19 कम्यूनिटी मोबिलीटी रिपोर्ट (सामुदायिक गतिशीलता रिपोट)

समाचार –

- 'कोविड–19 कम्यूनिटी मोबिलीटी रिपोर्ट' Google द्वारा जारी की गई है।
- रिपोर्ट का उद्देश्य कोविड–19 का मुकाबला करने के उद्देश्य से नीतियों में आए बदलावों का अध्ययन करना है।
- डेटा 5–सप्ताह की अवधि 3 जनवरी – 6 फरवरी, 2020 तथा भारत में लॉकडाउन अवधि के पहले कुछ दिनों पर आधारित है।
- यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर के लोग कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं।
- इस रिपोर्ट में 131 देशों को कवर किया गया है।
- इसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में दिन के विभिन्न समयों में, स्थानों की विभिन्न श्रेणियों में जैसे, खुदरा सामान खरीदने और मनोरंजन के स्थान, किराने का सामान लेने के स्थान, फार्मेसियों, पार्कों, पारगमन स्टेशनों, कार्यस्थल तथा आवास इत्यादि पर लोगो के आवागमन का अध्ययन किया गया।

भारत से संबंधित खोज

- रेस्तरां, कैफे, शॉपिंग सेंटर और मूवी थिएटर जैसी जगहों के लिए गतिशीलता की प्रवृत्ति में 77 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- किराने के बाजारों, खाद्य गोदामों, किसानों के बाजारों और फार्मेसियों में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- सार्वजनिक समुद्र तटों और उद्यानों जैसी जगहों के लिए 57 प्रतिशत की गिरावट, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर 71 प्रतिशत की गिरावट।
- कार्यस्थलों पर जाने में 47 प्रतिशत की गिरावट।
- लेकिन, निवास स्थानों में गतिशीलता के रुझान में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- ये रिपोर्ट कोविड–19 महामारी का प्रबंधन करने के तरीके के बारे में निर्णय लेने में सहायता करेगी।
- उदाहरण के लिए, सूचना अधिकारियों को आवश्यक यात्राओं में परिवर्तन को समझने में मदद कर सकती है।
- इसके द्वारा व्यवसाय के घंटे के बारे में सुझाव दिए जा सकते हैं या वितरण सेवा के प्रस्तावों की सूचना दी जा सकती हैं।

अन्य देशों में आवागमन

- 16 फरवरी से 29 मार्च तक खुदरा और मनोरंजक स्थानों, ट्रेन और बस स्टेशनों, किराने की दुकानों और कार्यस्थलों की पांच–सप्ताह की अवधि (जनवरी 3 – फरवरी 6) के साथ यातायात की तुलना।
- इटली और स्पेन, दो सबसे कठिन देश हैं, दोनों ने रेस्तरां और फिल्म थिएटर जैसे खुदरा और मनोरंजन स्थानों की यात्राओं में 94 प्रतिशत की गिरावट देखी।
- यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और फिलीपींस में 80 प्रतिशत से अधिक की गिरावट थी।
- जापान और स्वीडन में, खुदरा और मनोरंजन स्थलों की यात्रा में लगभग एक चौथाई की गिरावट आई।
- जबकि दक्षिण कोरिया में, गिरावट सिर्फ 19 प्रतिशत थी, जिसमें आक्रामक परीक्षण और संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक बड़ा प्रकोप हुआ है।
- चीन और ईरान के लिए कोई रिपोर्ट नहीं थी, जहां Google सेवाएं अवरुद्ध हैं।

आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID 2020)

- रिपोर्ट को नॉर्दर्न रिफ्यूजी काउंसिल के एक भाग आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) द्वारा जारी किया गया है।
- 2019 में भारत में लगभग पाँच मिलियन लोग विस्थापित हुए, जो दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
- दक्षिण–पश्चिम मानसून के कारण 2.6 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा।
- 2019 भारत में 1901 के बाद से सातवां सबसे गर्म वर्ष था। 25 वर्षों में मानसून ने इस वर्ष यहाँ सर्वाधिक वर्षा की है।
- आठ उष्णकटिबंधीय तूफानों ने देश के विभिन्न भागों में विनाश मचाया। इनमें महा और बुलबुल शामिल हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन के अलावा, 19,000 से अधिक संघर्षों और हिंसा ने भी इस घटना को प्रेरित किया।
- वर्ष की दूसरी छमाही में अशांति और सांप्रदायिक हिंसा ने विस्थापन शुरू कर दिया।
- उदाहरण के लिए, राजनीतिक और चुनावी हिंसा, विशेष रूप से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जिसमें 7600 से अधिक लोग विस्थापित हुए।

सोडियम हाइपोक्लोराइट

समाचार –

- कीटाणुनाशक सुरंग में सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग लोगों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, भले ही इसकी सांद्रता में थोड़ा बदलाव हो।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले ही एक सलाह जारी की थी जिसमें कहा गया था कि सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे कीटाणुनाशक का छिड़काव हानिकारक है।

विवरण –

- कई स्थानों पर निस्संक्रामक सुरंगें स्थापित की गई हैं, और सुरंग में सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल का उपयोग किया जा रहा है।
- सुरंगों, जिसके माध्यम से लोग इस समाधान की धुंध के दौरान चलते हैं, को किसी भी वायरस को साफ करने के लिए उन पर छिड़काव किया जाता है।
- सोडियम हाइपोक्लोराइट एक क्लोरीन–आधारित कीटाणुनाशक है, जिसका उपयोग निर्जीव वस्तुओं पर किया जाता है।
- इसकी 0.5 प्रतिशत से अधिक सांद्रता का उपयोग घाव की सफाई के लिए नहीं किया जाता है।
- सोडियम हाइपोक्लोराइट एक पीले रंग का तरल रसायन है जिसका उपयोग ब्लीच के रूप में किया जाता है।
- इस रसायन का उपयोग गंदे पानी को शुद्ध करने, और दाग हटाने के लिए किया जाता है।
- एक सामान्य ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सफाई और कीटाणुनाशक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- यह क्लोरीन छोड़ता है, जो कीटाणुनाशक है।
- घोल में रसायन की सांद्रता उस उद्देश्य के अनुसार भिन्न होती है, जिस उद्देश्य के लिए यह उपयोग की जाती है।
- बड़ी मात्रा में क्लोरीन हानिकारक हो सकती है। सामान्य घरेलू ब्लीच 2–10 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल है।
- बहुत कम 0.25–0.5 प्रतिशत पर, इस रसायन का उपयोग त्वचा के घावों जैसे कि कट या खरोंच के इलाज के लिए किया जाता है।
- हैंडवॉश के लिए भी कमजोर समाधान (0.05 प्रतिशत) का उपयोग किया जाता है।
- 1 प्रतिशत घोल से त्वचा को नुकसान होता है।
- यदि यह शरीर के अंदर जाता है, तो यह फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
- सोडियम हाइपोक्लोराइट संक्षारक होता है, और इसका अर्थ यह है कि इसका उपयोग मोटे तौर पर कठोर सतहों को साफ करने के लिए होता है।
- इसे मनुष्यों पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं सुझाया जाता है, ना ही स्प्रे या शॉवर के रूप में।
- इसका 0.05 प्रतिशत घोल आँखों के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है।

चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक नक्शा

समाचार –

- NASA, संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS), और चंद्र ग्रह संस्थान ने चंद्रमा की सतह का एक विस्तृत रंगीन नक्शा विकसित किया है।
- वैज्ञानिकों ने 2013 में जारी, निकट, मध्य सुदूर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर के 6 मानचित्रों के आधार पर डिजिटल नवीकरण बनाया है।
- मानचित्र में संपूर्ण चंद्र सतह पर 43 भूगर्भिक इकाइयां शामिल हैं, जो क्रेटर्स, बेसिन, टेरा, मैदानी और ज्वालामुखी इकाइयों की सामग्री के आधार पर समूहों में बाँटी गई हैं।
- चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक खाके के रूप में काम करेगा।
- यह शिक्षकों और चंद्र भूविज्ञान में रुचि रखने वाले आम लोगों के लिए अनुसंधान और विश्लेषण के स्रोत के रूप में भी काम करेगा।
- नक्शा 'सहज, विश्व स्तर पर सुसंगत, 1: 5,000,000 – स्केल का भूगर्भिक मानचित्र' है।
- नक्शे में चंद्रमा के सतह की कई विशेषताएं क्रेटर रिम क्रैस्ट, बरिड क्रेटर रिम क्रैस्ट, फिशर, ग्रैबन्स, स्कार्प्स, मेयर रिंकल रिज्स, फाल्ट्स, ट्रॉ, रेल्स, और लाइनमेंट्स इत्यादि शामिल है।

विश्व होम्योपैथी दिवस

समाचार –

- विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है।
- होम्योपैथी पद्धति के जनक डॉ. सैमुअल हैनीमैन के जन्म का सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
- उन्होंने होम्योपैथी द्वारा स्वस्थ करने का तरीका खोजा।
- 2 जुलाई, 1843 को उनका निधन हो गया।

- 2020 का विषय 'सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के दायरे को बढ़ाना' है।

होम्योपैथी

- 'सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरान्टुर' के सिद्धांत से ठीक होने का तरीका जैसे को तैसा ठीक करता है।
- यह विधि डॉ. हैनिमैन द्वारा लाई गई थी।
- होम्योपैथी भारत में सबसे लोकप्रिय चिकित्सा प्रणालियों में से एक है।
- यह आयुष चिकित्सा प्रणालियों – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में से एक है।
- विश्व होम्योपैथी दिवस 2020 के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन सह वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया।
- यह राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, CCRH, CCH और HPL के सहयोग से बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, कोलकाता में आयोजित किया गया था।
- होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली भारत में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के तहत एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है।
- इसे दवाओं की राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

TriboE मास्क

समाचार –

- सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साईंसेंस (CeNS), बेंगलुरु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त संस्थान, फेस मास्क बनाने के लिए एक नया तरीका लेकर आया है।
- इस नई विधि को TriboE मास्क कहा जाता है।
- यह मास्क बिना किसी बाहरी शक्ति के संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए विद्युत आवेश धारण कर सकता है।
- मुखौटा तीन–स्तरीय होता है, बाहर की तरफ पॉलीप्रोपाइलीन परतों के बीच नायलॉन या रेशम के कपड़े की एक परत होती है, और अंदर की परत में आमतौर पर बिना बुने किराने की थैलियों का उपयोग होता है।
- जब परतों को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ा जाता है, तो स्थैतिक बिजली उत्पन्न होती है। बाहरी परतें नकारात्मक आवेशों का विकास करती हैं, जबकि नायलॉन/रेशम सकारात्मक आवेश धारण करती हैं।
- यह संक्रमण के संभावित संचरण को प्रतिबंधित करता है।
- यह संक्रामक संस्थाओं को पार करने के खिलाफ दोहरी विद्युत दीवार के संरक्षण के रूप में कार्य करता है।
- लेकिन यह स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों के लिए अनुशंसित नहीं है।

SunRISE मिशन

समाचार –

- नासा ने विशाल सौर कण तूफानों का अध्ययन करने के लिए एक नए मिशन का चयन किया है।
- सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट (SunRISE) में देखा जाएगा कि कैसे सूर्य अंतरिक्ष में सौर कण तूफानों का निर्माण और निर्वहन करता है।
- यह मिशन सौर प्रणाली की अधिक समझ में सहायता करेगा। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अंतरिक्ष यात्रियों की मंगल या चंद्रमा की यात्रा के दौरान सुरक्षा करने संबंधी उपाय करने में मदद करेगा।
- SunRISE में 6 क्यूबसैट शामिल हैं जो एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में एक साथ काम करेंगे।
- प्रत्येक क्यूबसैट सौर ऊर्जा पर चलेगा और एक टोस्टर ओवन के आकार का होगा।
- ये सौर गतिविधि से कम आवृत्ति उत्सर्जन की रेडियो छवियों का निरीक्षण करेंगे।
- क्यूबसैट सूर्य पर एक सौर कण तूफान के मूल स्थान का पता लगाने के लिए 3 डी मानचित्र बनाएंगे।
- तूफान के विकास की पूरी प्रक्रिया का अंतरिक्ष में बाहर की ओर बढ़ने पर भी अध्ययन किया जाएगा।

प्रचुर मात्रा में लिथियम से युक्त लाल दानव तारा

समाचार –

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, ने प्रचुर मात्रा में लिथियम से युक्त लाल दानव सितारों की खोज की है, जिसमें देखा गया है कि लिथियम सितारों में उत्पादित हो रहा है और इंटरस्टेलर माध्यम में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- उन्होंने इन केंद्र में हिलीयम जलने वाले तारों के साथ लिथीयम वृद्धि को भी जोड़ा है, जिसे लाल दानवों का झुंड भी कहा जाता है, जिससे लाल विशाल सितारों के विकास में नई शुरुआत होती है।

- लिथियम (ली), हाइड्रोजन और हीलियम (हे) के अलावा तीन प्रारंभिक तत्वों में से एक है, जिन्होंने बड़े धमाके वाले न्यूक्लियोसिंथेसिस (बीबीएन) के निर्माण में भूमिका निभाई है।
- यह एक महत्वपूर्ण खोज है जिससे कई प्रस्तावित सिद्धांतो जैसे कि ग्रहों के निगल जाने या ऐसे लाल दानव तारे जिसके केंद्र में में हीलियम नहीं जल रहा है के दौरान होने वाले नाभिकिय संश्लेषण को समाप्त करने मदद करेगी ।

मधुबन गाजर

समाचार –

- मधुबन गाजर, गाजर की एक बायोफोर्टिफाईड किस्म है, जिसे जूनागढ़ (गुजरात) में 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगाया जा रहा है।
- इसकी औसत उपज, जो 40–50 टन/हेक्टेयर (टी/हेक्टेयर) है, स्थानीय किसानों की आय का मुख्य स्रोत बन गई है।
- इसका उपयोग विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे गाजर चिप्स, जूस और अचार के लिए किया जाता है।
- यह उच्च बी–कैरोटीन सामग्री (विटामिन ए का स्रोत) और लौह की प्रचुरता के साथ चयन विधि के माध्यम से निर्मित गाजर की एक अत्यधिक पौष्टिक किस्म है।
- इसे जूनागढ़ के किसान वैज्ञानिक वल्लभभाई वासराभाई मारवानिया द्वारा विकसित किया गया था।
- उन्हें इस असाधारण काम के लिए फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन (एफओआईएन) – 2017 और 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
- मधुबन गाजर का परीक्षण 2016–17 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) द्वारा किया गया था।
- यह पाया गया कि इस गाजर की किस्म में जड़ की अधिक पैदावार (74.2 टन/हेक्टेयर) और बायोमास (275 ग्राम प्रति पौधा) होती है।
- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की खेती की जा रही है।

फूड फोर्टिफिकेशन और बायोफोर्टिफिकेशन

- फूड फोर्टीफिकेशन भोजन में विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने का अभ्यास है।
- फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार और कम जोखिम में सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ देने के लिए किया जाता है।
- बायोफोर्टिफिकेशन में, वैज्ञानिक तरीकों तथा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि फसलों की पौष्टिकत्ता में सुधार किया जाता है।
- बायोफोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन से भिन्न होता है क्योंकि बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य फसलों के प्रसंस्करण के दौरान मानवीय साधनों के बजाय पौधों की वृद्धि के दौरान फसलों में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना है।
- बायोफोर्टिफिकेशन द्वारा पोषण की मात्रा में वृद्धि मार्च 2018 में शुरू किए गए भारत के राष्ट्रीय पोषण मिशन का समर्थन करती है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन को बाद में पोषण अभियान नाम दिया गया था।
- सूक्ष्म पोषक कुपोषण का सामना करने वाले देशों के लिए बायोफोर्टिफिकेशन सर्वाधिक प्रभावी हस्तक्षेप माना जाता है।
- यह उन ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुँचता है जिनकी औद्योगिक रूप से दृढ़ खाद्य पदार्थों, पूरक हस्तक्षेपों और विविध आहारों तक सीमित पहुँच है।
- इसमें पसंदीदा एग्रोनोमिक, गुणवत्ता और बाजार लक्षणों के साथ बढ़े हुए सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं तथा इसलिए बायोफोर्टिफाइड किस्मे किसानों द्वारा बोई जाने वाली सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक लोकप्रिय होती हैं।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय पोषण रणनीति के अंर्तगत 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है।

कोविड–19 का सामुहिक परीक्षण

समाचार –

- ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) ने उत्तर प्रदेश को कोविड–19 महामारी का सामुहिक परीक्षण शुरू करने की अनुमति प्रदान की।
- इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सामुहिक परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- सामुहिक परीक्षण का प्रयोग कुल परीक्षणों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- सामुहिक परीक्षण में, यदि किसी समुह के कोविड–19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक हैं, तो यह दर्शाता है कि सभी नमूने नकारात्मक परीक्षण करते हैं।

- लेकिन, यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं हैं, तो समुह के प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा।
- सामुहिक परीक्षण से कोविड–9 महामारी के परीक्षणों में विस्तार होगा तथा इससे परीक्षण प्रक्रिया में तेजी आएगी।

रेमेड्सविर की प्रभावशीलता

समाचार –

- ICMR के अनुसार, कोविड–19 महामारी को रोकने में एंटीवायरल दवा रेमेड्सविर अत्यधिक प्रभावी है।
- रेमेड्सविर की प्रभावकारिता पर शोध विष्व स्वास्थ्य संगठन के 'सॉलिडैरिटी ट्रायल' का एक हिस्सा है, न कि नैदानिक परीक्षण का।
- अध्ययनों के अनुसार, रेमेड्सविर के उपचार में आने वाले 68 प्रतिशत रोगियों को दवा लेने के बाद वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता नहीं थी।
- fo'o LokLF; laxBu ने 4 मेगा ट्रायल शुरू किए हैं।
- दवा की दक्षता पर और विकास विष्व स्वास्थ्य संगठन के मेगा परीक्षणों से सीखा जाना है।
- इससे पहले, दवा का इस्तेमाल इबोला वायरस के खिलाफ किया गया था।

हाइड्रोजन ईंधन सेल

समाचार –

- एनटीपीसी ने दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करने के लिए वैश्विक अभिव्यक्ति की रुचि (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट – ईओआई) को आमंत्रित किया है।
- एनटीपीसी ने लेह के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों की समान संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किया है।
- हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहनों की खरीद का कदम भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है
- इसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा।

विवरण –

- एक ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो ईंधन (अक्सर हाइड्रोजन) की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है।
- ईंधन कोशिकाओं को रासायनिक प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन (आमतौर पर हवा से) के एक निरंतर स्रोत की आवश्यकता के मामले में अधिकांश बैटरी से अलग होता है जबकि एक बैटरी (फ्लो बैटरी को छोड़कर) में, रासायनिक ऊर्जा धातुओं और उनके आयनों या ऑक्साइड से आती है जो पहले से बैटरी में मौजूद हैं।
- ईंधन कोशिकाएं तब तक लगातार बिजली का उत्पादन कर सकती हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है।

असमान द्रव्यमान वाले दो ब्लैक होल का पहला विलय

समाचार –

- LIGO साईंटिफिक कॉलेबरेशन पर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्ज़रवेटरीज़ ने जब से काम करना शुरू किया है वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार दो असमान–द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय का पता लगाया है।
- GW190412 नाम की घटना का लगभग एक साल पहले पता चला था तथा यह इन शक्तिशाली डिटेक्टरों द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेतों के `ज आरएसटी का पता लगाने के लिए स्थापित किए जाने के लगभग 5 साल बाद पता चला है।
- हिंसक विलय से आने वाले सिग्नल के विश्लेषण से पता चला कि इसमें असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल शामिल थे।
- जिनमें से एक सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 30 गुना था और दूसरा जिसका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान का लगभग 8 गुना था।
- वास्तविक विलय 2.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हुआ है।
- ज्ञात सिग्नल की तरंग में विशेष रूप से अतिरिक्त विशेषताएं हैं, यह समान आकार के ब्लैक होल के विलय की तुलना में दो असमान आकार के ब्लैक होल के विलय से मेल खाती है।
- जबकि ब्लैक होल का द्रव्यमान स्पेस–टाईम को मोड़ देता है, इस असंज्ञेय वस्तु का स्पिन या कोणीय गति आस–पास के स्पेस–टाईम में भँवर पैदा करता है।
- इसलिए यह दोनों गुण अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।

समान द्रव्यमान के बाईनरी ब्लैक होल तथा असमान द्रव्यमान के बाईनरी ब्लैक होल में क्या मुख्य अंतर है

- गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रमुख उत्सर्जन बाईनरी ब्लैक होल की कक्षीय आवृत्ति के दोगुने के बराबर होता है. लेकिन इस मामले में, हम, पाते हैं कि यह कक्षीय आवृत्ति का तीन गुना के बराबर आवृत्ति उत्सर्जन करता है।
- यह उत्सर्जन नगण्य होता है जब बायनेरिज़ में समान द्रव्यमान होता है और जब कक्षा आमने–सामने होती है।
- द्रव्यमानों में विषमता ने उच्चतर हार्मोनिक घटक को बेहतर ढंग से सुनने लायक बनाया, जिससे इसकी अस्पष्ट पहचान हुई।
- इसके अलावा, असमान ब्लैक होल के विलय के मामले में, अधिक बड़े ब्लैक होल की स्पिन को सिग्नल तरंग में अतिरिक्तता से भी निर्धारित किया जा सकता है।
- भारी ब्लैक होल की स्पिन बाइनरी की गतिशीलता में अधिक प्रमुख भूमिका निभाती है।
- इसलिए, यह तरंग पर एक मजबूत छाप छोड़ता है, जिससे इसे मापना आसान हो जाता है।

करमी–बॉट रोबोट

समाचार –

- करमी–बॉट, एक रोबोट जो सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, एर्नाकुलम में कोविड–19 रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड में तैनात है।
- यह रोबोट जल्द ही देश भर के अस्पतालों और यहां तक कि विदेशों में अपना रास्ता बना सकता है।
- ASIMOV रोबोटिक्स के लिए, यहां के मेकर विलेज में स्थित एक स्टार्ट–अप, इसके व्यावसायिक उत्पादन को शुरू करने की कगार पर है।
- ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया रोबोट, अभिनेता मोहनलाल द्वारा संचालित विश्वशांति फाउंडेशन के सहयोग से साकार हुआ है।
- रोबोट को एर्नाकुलम कलेक्टर को सौंप दिया गया है।
- रोबोट भोजन और दवाओं के वितरण और रोगियों द्वारा डॉक्टरों के बीच वीडियो कॉल शुरू करने के लिए छोड़े गए कचरे के संग्रह से लेकर अन्य कई गतिविधियों तक बहुत कुछ करता है।
- इसके अलावा, यह पराबैंगनी–आधारित कीटाणुशोधन प्रदर्शन कर सकता है और लक्ष्य पर डिटर्जेंट भी स्प्रे कर सकता है।
- इसका मुख्य लक्ष्य रोगियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत को सीमित करना है।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के उपयोग को कम करना है, जो वर्तमान में देश में दुर्लभ हैं।
- ASIMOV रोबोटिक्स स्टार्ट–अप हेल्थकेयर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा वे विशेषतौर पर गहन देखभाल इकाइयों में तैनाती के लिए चिकित्सीय अनुप्रयोगों के साथ तैयार किए गए एक रोबोट लाने की योजना बना रहे है।
- मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद एक महीने के भीतर करमी–बॉट विकसित किया गया था।
- 25 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम रोबोट दो घंटे तक चलने वाले फुल चार्ज के बाद 6–8 घंटे तक काम कर सकता है।
- एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब स्पेयर पार्ट्स मिलने लगेंगे तब इसे अतिरिक्त फीचर्स के साथ लोड किया जाएगा, जैसे कॉन्टैक्ट–लेस टेम्परेचर चेकिंग और ऑटोमैटिक चार्जर डॉकिंग इत्यादि।

'कोविड इंडिया सेवा' का शुभारंभ

समाचार –

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, कोविड इंडिया सेवा लॉन्च किया।
- कार्यक्रम कोविड–19 संबंधित प्रश्नों को वास्तविक समय में समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से है।
- लोग प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम से तेजी से जवाब पाने के लिए कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य – विशेष रूप से संकट की स्थितियों में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई–गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम करना।
- इस मंच की मदद से, प्रशिक्षित विशेषज्ञ आधिकारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी को तेजी से बड़े पैमाने पर साझा करने में सक्षम होंगे।
- जो नागरिकों के साथ संचार के लिए एक सीधा चैनल बनाने में मदद करेगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर की वेबसाइटों पर यातायात में वृद्धि

समाचार –

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की वेबसाइटों पर यातायात में काफी वृद्धि हुई थी।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि नागरिकों ने कोविड–19 के बारे में वास्तविक जानकारी की तलाश करनी चाही।
- एनआईसी के विभिन्न राज्य केंद्र राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि राज्य और जिला प्रशासन को महामारी से निपटने के लिए ट्रैकिंग और प्रबंधन पोर्टल विकसित किया जा सके।
- यह केरल और मेघालय में पहले से लॉन्च किए गए कार्यक्रमों के समान है।
- उदाहरण के लिए, कोविद–19 जागृति – पोर्टल केरल में लॉन्च किया गया था।
- यह जनता के लिए कोविद–19 से संबंधित आपातकालीन सेवाओं और सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए एक मंच है और सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी उपायों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- एनआईसी ने वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) की कुछ चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला जैसे –
  a) **कॉन्फिगरेशन चुनौतियां** – वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) एक्सेस को कॉन्फिगर करना – सरकारी कर्मचारियों को अपने घरों से काम करने में सक्षम बनाना – बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तीन या चार दिनों की अवधि में। एक वीपीएन ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है। यह सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्शन से एक निजी नेटवर्क बनाकर ऐसा कर सकता है।
  b) **सीमित जनशक्ति** – एनआईसी में अधिकांश सदस्यघर से काम कर रहे थे, विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन को क्रियान्वित करना एक सीमित शक्ति के साथ कठिन था।
  c) **लॉजिस्टिक की कमी** – प्रत्येक स्त्रोत के लिए एक लैपटॉप या होम डेस्कटॉप की उपलब्धता एक और चुनौती थी।
- आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर बढ़े हुए ट्रैफिक के अलावा, एनआईसी की वीडियोकांफ्रेंसिंग सेवा का भी व्यापक रूप से सामाजिक दूरियों के मानदंडों के कारण उपयोग किया जा रहा है।
- वीडियोकांफ्रेंसिंग सेवा केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाती है।

अटल टिंकरिंग लैब्स में CollabCAD

समाचार –

- अटल इनोवेशन मिशन, NITI Aayog और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने संयुक्त रूप से सहयोगी नेटवर्क CollabCAD लॉन्च किया है।
- भारत में ATL के छात्रों को एक बेहतरीन मंच देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स (या ATL स्कूलों) में CollabCAD लॉन्च किया गया है।
- CollabCAD को बनाने के पीछे रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3 डी डिजाइन विकसित करने और संशोधित करने का लक्ष्य है।
- यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा विकसित करने में भी सक्षम करेगा।
- यह सॉफ्टवेयर स्टोरेज और विजुअलाइजेशन के लिए समान डिजाइन डेटा को समवर्ती रूप से एक्सेस करेगा।
- यह डेस्कटॉप सीएडी (कंप्यूटर–एडेड डिजाइन) सॉफ्टवेयर सिस्टम 2 डी ड्राफ्ट और 3 डी प्रिंटिंग का विवरण देने से लेकर इंजीनियरिंग के संपूर्ण समाधान देता है।
- यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (परमाणु ऊर्जा विभाग), और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (अंतरिक्ष विभाग, इसरो) की एक पहल है।

अटल टिंकरिंग लैब्स

- भारत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने ATL की स्थापना की है।
- एटीएल की स्थापना नए कार्यक्रमों को विकसित करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
- इसका उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है। और डिजाइन मानसिकता, कम्प्यूटेशनल सोच, अनुकूलन सीखने, शारीरिक कंप्यूटिंग इत्यादि जैसे कौशल विकसित करना।

- AIM विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करता है, जागरूकता पैदा करता है और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख के लिए एकछत्र संरचना बनाता है।
- ATL एक कार्य स्थान है जहाँ बच्चे अपने विचारों को do&it&yourself स्वयं अपने तरिके से करके देखने का माध्यम प्रदान करता हैं।
- एटीएल का उद्देश्य एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) की अवधारणाओं को समझने के लिए उपकरणों के साथ काम करने का मौका देना है।
- AIM अनुदान–सहायता भी देता है जिसमें एक बार की स्थापना लागत 10 लाख रूपये और प्रत्येक एटीएल को अधिकतम 5 वर्षों के लिए 10 लाख रुपये परिचालन खर्च शामिल है।
- वर्तमान स्थिति (कोविद–19) में, एटीएल कार्यक्रम ने 'होम से टिंकर' अभियान लॉन्च किया है।
- 'होम से टिंकर' अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश भर के बच्चों को उपयोगी आसानी से सीखने के लिए ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच हो, ताकि वे खुब फल–फूल सकें।
- AIM ने गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल को 'होम से टिंकर' अभियान के हिस्से के रूप में भी प्रस्तावित किया है।
- यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा युवा दिमाग अपने खेल को विकसित करना सीख सकते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं।
- यह प्लेटफॉर्म छात्रों को 'गेम प्लेयर' से 'गेम मेकर' बनाने के लिए परिकल्पित करता है।

सेट टॉप बॉक्सेस (एसटीबी)

समाचार –

- हाल ही में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सिफारिश की है कि देश में सभी सेट टॉप बॉक्स (STB) को इंटरऑपरेबल बनाया जाना चाहिए।
- इसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न डीटीएच (डायरेक्ट–टू–होम) या केबल टीवी प्रदाताओं में एक ही एसटीबी का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

अंतर की कमी के कारण मुद्दे

- यह ग्राहक को उसे / उसके सेवा प्रदाता को बदलने की स्वतंत्रता से वंचित करता है।
- तकनीकी नवाचार और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक बाधा बनाता है।
- संपूर्ण डीटीबी क्षेत्र की वृद्धि में बाधा बनता है।

आगे को राह –

- यूनिवर्सल एसटीबी में तकनीकी और वाणिज्यिक बाधाएँ हैं, इसलिए इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म–विशिष्ट होनी चाहिए।
- केबल टीवी सेगमेंट के भीतर इंटरऑपरेबल एसटीबी और इसी तरह डीटीएच सेगमेंट के भीतर विकसित किया जाना चाहिए।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य बनाने के लिए लाइसेंस और पंजीकरण शर्तों में आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।
- डीटीएच और केबल होम सेगमेंट दोनों के लिए संशोधित एसटीबी मानकों को लागू करने के लिए एक समन्वय समिति गठित करने की भी सिफारिश की गई है।
- समिति भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा डिजिटल टीवी मानकों की स्थापना के लिए निरंतर निगरानी रख सकती है।

सत्यम कार्यक्रम

समाचार –

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने योग और ध्यान (SATYAM) कार्यक्रम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है।
- कार्यक्रम के तहत इसने कोविड–19 और इसी प्रकार के वायरस से लड़ने में योग और ध्यान के उचित हस्तक्षेप का अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
- डीएसटी प्रस्ताव कवर पर अवधारणा नोट प्रस्तुत करने के लिए एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वैज्ञानिकों, चिकित्सकों तथा योग और ध्यान के अनुभवी चिकित्सकों को प्रोत्साहित कर रहा है।
  क) प्रस्तावित कार्यों के उद्देश्य।
  ख) मौजूदा साहित्य।
  ग) क्रियाविधि विज्ञान।
  घ) अपेक्षित परिणाम।
  च) बजट की आवश्यकता।
  छ) वैज्ञानिक पत्रिका डेटाबेस में शामिल नवीनतम प्रकाशनों के साथ प्रमुख अन्वेषक के विस्तृत जैव–डेटा के साथ मेजबान संस्थानों का विवरण।

योग और ध्यान कार्यक्रम का विज्ञान और प्रौद्योगिकी –

- इसकी अवधारणा संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल (CSRI) के तहत DST द्वारा 2015 में की गई थी।
- इसे स्वस्थ लोगों में और साथ ही विकारों के रोगियों में संज्ञानात्मक कार्य पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर योग और ध्यान के प्रभावों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।

विषय–वस्तु

- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर योग और ध्यान के प्रभाव पर जांच।
- शरीर, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क पर योग और ध्यान के प्रभाव पर पड़ने वाली जांच बुनियादी प्रक्रियाओं और तंत्रों के संदर्भ में।

संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल

- डीएसटी ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2008 में इसे अत्यधिक केंद्रित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया।
- DSRI संज्ञानात्मक विकारों से संबंधित चुनौतियों के बेहतर समाधान के लिए वैज्ञानिक समुदाय को एक मंच प्रदान करता है।
- यह विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपकरणों और बैटरी, प्रारंभिक निदान और बेहतर चिकित्सा, अंतःक्षेप तकनीकों और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर वैज्ञानिक समुदाय को भी सुविधा प्रदान करता है।

हाईड्रोक्सीक्लोराक्वीन

समाचार –

- भारत ने मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) के निर्यात पर अपने पहले के प्रतिबंध को रद्द कर दिया।
- दवा का उपयोग कोविद–19 के इलाज के लिए किया जा रहा है और यह महामारी के मानवीय पहलुओं को देखते हुए किया गया है।
- भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों को पैरासीटामोल और एचसीक्यू को उचित मात्रा में लाइसेंस देने का फैसला किया है जो इसकी क्षमताओं पर निर्भर हैं।
- यह कुछ राष्ट्रों को इन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी करेगा जो विशेष रूप से महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
- सरकार पहले से मौजूद आदेशों को पूरा करेगी, मुख्य रूप से अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों को, क्योंकि उन्होंने अपने आदेशों पर अग्रिम भुगतान किया है।
- दवा के लिए स्टॉक की स्थिति और घरेलू मांग के आधार पर आदेश पूरे किए जाएंगे, जिनकी निरंतर निगरानी की जाएगी।
- सरकार ने कहा कि वर्तमान में उसके पास दवा का पर्याप्त स्टॉक है।

दवा के बारे में –

- यह एक मौखिक दवा है जिसका उपयोग मलेरिया और कुछ स्व–प्रतिरक्षित बीमारियों जैसे कि संधिशोथ के उपचार में किया जाता है।
- मलेरिया मादा एनोफिलिस के मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है और परजीवी के माध्यम से फैलती है।
- हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि अकेले एचसीक्यू दवा या एजिथ्रोमाइसिन के संयोजन से सीओवीआईडी–19 वायरस को कम किया जा सकता है।
- इसके अलावा, अध्ययन से पता चलता है कि अनुमोदित खुराक पर हाइड्रोक्सी–क्लोरोक्विन के साथ प्रोफिलैक्सिस (बीमारी को रोकने के लिए दिया गया उपचार) SARS-CoV–2 संक्रमण को रोक सकता है।
- हालांकि दवा के कुछ दुष्प्रभाव हैं, यह हृदय अतालता और यकृत क्षति के उदाहरणों से जुड़ा हुआ है।
- व्यापक उपयोग से लोगों में बीमारी से लड़ने की क्षमता में बाधा आ सकती है।

आंतरिक सुरक्षा

पिच ब्लैक रद्द

समाचार –

- कोविड–19 के कारण प्रीमियर मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अर्थात् पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास 27 जुलाई से 14 अगस्त तक निर्धारित किया गया था।
- अभ्यास दुनिया भर की ताकतों के साथ प्रशिक्षण लेने का एक अच्छा अवसर होता है।

- पिच ब्लैक का अगला संस्करण 2022 में होगा।
- 2018 में पिच ब्लैक के अंतिम संस्करण में, भारतीय वायुसेना ने पहली बार लड़ाकु हवाईजहजों की तैनाती की थी जिसने 'एक गतिशील युद्ध वातावरण में विभिन्न देशों के साथ ज्ञान और अनुभव को साझा करने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ था।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और रणनीतिक जुड़ाव हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है, विशेषकर द्विपक्षीय मोर्चे पर सबसे आगे नौसेना के सहयोग के साथ।
- 2019 की शुरुआत में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास AUSINDEX, 1,000 कर्मियों के साथ भारत में अब तक के सबसे बड़े ऑस्ट्रेलियाई सम्मेलन की भागीदारी का गवाह बना।
- पिच ब्लैक अभ्यास के उद्देश्य
  – भाग लेने वाले अनुकूल बलों के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना।
  – ज्ञान और अनुभव के आदान–प्रदान के माध्यम से अंतर को बढ़ावा देना।

अमेरिका ने मिसाइलों और टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी

समाचार –

- अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 155 मिलियन डॉलर मूल्य की मिसाइलों और टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है।
- भारत ने इन सैन्य हार्डवेयर के लिए यूएसए से अनुरोध किया था।
- 10 AGM–84L हार्पून ब्लॉक II एयर लॉन्च की गई मिसाइलों की बिक्री में 92 मिलियन डॉलर खर्च होने की उम्मीद है।
- 16 एमके 54 ऑल अप राउंड लाइटवेट टॉरपीडो और 3 एमके 54 एक्सरसाइज टॉरपीडो की बिक्री पर 63 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है।
- भारत ने अपने ाली P–8I विमान पर एमके 54 लाइटवेट टॉरपीडो का उपयोग करने की योजना बनाई है।
- एमके 54 लाइटवेट टॉरपीडो पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों का संचालन करने की क्षमता देगा।
- हार्पून मिसाइल प्रणाली P–8I विमान में एकजुट होगी।
- यह एकीकरण महत्वपूर्ण समुद्री लेन की रक्षा में सतह–रोधी युद्ध अभियानों का संचालन करेगा।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संबद्ध बलों के साथ सामंजस्य को भी बढ़ाएगा।

हारपून ब्लॉक II मिसाइल

- भूमि से हमलें और जहाज–रोधी दोनों अभियानों को निष्पादित करता है।
- मिसाइल एक निर्दिष्ट लक्ष्य लक्ष्य बिंदु को हिट करने के लिए जीपीएस–एडेड इनरटेड नेविगेशन का उपयोग करती है।
- तटीय रक्षा स्थलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों, उजागर विमान, बंदरगाह / औद्योगिक सुविधाओं और बंदरगाह में जहाजों सहित भूमि आधारित लक्ष्यों की एक विस्तृत विविधता के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

एमके 54 टॉरपीडो

- सिगार के आकार का, स्व–चालित अंडरवाटर मिसाइल
- एक पनडुब्बी, सतह पोत, या हवाई जहाज से लॉन्च किया जाता है।
- जहाजों और पनडुब्बियों के पतवार के संपर्क में विस्फोट के लिए बनाया गया है।
- जानकारी का विश्लेषण करने, झूठे लक्ष्य या प्रतिवाद को संपादित करने और फिर पहचाने गए खतरों का पीछा करने के लिए परिष्कृत प्रसंस्करण एल्गोरिदम का उपयोग करता है।
- अमेरिका के अनुसार, मिसाइलें संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत–प्रशांत क्षेत्र में शांति, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति लाने के लिए अपने प्रमुख रक्षा सहयोगियों में से एक को मजबूत करने में मदद करेंगी।
- भारत अपनी मातृभूमि की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिसाइलों का उपयोग करेगा।
- ये मिसाइलें भारत के पी–81 हवाई जहाजों के साथ पूरी तरह से अनुकूल हैं।
- इसलिए, भारत को इन सशस्त्र बलों में इन प्रणालियों को अवशोषित करने के लिए कोई समस्या नहीं है।

स्वास्थ्य संस्थान को साइबर हमलों का खतरा

समाचार –

- कोविड–19 प्रकोप चिकित्सा बिरादरी, समाज और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक वैश्विक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ है।
- ऐसा साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के कारण है।

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने भारत सहित 194 देशों को चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई के में प्रमुख भूमिका निभा रहे अस्पतालों और अन्य संस्थानों को रेन्समवेयर से लक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- इंटरपोल ने चेतावनी दी कि महामारी के कारण घर से काम करने वाले अधिकांश लोगों के साथ अपराधों के पैटर्न में भी बदलाव आया है।
- मुख्य रूप से ई–मेल के माध्यम से फैलने वाली रैनसमवेयर, अक्सर किसी सरकारी एजेंसी से कोविड–19 के बारे में जानकारी प्राप्त करने का झूठा दावा करते है, जो प्राप्तकर्ता को संक्रमित लिंक या अनुलग्नक पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करते है।
- संगठन अपने सदस्य देशों साथ लगातार खड़ा है। संगठन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को इन अपराधों से अछूता रखने के लिए आवश्यक कोई सहायता भी प्रदान करता है और अपराधियों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराता है।
- इंटरपोल ने अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मॉड्युस ऑपरेंडी, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों की जानकारी लेने या प्रदान करने के लिए एक बैंगनी नोटिस भी जारी किया।
- इंटरपोल की साइबर अपराध धमकी प्रतिक्रिया टीम ने वायरस प्रतिक्रिया में लगे प्रमुख संगठनों के खिलाफ रैंसमवेयर हमलों की संख्या में वृद्धि का पता लगाया था।
- हमलों को इन संस्थानों से रूपये ऐंठने के लिए उनकी महत्वपूर्ण प्रणालियों से बाहर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह इस अभूतपूर्व समय में आवश्यक त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया में भी देरी करेगा। इससे सीधे मौतें भी हो सकती हैं।
- साइबर अपराधी अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल रूप से बंधक बनाने के लिए रैंसमवेयर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण फाइलों और प्रणालियों तक पहुंचने से रोकते हैं जब तक कि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इस स्थिति में, हमलों को रोकने के लिए रोकथाम और शमन प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम –

- रैंसमवेयर/मालवेयर हमलों के खतरे पर प्राप्त अलर्ट को संबंधित विभागों को सूचित किया गया है।
- संस्थानों और व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे कोरोनोवायरस डेटा या घरेलू उपचार पर कोई भी मेल या लिंक न खोलें, जब तक कि यह एक सरकारी एजेंसी की तरह विश्वसनीय स्रोत से न हो।
- उन्हें ई–मेल स्पूफिंग की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी गई थी, जहां एक दूरस्थ स्थान से संचालित होने वाला एक संदिग्ध एक ई–मेल भेजेगा जो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वह किसी ज्ञात व्यक्ति से आया हो।

साइबर क्राइम पैटर्न में निम्न बदलाव हुए हैं–

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और एंटी–वायरल दवाओं में धोखाधड़ी का व्यापार
- व्यक्तियों/व्यवसायों आय घटने पर ऋण शार्क के संभावित लक्ष्य बन सकते हैं।
- ऋण शार्क एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार देता है और अक्सर ऋण लेने के लिए हिंसा के खतरों का उपयोग करता है।
- लॉकडाउन अवधि ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/कारखानों में चोरी की संभावना को बढ़ा दिया है।
- लॉकडाउन ने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए मजबूर किया है। यदि किसी संगठन के पास अपना बुनियादी ढांचा नहीं है तो वह अपने संसाधनों तक पहुँचने के लिए वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का उपयोग नहीं करता है तो उसके द्वारा उपयोग किए गए सार्वजनिक प्लेटफार्मों के उपयोग से गोपनीय डेटा की हानि हो सकती है।
- कोरोनोवायरस संबंधी लॉकडाऊन के शुरू होने के बाद से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा में तेजी आई है।
- हाल के हफ्तों में बाल यौन अपराध करने वाले व्यक्तियों की ऑनलाइन गतिविधि में वृद्धि देखी गई है।
- इसके अलावा, सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लोगों को धोखा देने के लिए नए तरीके (फर्जी खाते और विभिन्न अनुप्रयोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने) का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए किया जा रहा है।

इंटरपोल की सलाह

- लोगों को संदिग्ध ईमेल खोलने से बचने और गैर–मान्यता प्राप्त ईमेल और संलग्नक में लिंक पर क्लिक न करने, नियमित रूप से बैकअप फाइलों, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने, सॉफ्टवेअर को अपडेट रखने, आदि के लिए अनुशंसित किया जाता है।
- कानून–प्रवर्तन एजेंसियों के दिशानिर्देशों में, इंटरपोल ने चिकित्सा उत्पादों के बारे में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की उभरती प्रवृत्ति, महामारी के दौरान धोखाधड़ी वाले ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों की स्थापना, फिशिंग आदि के बारे में चेतावनी दी है।
- कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार के किसी अपराध का पीड़ित बनता है तो उसको तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए ।
- कंप्यूटर से संबंधित गलतियाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम), 2000 के अंतर्गत आती हैं। अपराधी उपयुक्त मामलों में जुर्माना, मुआवजा और आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी हैं।

साइबर धोखाधड़ी के हालिया मामले

1. **पीएम केयर फंड की नकली युपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)** – ID के फिशिंग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अपराधी ने यूजर्स को धोखा देने के लिए एक जैसी दिखने वाली आईडी बनाई। यूपीआई अंर्तबैंकीय लेनदेन के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) द्वारा विकसित एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इंटरफेस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करता है। एनपीसीआई सभी खातों और लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है।
2. **फेसबुक फ्रॉड** – फर्जी फेसबुक अकाउंट्स के मामले सामने आए हैं जहाँ कथित फर्जी मरीजों के अकाउंट हैक करके उनसे पैसे ऐंठ लिए गए हैं।
3. **जूम ऐप मिशन** – कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम–इंडिया (सीईआरटी–इन) ने एक भेद्यता नोट को परिचालित किया, जिससे जूम को 'मध्यम 'सुरक्षा रेटिंग मिली। उपयोगकर्ता के माइक्रोफोन, वेब–कैम और डेटा स्टोरेज तक पहुँचने के लिए जूम को अनुमति देने के परिणामस्वरूप निजी डेटा का अपहरण और नुकसान हो सकता है। 'जूमराइडिंग' या व जोम्बॉम्बिंग 'शुरू किया जा सकता है, जिसमें जूम पर वीडियो कॉल को बाधित करके अभद्र भाषा, अश्लील साहित्य या अन्य सामग्री को अचानक फ्लैश किया जाता है। ऐप में, मीटिंग आईडी को एक लिंक, स्क्रीन और अन्य माध्यमों से साझा किया जा सकता है, जो बिन बुलाए मेहमानों को एक बैठक में शामिल होने और संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने का मौका देता है।
4. **भुगतान संबंधित** – गंतव्य यूपीआई आईडी का सत्यापन, एक चोरी गए मोबाइल फोन को यूपीआई–सक्षम ऐप के साथ अवरुद्ध करना और आरबीआई द्वारा जारी किए गए केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन करना।
5. **सोशल मीडिया संबंधी**– गोपनीयता की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना।
6. **वीडियोकांफ्रेंसिंग संबंधी**– गोपनीय बैठकों के लिए मुफ्त ऐप्स का उपयोग करते समय सतर्क रहना और संगठनात्मक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके वीपीएन या अन्य विकल्पों के माध्यम से प्रमाणीकरण, अभिगम नियंत्रण और डेटा की अखंडता सुनिश्चित करना।

वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद

समाचार –

- पीट्र्सबर्ग जलवायु वार्ता के ग्यारहवें सत्र में भारत के साथ 27–28 अप्रैल 2020 को 30 अन्य देशों ने भाग लिया।
- देशों ने कोविड–19 के बाद अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की मजबूती की चुनौती से निपटने के तरीकों और साधनों पर विचार–विमर्श किया, जबकि सामूहिक लचीलेपन को बढ़ाने और विशिष्ट रूप से उन सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करते हुए जलवायु कार्रवाई को उत्प्रेरित करने पर चर्चा की गई है।
- यह सत्र पहला वर्चुअल जलवायु संवाद था, जिसे 2010 से जर्मनी द्वारा होस्ट किया गया था।
- यह अनौपचारिक उच्च–स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं और जलवायु कार्रवाई की उन्नति दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है।

एंटी स्मॉग गन

समाचार –

- दिल्ली में 47 बड़ी परियोजनाओं में से 14 पर एंटी–स्मॉग बंदूकें स्थापित की गई हैं।
- यह उच्चतम न्यायालय द्वारा धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सभी बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी–स्मॉग गन की स्थापना के आदेश के बाद किया गया है।
- डिवाइस उच्च दबाव वाले प्रोपेलर द्वारा हवा में नेबुलाइज्ड पानी की बूंदें छिड़कता है।

कोविड–19 जैव–चिकित्सा अपशिष्ट निपटान

समाचार –

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति से कोविड–19 बीमारी के जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान के संभावित जोखिम को कम करने के लिए गंभीर प्रयासों में लगाने का आग्रह किया है।
- न्यायाधिकरण ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 'हैंडलिंग, उपचार, इलाज के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के निपटान, कोविड–19 मरीजों के संगरोध इत्यादि के दिशानिर्देशों का अवलोकन भी किया।

- NGT ने बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुपालन में अंतराल के मुद्दे को उठाया।
- यह नियम एक वायरल बीमारी से निपटने के लिए उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए लागू होते हैं।
- इसने दिशानिर्देशों के संशोधन की आवश्यकता व्यक्त की ताकि तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक निपटान के सभी पहलुओं पर न केवल संस्थान स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी ध्यान दिया जाए।
- पहलुओं में अन्य निजी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होने के बिना इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), प्रयुक्त बैग, दस्ताने, काले चश्मे के निपटान के तरीके शामिल हैं।
- यह कहा गया कि संबंधित स्थानीय निकायों में प्रशिक्षण का आयोजन, विशेष जागरूकता प्रोग्रामरों द्वारा जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य विभागों की आवश्यकता है, जो श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षात्मक गियर, मीडिया और अन्य संबंधित नियामक अधिकारियों के साथ पर्याप्त समन्वय के साथ कोविड–19 कचरे से निपटने में सहायता प्रदान करते हैं।

सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान

समाचार –

- कोविड–19 के लिए लॉकडाउन के बीच, गुजरात सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए संरक्षण योजना 'सुजलम सुफलाम जलसंचय अभियान' का तीसरा संस्करण शुरू किया।
- यह योजना 10 जून 2020 तक जारी रहेगी।
- यह गाद को हटाकर झीलों, चौक डेम और नदियों के गहरीकरण को देखेगा, और यह लोगों की भागीदारी के साथ किया जाएगा।
- योजना लॉकडाउन के बीच, मनरेगा के तहत ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिसमें कोरोनोवायरस के प्रकोप से निपटने के लिए नियमों को लागू करने के लिए नियमों का पालन किया जाएगा।

चक्रवातों की नई सूची

समाचार –

Place	List 1	List 2	List 3	List 4	List 5	List 6
Bangladesh	Nisarga	Biparjoy	Arnab	Upakul	Barshon	Rajani
India	Gati	Tej	Murasu	Aag	Vyom	Jhar
Iran	Nivar	Hamoon	Akvan	Sepand	Booran	Anahita
Maldives	Burevi	Midhili	Kaani	Odi	Kenau	Endheri
Myanmar	Tauktae	Michaung	Ngamann	Kyarthit	Sapakyee	Wetwun
Oman	Yaas	Remal	Sail	Naseem	Muzn	Sadeem
Pakistan	Gulab	Asna	Sahab	Afshan	Manahil	Shujana
Qatar	Shaheen	Dana	Lulu	Mouj	Suhail	Sadaf
Saudi Arabia	Jawad	Fengal	Ghazeer	Asif	Sidrah	Hareed
Sri Lanka	Asani	Shakhti	Gigum	Gagana	Verambha	Garjana
Thailand	Sitrang	Montha	Thianyot	Bulan	Phutala	Aiyara
United Arab Emirates	Mandous	Senyar	Afoor	Nahhaam	Quffal	Daaman
Yemen	Mocha	Ditwah	Diksam	Sira	Bakhur	Ghwyzi

List 7	List 8	List 9	List 10	List 11	List 12	List 13
Nishith	Urmi	Meghala	Samiron	Pratikul	Sarobor	Mahanisha
Probaho	Neer	Prabhanjan	Ghurni	Ambud	Jaladhi	Vega
Azar	Pooyan	Arsham	Hengame	Savas	Tahamtan	Toofan
Riyau	Guruva	Kurangi	Kuredhi	Horangu	Thundi	Faana
Mwaihout	Kywe	Pinku	Yinkaung	Linyone	Kyeekan	Bautphat
Dima	Manjour	Rukam	Watad	Al-jarz	Rabab	Raad
Parwaz	Zannata	Sarsar	Badban	Sarrab	Gulnar	Waseq
Reem	Rayhan	Anbar	Oud	Bahar	Seef	Fanar
Faid	Kaseer	Nakheel	Haboob	Bareq	Alreem	Wabil
Neeba	Ninnada	Viduli	Ogha	Salitha	Rivi	Rudu
Saming	Kraison	Matcha	Mahingsa	Phraewa	Asuri	Thara
Deem	Gargoor	Khubb	Degl	Athmad	Boom	Saffar
Hawf	Balhaf	Brom	Shuqra	Fartak	Darsah	Samhah

- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों की एक नई सूची भारत मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी की गई है जो निर्सग (बांग्लादेश), गाटी (भारत), निवार (ईरान) से शुरू होती है।

- सूची में भारत के 169 नाम शामिल हैं जिनमें से 13 नाम भारतीय मूल से हैं, जैसे कि गती, तेज, आग, नीर, व्योम, झार, जलधि, मुरासु, प्रोबाहो, प्रभंजन, घुमी, अंबुद और वेग।
- आईएमडी पाँच क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों (टीसीडब्ल्यूसी) के साथ–साथ दुनिया भर में स्थापित छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (आरएसएमसी) में से एक है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परामर्श और नाम जारी करने का काम दिया जाता है।
- आईएमडी बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन सहित 13 सदस्य देशों को आगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में सलाह जारी करता है।

सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हुआ

समाचार –

- कोपरनिकस वायुमंडलीय निगरानी सेवा (CAMS) में तैनात वैज्ञानिक जो ओजोन छिद्र पर नजर रख रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण बने सबसे बड़ा ओजोन होल अपने आप समाप्त हो गया है।
- यह छेद 620,000 वर्ग मील (या 997793.28 किलोमीटर) के क्षेत्र में फैला था।
- यह उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक क्षेत्र में दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो अब ठीक हो गया है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार छेद को बंद करना ध्रुवीय भंवर नामक घटना के कारण है, जिसका कोविड–19 लॉकडाउन के कारण कम हुए प्रदूषण से संबंध नही है।
- ध्रुवीय भंवर को बेहद शक्तिशाली होने के लिए दर्ज किया गया है, और इसके अंदर का तापमान बहुत ठंडा है। शक्तिशाली भंवर और कम तापमान का अनोखा मिश्रण स्ट्रैटोस्फेरिक बादल उत्पन्न करता है जो सीएफसी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और प्रक्रिया में ओजोन परत को प्रभावित करते हैं।
- यह ध्रुवों पर कम दबाव का एक भँवर शंकु के रूप में वर्णित किया जाता है जो सर्दी के महीनों में बढ़ते तापमान के कारण सबसे अधिक होता है।

पृथ्वी का भूकंपीय शोर

समाचार –

- ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे (BGS) के वैज्ञानिकों ने परिवेशी भूकंपीय नाद के स्तर में 30–50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है क्योंकि मार्च 2020 के मध्य में स्कूल और व्यवसाय बंद थे।
- कम नाद के स्तर के कारण, वैज्ञानिक अब उम्मीद कर रहे हैं कि वे छोटे भूकंप और झटके का पता लगाने में सक्षम होंगे जो अब तक उपकरणों से छुट जाते थे।
- भूविज्ञान में, भूकंपीय नाद जमीन में कई कारणों से होने वाले लगातार कंपन को संदर्भित करता है।
- यह एक सिस्मोमीटर द्वारा दर्ज किए गए संकेतों का अवांछित घटक है – वैज्ञानिक उपकरण जो जमीनी गति को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी स्फुटन और विस्फोट।
- आमतौर पर, भूकंपीय गतिविधि को सही ढंग से मापने और भूकंपीय नाद के प्रभाव को कम करने के लिए, भूवैज्ञानिक अपने डिटेक्टरों को पृथ्वी की सतह से 100 मीटर नीचे रखते हैं।
- भूविज्ञान के अलावा, अन्य क्षेत्रों जैसे कि तेल की खोज, जल विज्ञान और भूकंप इंजीनियरिंग में भूकंपीय नाद का भी अध्ययन किया जाता है।

देवनहल्ली चकोटा

समाचार –

- बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल), जो विश्व पृथ्वी दिवस की 50 वीं वर्षगांठ के भाग के रूप में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (बीएलआर–एयरपोर्ट) का स्वामित्व और संचालन करता है, लुप्तप्राय फलों के संरक्षण की उम्मीद करता है, जिसका नाम देवनाहल्ली पोमेलो या चकोटा है।
- देवनहल्ली पोमेलो एक खट्टे किस्म है जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, इसे हवाई अड्डे के परिसर के भीतर खेती करके।
- देवनहल्ली पोमोलो, जो एक भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के साथ आता है, में अपनी किस्मों के विपरीत एक अनूठा, मीठा स्वाद है।
- पोमेलो वृक्षारोपण के हेक्टेयर, जो कभी देवनहल्ली क्षेत्र को बिताते थे, अब सभी गायब हो गए हैं।
- वर्तमान में, क्षेत्र में 100 से कम काश्तकार हैं।

- अब अपने प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम नम्मा ओरू के हिस्से के रूप में, बीआईएएल 500 पोमोलो के पेड़ लगाएगा।
- कर्नाटक बागवानी विभाग के समर्थन से, बीआईएएल ने पौधे खरीदे और हवाई अड्डे के निर्माण से पहले एक स्थान पर 50 पौधे लगाए हैं, जो कभी पोमेलोस का केंद्र था।
- इस पहल के साथ, देवेनहल्ली पोमेलो के पिछले गौरव को पुनर्जीवित, संरक्षित और पुर्नस्थापित करने का उद्देश्य, एक फल जो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिसमें बीएलआर हवाई अड्डा स्थित है।
- बीआईएएल ने क्षेत्र के चारों ओर फलों की खेती को बढ़ावा देने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करके एक व्यवहार्य बाजार विकसित करने की योजना बनाई है।
- बीआईएएल देवनहल्ली और उसके आसपास के किसानों के साथ भी काम करेगा।

असम हाथी रिजर्व में खनन के लिए वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी

समाचार –

- देशव्यापी लॉकडाउन के बीच, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने असम में एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है।
- एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने उत्तरी ईस्टर कोल फील्ड (एनईसीएफ) द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए साल्की प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि से 98.59 हेक्टेयर भूमि के उपयोग के लिए एक सुझाव पर चर्चा की थी।
- नॉर्थ ईस्टर कोल फील्ड (NECF) कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है।
- NBWL पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन है।
- साल्की देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है।
- सेल्कु में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, जो शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकी जिलों में 111.19 वर्ग किमी वर्षावन और कई आरक्षित वनों को कवर करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग

समाचार –

- अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के अमेरिकी आयोग ने भारत को एक रिपोर्ट में सबसे बदतर स्थिति में बताया है।
- इसने अपनी 2020 की रिपोर्ट में चीन, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे पास के देशों के बीच भारत को विशिष्ट चिंता वाले देशों '(सीपीसी) में डाल दिया है।
- भारत को पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 'टीयर 2 देश' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- यह 2004 के बाद पहली बार है जब भारत को इस श्रेणी में रखा गया है।
- इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्टर, परिवर्तन कानूनों और जम्मू और कश्मीर की परिस्थितियों के खिलाफ स्पष्ट चिंताएं शामिल थीं।
- आयोग ने अतिरिक्त रूप से सुझाव दिया कि अमेरिकी सरकार 'वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' (IRFA) के तहत भारत के खिलाफ कठोर कदम उठाती है।
- इसने संगठन को भारतीय सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों पर प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य किया, जो सख्त अवसर के गंभीर उल्लंघन के लिए उत्तरदायी थे।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (USCIRF)

- यह एक अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है जो 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
- मुख्यालय – वाशिंगटन, डी.सी.
- यह अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मुद्दों की निगरानी और शोध करता है।
- यह दुनिया भर में सख्त अवसर उल्लंघन की वास्तविकताओं और शर्तों के आकलन के बाद एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है।

जिम्मेदारियाँ

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा करना।
- राष्ट्रपति, राज्य सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करना।

नूर उपग्रह

समाचार –

- ईरान ने 425 किमी (264 मील) की उच्च कक्षा में अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसका नाम नूर (एनओओआर) था।
- उपग्रह को तीन–चरण रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है जो ठोस और तरल ईंधन के संयोजन द्वारा संचालित था।
- इस कदम ने यूएसए के साथ उस समय तनाव बढ़ा दिया जब दोनों देश पहले ही फारस की खाड़ी में भिड़ रहे हैं।
- ईरान ने 2009 में अपना पहला नागरिक उपग्रह लॉन्च किया था।

आसियान शिखर सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित

समाचार –

- वियतनाम ने एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।
- चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेता भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।
- वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं से कोरोनोवायरस से निपटने के लिए एक आपातकालीन कोष स्थापित करने का आग्रह किया है।
- कोविड–19 ने क्षेत्र के पर्यटन और निर्यात–निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया है।
- ASEAN नेताओं ने कोविड–19 की अपंग आर्थिक लागत के बारे में चेतावनी दी तथा नौकरिया, खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा उपकरणों के भंडार इत्यादि के लिए व्यापार मार्गों को फिर से खोले जाने की मांग की है।

आईएमएफ ने $500 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों के लिए छह महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए $500 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी।
- इससे IMF के सबसे गरीब और सबसे कमजोर सदस्य देशों को कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए अनुदान मिलेगा।
- 25 देशों में से कई में प्रति राष्ट्र 50 से कम महत्वपूर्ण देखभाल इकाई बेड हैं।
- आईएमएफ ने अफगानिस्तान, हैती, नेपाल, सोलोमन द्वीप, ताजिकिस्तान और यमन जैसे 19 अफ्रीकी देशों के लिए तत्काल ऋण सेवा राहत को मंजूरी दी।
- वे महत्वपूर्ण आपातकालीन चिकित्सा और अन्य राहत प्रयासों के लिए अपने दुर्लभ वित्तीय संसाधनों को अधिक से अधिक चैनल करने में सक्षम होंगे।
- यह धन आईएमएफ के प्रलयकारी कंटेनर और राहत ट्रस्ट (CCRT) से आएगा।
- यह हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से 185 मिलियन और जापान से 100 मिलियन का उपयोग करेगा।
- आईएमएफ ने अन्य दाताओं से ट्रस्ट के संसाधनों को फिर से भरने में मदद करने का आग्रह किया।

तबाही कंटेनर और राहत ट्रस्ट (CCRT)

- CCRT आईएमएफ को भयावह प्राकृतिक आपदाओं या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं से प्रभावित सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों के लिए ऋण राहत के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है।
- ऋण सेवा के भुगतान पर राहत, आपदा द्वारा विकसित किए गए भुगतान संतुलन के असाधारण संसाधनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को मुक्त कर देती है।
- इसे फरवरी 2015 में इबोला के प्रकोप के दौरान स्थापित किया गया था और मार्च 2020 में कोविड–19 महामारी की प्रतिक्रिया में संशोधित किया गया था।

कोविड–19 सहायता पैकेज का ADB द्वारा आश्वासन दिया गया

समाचार –

- भारत सरकार ने स्वास्थ्य और सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में, कोविड–19 को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से $1.5 बिलियन का ऋण लिया है।

- एडीबी ने महामारी के लिए भारत सरकार की निर्णायक प्रतिक्रिया की प्रशंसा की, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यक्रम और व्यवसायों को प्रदान किए जाने वाले अन्य राहत उपाय शामिल हैं।

ADB का भारत को समर्थन

- एडीबी इस अवधि के दौरान अपनी वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है।
- जब भी स्थिति में सुधार होता है, वह आगे वित्तीय मदद और नीति सलाह देने के लिए तैयार होता है।
- एडीबी भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सभी वित्तपोषण विकल्पों पर विचार करना चाहता है
- एडीबी का इरादा आपातकालीन सहायता, नीति–आधारित ऋण और बजट समर्थन जैसे एडीबी फंडों के त्वरित संवितरण की सुविधा प्रदान करना है।

ऑपरेशन संजीवनी

समाचार –

- भारत ने मालदीव को इन्फ्लूएंजा के टीके, एंटीवायरल ड्रग्स (लोपिनवीर, रटनवीर आदि) के साथ–साथ उपभोग्य सामग्रियों (कैथेटर्स, नेबुलाइजर, मूत्र बैग और शिशु आहार ट्यूब) जैसी 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की।
- ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायु सेना के एक हरक्यूलिस सी–130 जे–30 विमानों द्वारा आपूर्ति भेजी गई है।
- ऑपरेशन संजीवनी कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में एक सहायता है।
- लोपिनेवीर और रेटनवीर का उपयोग कुछ देशों में कोविड–19 रोगियों के इलाज के लिए किया गया है।
- मार्च में, भारत ने वायरल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मालदीव में सेना की एक 14–सदस्यीय मेडिकल टीम भेजी।
- भारत ने मालदीव को 5.5 टन आवश्यक दवाएं उपहार में दीं।

भारत–मालदीव संबंध

- दोनों देश जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं।
- भारत ने 1965 में मालदीव को मान्यता दी और बाद में 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया।
- 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत, भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्तापलट के प्रयास को निष्प्रभावी करने में मालदीव की मदद की है।
- भारत ने 2004 में सुनामी के बाद मालदीव की मदद की है।
- यूएई, चीन और सिंगापुर के बाद भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर करती है, जो विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत है।
- 2014 में 'ऑपरेशन नीर 'के तहत, भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पीने के पानी की आपूर्ति की।
- मालदीव के सशस्त्र बलों को भारत द्वारा दिए गए दो एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) का उपयोग मालदीवियन जीवन को बचाने में किया गया है।
- ALH एक बहु–भूमिका, 5.5–टन भार वर्ग में नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
- भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) को सर्वाधिक प्रशिक्षण देता है।
- ये प्रशिक्षण अवसर उनकी रक्षा प्रशिक्षण जरूरतों के 70 प्रतिशत को पूरा करते हैं।
- 'एकुवेरिन' भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

कला एवं संस्कृति

दक्षिण भारत में नववर्ष का स्वागत

समाचार –

- तमिल नववर्ष, विशु महोत्सव तथा पुथंडु प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को क्रमशः केरल और तमिलनाडु के सभी हिस्सों में मनाया जाता है।

विशु महोत्सव

- यह पारंपरिक रूप से मलयालम पंचांग में नए साल के रूप में नहीं मनाया जाता है, हालांकि, मालाबार क्षेत्र के लोग इस त्योहार को ज्योतिषीय नववर्ष का आगमन मानते हैं।
- यह त्योहार मंदिरों में दिन के शुरुआती घंटों में मनाया जाता है।

- यह सबरीमालाअयप्पन मंदिर या गुरुवायुरश्री कृष्ण मंदिर या कुलाथुपुझाश्रीबालास्थ मंदिर में मनाया जाता है।
- विशु दावत का दिन है। खाद्य पदार्थों में नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वा समान मात्रा में होता है, जिसमें नीम से बना कड़वा वेप्पमपुरासम तथा खट्टे आम का सूप शामिल है।
- अन्य त्योहारों के समान, विशु में भी भोजन एक विशेष आकर्षण होता है।
- लोग साद्या पर न्यौते देते हैं – एक न्यौते में विभिन्न पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन शामिल होते हैं।
- केरल में आमतौर पर भोजन केले के एक पत्ते पर परोसा जाता है।
- कई लोगों का यह मानना है कि उनका नया साल इस दिन शुभ होगा।
- इस प्रकार, मलयाली महिलाएं विशुक्कनी नामक एक सेटिंग तैयार करती हैं।
- जिसमें, चावल, स्वर्ण नींबू, स्वर्ण ककड़ी, खुला नारियल, कटहल, कन्माशी काजल, सुपारी, सुपारी, धातु का दर्पण, सुनहरे पीले कोना फूल, पवित्र वस्त्र, सिक्के या मुद्रा नोट, तेल का दीपक, जैसे आइटमों के साथ विष्णुकणी तैयार की जाती है, और हिंदू भगवान विष्णु की एक छवि होती है।
- घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भोर में दीपक जलाता है।
- वह प्रत्येक सदस्य को किसी भी चीज से पहले दीपक देखने के लिए उनकी आँखें को हाथो से आ ढक देता है।

पुथंडु –

- यह त्यौहार तमिल महीने चिथिराई के पहले दिन मनाया जाता है और तमिल पंचांग के शुरू होने का प्रतीक है।
- पुथंडू दुनिया भर में तमिलों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है।
- यह त्योहार श्रीलंका, मॉरीशस, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में मनाया जाता है।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह माना जाता है कि हिंदू देवताओं के पवित्र त्रिदेवों के भगवान ब्रह्मा ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था।
- पुथंडु तमिलनाडु के 23 सार्वजनिक अवकाशों में शामिल है, जो कि 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार है।

विश्व धरोहर दिवस (वर्ल्ड हैरिटेज डे)

समाचार –

- प्रतिवर्ष, 18 अप्रैल को समाज में विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है।
- विश्व विरासत दिवस 2020 का थीम – 'साझा संस्कृति, साझा विरासत एवं साझा जिम्मेदारी'।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक धरोहर स्थलों में छठे स्थान पर है। भारत में कुल 38 विरासत स्थल हैं।
- विश्व विरासत स्थल को प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र या संरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, और ऐसे स्थान हैं जिन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है।
- इन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, जिसे यूनेस्को के रूप में भी जाना जाता है।
- यूनेस्को का मानना है कि विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत स्थल मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं, और वे सांस्कृतिक और भौतिक महत्व रखते हैं।

ICH की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ

समाचार –

- भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है ताकि इसकी अमूर्त विरासत में भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचाना जा सके। यह पहल मंत्रालय के विजन 2024 का एक हिस्सा है।
- सूची में 100 से अधिक तत्व हैं, जिसमें भारत के 13 तत्व शामिल हैं, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भी अंकित हैं (यह सूची 2008 में स्थापित की गई थी, जब सांस्कृतिक संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था)।
  1. वैदिक जप की परंपरा
  2. रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन
  3. कुटियाट्टम, संस्कृत रंगमंच
  4. गढ़वाल हिमालय के राममन, धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान मंच।
  5. मुदियेट्टू, अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक।
  6. कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य।
  7. छाऊ नृत्य

8. लद्दाख का बौद्ध जपः ट्रांस हिमालयन लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ।
9. संकीर्तन, अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नृत्य करना।
10. पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प।
11. योग
12. नवरोज़
13. कुम्भ मेला

- अमूर्त सांस्कृतिक संरक्षण के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन का पालन करके राष्ट्रीय आईसीएच सूची को 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया गया है।
  1. मौखिक परंपरा और अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहन के रूप में भाषा सहित
  2. प्रदर्शन कलाएँ
  3. सामाजिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और उत्सव की घटनाएँ
  4. प्रकृति और ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान और अभ्यास
  5. पारंपरिक शिल्प कौशल

चकमा और हाजोंग

समाचार –

- अधिकार और जोखिम विश्लेषण समूह ने अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हजोंग समुदायों के लिए भोजन सुनिश्चित करने में भारतीय पीएम के हस्तक्षेप की मांग की है।
- कोरोमा वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोविड–19 आर्थिक राहत पैकेज में चकमा और हाजोंग्स को कथित तौर पर शामिल नहीं किया गया है।

समुदायों के बारे में –

- ये जनजातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी इलाकों में रहते थे, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश में स्थित हैं। 1960 के दशक में कपाई बांध परियोजना द्वारा जलमग्न होने पर उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ दी थी।
- चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग्स हिंदू हैं, उन्हें भी कथित रूप से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उन्होंने असम के तत्कालीन लुशाई हिल्स जिले (अब मिजोरम) के माध्यम से भारत में प्रवेश किया।
- केंद्र ने उनमें से अधिकांश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) में स्थानांतरित कर दिया, जो अब अरुणाचल प्रदेश में है।
- उनकी संख्या 1964–69 में लगभग 5,000 से एक लाख हो गई है। वर्तमान में, उनके पास नागरिकता और भूमि अधिकार नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, म्यांमार और बांग्लादेश में पाए जाते हैं।
- 2015 में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को उन चकमा और हजोंग्स व्यक्तियों को जो 1964–69 में बांग्लादेश से चले आए थे, नागरिकता देने का निर्देश दिया।

बोहाग या रोंगालीबिहू

समाचार –

- पहली बार, असम ने बोहाग या रोंगाली बिहू को कोविड–19 लॉकडाउन के कारण बिना रोंग (अर्थात खुशी) के मनाया।

विवरण –

- बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। यह वर्ष में तीन बार मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है।
- रोंगाली या बोहाग बिहू असमिया नववर्ष और वसंत के त्योहार है। यह सिख नववर्ष–बैसाखी के साथ आता है।
- बोहाग बिहू तिथियां 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक हैं।
- यह एक फसल या बुवाई का त्योहार है। यह हिंदू सौर कैलेंडर के पहले दिन को चिह्नित करता है और बंगाल, मणिपुर, मिथिला, नेपाल, ओडिशा, पंजाब, केरल तथा तमिलनाडु में भी मनाया जाता है।
- उत्सव के खाद्य पदार्थ में पीठा (राइस केक) और लार्स (चावल, नारियल से बना पारंपरिक भोजन) तैयार किए जाते हैं।
- पारंपरिक मग रेशम (गोल्डन सिल्क) में पुरुष और महिलाएं राज्य भर में बिहुधोल (पारंपरिक ड्रम) की बिहू धुनों और ताल पर नृत्य करते हैं।
- बिहू नृत्य असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है।
- हथकरघों पर बुने जाने वाले पारंपरिक गमोसा को बिहू के रूप में किसी के प्रिय और मेहमानों को भी दिया जाता है।

गमोसा –

- गामोसा असम के लोगों के लिए महत्व की वस्तु है।
- यह आम तौर पर कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें मुख्य रूप से तीन तरफ लाल बॉर्डर और चौथे पर लाल बुने हुए रूपांकन होते हैं।
- असम में पारंपरिक रूप से दो प्रकार के गामोस थे। उकोर सादा किस्म जो स्नान के बाद शरीर को पसीना पोंछने या सुखाने का काम आता था। फुलम, जो फुलों के रूपांकनों से बुना होता है तथा जिसे बिहु इत्यादि त्यौहार पर उपहार के रूप में एक दुसरे को दिया जाता है।
  गमोसा 1916 में असम की राष्ट्रीयता के प्रतिक के रूप में उभरा जब असमिया साहित्य सभा, जो एक साहित्यिक संस्था के बाद असमिया छात्र सम्मिलन जो कि एक छात्र संगठन है, का गठन किया गया।
- गर्दन के चारों ओर फुलगामोसा पहनना सांस्कृतिक पहचान के लिए एक मानक बन गया।
- जीवन का असमिया तरीका गमोसा में बुना जाता है, चाहे वह सादा या सजावटी हो।
- इससे पहले कि डिजाइनरों ने विशिष्ट शर्ट जैसे ड्रेस सामग्री के रूप में इसकी क्षमता का पता लगा पाते यह एक सांस्कृतिक प्रतीक से, यह एक राजनीतिक प्रतीक बन गया।
- विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में गमोसा का ग्राफ 1979–1985 के विदेशी विरोधी असम आंदोलन के दौरान बढ़ा।
- गमोसा ने दिसंबर 2019 के मध्य से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध के साथ एक राजनीतिक बयान के रूप में वापसी की। कोविड–19 ने गेमोस को मुखौटे में बदल दिया।

अंबुबाची मेला

समाचार –

- कोविड–19 महामारी के कारण असम का अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया है। त्योहार को 'पूर्व के महाकुंभ' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं।
- यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर के रूप में कार्य करता है। असम में लड़कियों की नारीत्व की प्राप्ति एक रस्म 'तुलोनीबिया' मनाती है, जिसका अर्थ है छोटी शादी।
- देवी की अवधि का जश्न मनाने वाला अनुष्ठान मेला एक कारण है कि भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ कम है।
- यह त्यौहार देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है, जिसकी पूजा एक योनी जैसे पत्थर के रूप में की जाती है जिसके ऊपर एक प्राकृतिक झरना बहता है, क्योंकि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है।
- कामाख्या, गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों के ऊपर, 51 शक्तिपीठों में से एक या शक्ति अनुयायियों की सीट है, जिनमें से प्रत्येक भगवान शिव के साथी सती के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- देवी एक हिंदू तांत्रिक देवी हैं जो इच्छा से हिमालय की पहाड़ियों में विकसित हुई हैं। उसकी पहचान काली और महा त्रिपुर के रूप में भी है। इसलिए, वह सिद्धकुब्जिका के रूप में भी जानी जाती है।

मेरु जात्रा त्यौहार और पट्टचरित्र

समाचार –

- ओडिशा के गंजम जिला प्रशासन ने कोविड–19 के कारण, महाविषु संक्रांति (13 अप्रैल, 2020) के अवसर पर मंदिरों में मेरुजात्रा उत्सव और उससे संबंधित मण्डलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले, प्रशासन ने तारा तारिणी पहाड़ी पर प्रसिद्ध चैत्रराजा उत्सव पर भी प्रतिबंध लगा दिया था
- कोविड–19 ने पट्टचित्रा चित्रों की बिक्री को भी प्रभावित किया है।

विवरण –

- मेरुजात्रा 21 दिनों के लंबे तप के अंत का प्रतीक है, जिसका नाम 'दंडनाटा' ('चैत्र' के महीने में मनाया जाता है), है।
- दंड, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वयं को दी जाने वाली पीड़ा है, जो दांडूस (त्योहार में भाग लेने वाले लोग) स्वामी काली को मानने के लिए अदा करते हैं। यह भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती की पूजा करने का एक रूप भी है।
- त्योहार की उत्पत्ति आमतौर पर ओडिशा में बौद्ध धर्म के पतन के बाद 8 वीं और 9 वीं ईस्वी तक पाई जाती है।
- महाविशूब संक्रांति (ओडिया नव वर्ष की शुरुआत) के अवसर पर हजारों भक्त तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर और अन्य मंदिरों में इकट्ठा होते थे।
- तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर, ऋषिकुल्या नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जो ओडिशा में शक्ति पूजा का एक प्रमुख केंद्र है। जुड़वां देवी तारा और तारिणी एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और गंजम जिले की मुख्य देवता हैं।

पटचित्र की चित्रकला शैली

- यह ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है।
- पट्टचित्रा नाम संस्कृत शब्दों पट्ट, अर्थ कैनवास और चित्र से लिया गया है, जिसका अर्थ चित्र है। पट्टचित्रिस कैनवास पर किए गए हैं और समृद्ध रंगीन अनुप्रयोग, रचनात्मक रूपांकनों और डिजाइनों और सरल विषयों के चित्रण से प्रकट होते हैं, जो ज्यादातर चित्रण में पौराणिक हैं।
- पटचित्र, जब कपड़े पर चित्रित किया जाता है, कैनवास की तैयारी की एक पारंपरिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। सबसे पहले, बेस को नरम, सफेद, चाक के पत्थर के पाउडर और इमली के बीज से बने गोंद के साथ कोटिंग करके तैयार किया जाता है।
- पहले पेंटिंग की सीमाओं को पूरा करना एक परंपरा है। चित्रकार फिर हल्के लाल और पीले रंग का उपयोग करके ब्रश के साथ एक मोटा स्केच बनाना शुरू कर देता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग सफेद, लाल, पीले और काले होते हैं।

दरबार परिवर्तन पर रोक

- जम्मू एवं कश्मीर शासन ने 144 वर्षों में पहली बार कोविड–19 महामारी के चलते वर्ष में दो बार राजधानी बदलने की प्रथा जिसे दरबार परिवर्तन कहा जाता है पर रोक लगा दी है।
- मई से ऑक्टोबर अर्थात ग्रीष्म ऋतु में राज्य की राजधानी श्रीनगर होती है जबकि शीत ऋतु में इसे जम्मु से चलाया जाता है।
- दरबार परिवर्तन जम्मु एवं कश्मीर के दो विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का कार्य करता है।
- इस प्रथा की शुरूआत डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह द्वारा 1872 में की गई थी।
- वे जम्मु एवं कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाबसिंह के तीसरे पुत्र थे।

मुख्य परीक्षा
सामान्य अध्ययन I
(भारतीय धरोहर एवं संस्कृति, विश्व एवं समाज का इतिहास तथा भुगोल)

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी

समाचार –

- संयूक्त राष्ट्र महिला, महिला अधिकार कार्यकर्ता, शासकीय अधिकारियों तथा संपूर्ण विश्व के सिविल सोसायटी भागीदारों ने कोविड–19 के दौरान महिलाओं पर हुई घरेलू हिंसा जो अन्य राष्ट्रों के अलावा अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, युनाईटेड किंगडम, सायप्रस, सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ी है पर चिंता जताई है।
- संयुक्त राष्ट्र महिलाओं ने सदस्य–राज्यों से आग्रह किया है हिंसा के खिलाफ रोकथाम पर ध्यान दिया जाए। लिंग–आधारित इस हिंसा वृद्धि को कोविड–19 के समानांतर एक ओर महामारी कहा जा रहा है।
- राष्ट्रीय लॉकडाउन ने कई लोगों को बेरोजगार, वेतन मिलने के प्रति अनिश्चित, मजबूर में अलगाव और तनावग्रस्त घरों में रहने के लिए मजबुर कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप महिला के विरुद्ध क्रूरतामें वृद्धि हुई है।
- कई देशों में कानून महिलाओं के पक्ष में नहीं है। प्रति चार में से एक देश में घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं के लिए कोई कानून नही है।
- भारत में, महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग (NCW) ने कोविड–19 महामारी के कारण घरेलू हिंसा के मामलों में दोगुना की वृद्धि दर्ज की है।
- 40 प्रतिशत से भी कम महिलाएं जो घरेलू हिंसा का सामना करती हैं किसी भी तरह की मदद चाहती है या अपराध की सूचना देती है। 10 प्रतिशत से कम महिलाएं ऐसी हैं जो पुलिस के पास जाना पसंद करती हैं।
- वर्तमान परिस्थितियों (कोविड–19 महामारी) रिपोर्टिंग को और भी कठिन बना देती है, जिसमें महिलाओं की फोन और हेल्पलाइन तक लड़कियों की पहुँच और बाधित सार्वजनिक, न्याय और सामाजिक सेवाएं शामिल है।
- लिंग अधिकार कार्यकर्ता और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने हेल्पलाइन, मनो–सामाजिक समर्थन, महिलाओं की

सहायता के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

संभावित कारण –

- महिलाएं घरों में निजता की कमी के कारण बाहर निकलने पर प्रतिबंध के कारण शिकायत नही कर पा रही हैं।
- अपनी नौकरी, वेतन और आजीविका के बारे में लोगों के मन में बहुत चिंता है। पितृसत्तात्मक समाजों में अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए महिलाएं पुरुषों के लिए आसान लक्ष्य बन जाती हैं।
- इसने हिंसा से बचने के लिए आवाजाही को बंद कर दिया है और हिंसा से बचने के रास्ते बंद कर दिए हैं, जैसे कि अपने घरों में या स्थानीय पुलिस से संपर्क करके।
- इस बात के सबूत हैं कि संकट या आपदा की स्थितियों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है।

घरेलू हिंसा का प्रभाव

- कोविड–19 से पहले ही, घरेलू हिंसा पहले से ही सबसे बड़े मानव अधिकारों के उल्लंघन में से एक थी।
- इससे महिलाओं की भलाई, उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, उनके मानसिक स्वास्थ्य, और हमारे समाजों, अर्थव्यवस्था की वसूली में भाग लेने और नेतृत्व करने की उनकी क्षमता और सतत विकास लक्ष्य–5 (SDG–5) प्राप्त करने में उनकी क्षमता पर कई प्रभाव पड़ेंगे। ।
- ये व्यवधान बलात्कार के नैदानिक प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य और मनो–सोशलएबिलिटी की तरह देखभाल और सहायता से बचे हैं, जिनकी आवश्यकता है।
- विघ्न अपराधियों के लिए भी अशुद्धता का ईंधन है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण

1. यह संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए एक अधिनियम है जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा का शिकार है और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए है।
2. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत में घरेलू अपराध को दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता देने, लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसके प्रावधानों का विस्तार करने और कानूनी सहायता के अलावा पीड़ितों के लिए आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए पहला महत्वपूर्ण प्रयास है।
3. इसका उद्देश्य घर में महिलाओं को शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण से बचाना है। इसके अलावा, 1983 में, घरेलू हिंसा को भारतीय दंड संहिता की धारा 498। की शुरूआत के द्वारा एक विशेष आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता दी गई थी। यह धारा एक विवाहित महिला के प्रति पति या उसके परिवार द्वारा क्रूरता से पेश आती है।

आगे को राह –

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन पैकेज में निहित उपायों से तत्काल निपटा जाना चाहिए जो चुनौती के गुरुत्वाकर्षण और पैमाने को पूरा करते हैं और उन महिलाओं की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो भेदभाव के कई रूपों का अनुभव करती हैं।
- प्रेरणा फ्रांस से ली जा सकती है जिसने घोषणा की है कि वह 20,000 होटल बुकिंग के लिए भुगतान करेगी और घरेलू दुरुपयोग से लड़ने वाले संगठनों के साथ–साथ सुपरमार्केट और फार्मेसियों में सहायता बिंदुओं पर €1 मिलियन का योगदान करेगी।
- जमीनी स्तर और महिलाओं के संगठनों और समुदायों को उनकी वर्तमान सीमा रेखा में दृढ़ता से समर्थन करने की आवश्यकता है।
- सामाजिक सहायता का विस्तार करने, और फोन या इंटरनेट का उपयोग न करने वाली महिलाओं तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान जैसे एसएमएस, ऑनलाइन टूल और नेटवर्क का उपयोग करते हुए हेल्पलाइन, साइकोसोशल सपोर्ट और ऑनलाइन काउंसलिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- पुलिस और न्याय सेवाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए जुटना चाहिए कि अपराधियों के लिए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को उच्च प्राथमिकता न दी जाए।
- पुलिस को घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए कॉल का पहला ठिकाना नहीं लगता है और इसलिए, वैकल्पिक व्यवस्था को सक्रिय किया जाना चाहिए।
- सरकार को संकट में महिलाओं की मदद करने के लिए संसाधनों को सुनिश्चित करना चाहिए, और महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सेवाओं की सूची में रखना चाहिए।

खाद्यान्न की कमी का खतरा – यूएन, एफएओ एवं डब्ल्यूटीओ

समाचार –

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन), फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन (एफएओ) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसी वैश्विक एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी कोविड–19 महामारी का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं तो दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है।

भोजन की कमी के कारण –

भोजन की कमी के निम्न कारण हो सकते हैं –

- **लॉकडाउन** – दुनिया भर में कई सरकारों ने अपने यहाँ संपूर्ण आबादी पर लॉकडाउन जारी कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में गंभीर गिरावट आई है।
- **यात्रा प्रतिबंध** – कृषि श्रमिकों की अनुपलब्धता और बाजारों में भोजन प्राप्त करने में असमर्थता के कारण कारावास के आदेश और यात्रा प्रतिबंध कृषि उत्पादन में व्यवधान पैदा करते हैं।
- **खाद्य उपलब्धता** – खाद्य उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता वैश्विक बाजार में कमी पैदा कर सकती है।
- **कमजोर आपूर्ति श्रंखला** – सामाजिक अलगाव के लिए लोगों द्वारा दहशत की खरीद ने पहले ही आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरी का प्रदर्शन किया है।

आगे को राह –

- खाद्य संकट को विकसित होने से बचाने के लिए इस संकट के बीच मुक्त व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।
- जब अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं, तो देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यापार से संबंधित उपाय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित न करें।
- खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा करने की आवश्यकता स्वयं उनकी सुरक्षा करने के अलावा खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने के लिए दोनों के लिए आवश्यक है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बेहतरी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, कोविड–19 के कारण वैश्विक भूख दोगुनी हो सकती है।

- संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के अनुसार, कोविड–19 की आर्थिक गिरावट के कारण तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या इस वर्ष लगभग 265 मिलियन हो सकती है।
- पर्यटन को हुए नुकसान के कारण राजस्व, प्रेषण और यात्रा और कोरोनावायरस महामारी से जुड़े अन्य प्रतिबंधों के प्रभाव से इस वर्ष लगभग 130 मिलियन लोगों को भूख से मरने की आशंका है, जो कि पहले से ही लगभग 135 मिलियन है।
- कोविड–19 संभावित रूप से लाखों लोगों के लिए विनाशकारी है जो पहले से ही एक धागे से लटके हुए हैं।
- खाद्य संकट पर वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट का एक नया संस्करण भी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूडक्रिज द्वारा जारी किया गया है।
- 2019 के अंत में, 55 देशों और क्षेत्रों में 135 मिलियन लोगों ने तीव्र खाद्यान्न का अनुभव किया।
- इसके अतिरिक्त, 2019 में, 183 मिलियन लोगों को कोविड–19 महामारी के समय तीव्र भूख के कारण तनावग्रस्त स्थिति में वर्गीकृत किया गया था।

ऑनलाइन चाइल्ड पोर्न ट्रेफिक में बढोतरी हुई

समाचार –

- चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (ICPF) के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन डेटा मॉनिटरिंग वेबसाइट, पोर्न हब से पता चलता है कि देश में लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सर्च जैसे कि "चाइल्ड पोर्न", "सेक्सी चाईल्ड' एवं 'किशोर (टीन) सेक्स वीडियो', में 95 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- ICPF की स्थापना जनवरी 2020 में की गई थी और इसका उद्देश्य गैर–सरकारी संगठनों को बच्चों के वित्तपोषण के लिए संसाधनों की मदद करना है। इस फंड का प्रबंधन नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के बेटे भुवन रिभु द्वारा किया जाता है।
- यह वृद्धि इंगित करती है कि 'लाखों पीडोफाइल, बाल बलात्कारी और बच्चों की अश्लील साहित्य की लत वाले व्यक्ति ऑनलाइन आ गए है, जिससे बच्चों के लिए इंटरनेट बेहद असुरक्षित हो गया है। कड़ी कार्रवाई के बिना, इससे बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में भारी वृद्धि हो सकती है।

- जब बच्चे लॉकडाउन के दौरान अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं, तो यूरोपोल, संयुक्त राष्ट्र और ईसीपीसीएटी (एंड चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन एंड टीआर) काकिंग) जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने बताया है कि पीडोफाइल और चाइल्ड पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स के बच्चों को 'ग्रुम' करने का लालच देकर उन्हें सोशल मीडिया पर, भावनात्मक संबंध बनाने और फोटो और वीडियो के माध्यम से यौन गतिविधियों को करने के लिए फुसलाते हुए, लक्षित करने की गतिविधि में वृद्धि हुई है।
- 100 शहरों में बाल पोर्नोग्राफी की मांग पर दिसंबर में किए गए एक सर्वेक्षण में, ICPF ने पाया कि औसतन प्रति माह 5 मिलियन डाउनलोड थे। इसमें यह भी बताया गया है कि बच्चों से जुड़ी हिंसक सामग्री की मांग में वृद्धि हुई है।
- यह आरटीआई, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से एक पैन–इंडिया ट्रैकर – जो बाल यौन शोषण सामग्री की मेजबानी, साझा करने, देखने और डाउनलोड करने की निगरानी कर सकता है तथा सरकारी एजेंसियों को जानकारी प्रदान कर सकता है, द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर तत्काल रोक लगाने की मांग करती है।

भारतीय प्रवासी और चुनौतियां

समाचार –

- कोविड–19 लॉकडाउन ने शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवासी श्रमिकों का पलायन हुआ है और उन भारी संख्या में उन भारतीयों को अपने गृहराज्य के बाहर कार्य करते हैं, को सुखियों में ला दिया है।
- लॉकडाऊन अनिवार्य रूप से आर्थिक गतिविधि को सीमित कर देता है परिणामस्वरूप अस्थायी श्रमिकों और दैनिक मजदूरी कमाने वालों के रोजगार समाप्त हो जाते हैं, प्रवासी श्रमिक इस श्रेणी में आते हैं।
- इसके अलावा, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत अप्रैल में केवल 30 लाख लोगों को काम दिया गया था सामान्य रूप से दिए जाने वाले रोजगार का लगभग 17 प्रतिशत था। मध्य अप्रैल में, श्रमिकों की सामान्य संख्या के केवल 1 प्रतिशत को ही रोजगार दिया गया था।
- इस अप्रैल के आंकड़े पांच साल में सबसे कम हैं, और पिछले वर्ष के 1.7 करोड़ श्रमिकों के आंकड़े से इसमें 82 प्रतिशत की गिरावट आई है। कुछ राज्यों में 29 अप्रैल को शून्य कार्यकर्ता थे, जो यह दिखाते हुए कि उन्होंने अपने कार्य फिर से शुरू नहीं किए हैं।
- ऐसे समय में पर्याप्त कार्य प्रदान करने में सरकार की विफलता के आलोक में लॉकडाउन और लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के कारण आजीविका के नुकसान ने भारतीय गांवों में काम की आवश्यकता को बढ़ा दिया है, श्रमिकों को मुआवजा के भुगतान की मांग बढ़ी है।
- श्रम मंत्रालय ने मजदूरी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन्हें फोन नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रमिकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों का समाधान करना है। साथ ही, कर्मचारी ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
- नियंत्रण कक्ष कॉल सेंटर के रूप में कार्य करेगा। उनकी निगरानी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों, सहायक श्रम आयुक्तों और उप मुख्य श्रम आयुक्तों द्वारा की जानी है। केंद्र विभिन्न शहरों जैसे अजमेर, अहमदाबाद, आसनोल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, धनबाद, हैदराबाद, कानपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, रायपुर और पटना में स्थापित किए गए हैं।
- नियंत्रण कक्ष प्रवासी श्रमिकों की मदद करेंगे क्योंकि वे लॉक डाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, 'काम/रोजगार के लिए प्रवासी' श्रेणी के तहत प्रवासी श्रमिकों की संख्या 41.42 मिलियन थी। यह संख्या अब तक काफी बढ़ गई होगी। लॉकडाऊन का असर गरीब और कमजोर समूहों पर बहुत अधिक पड़ा है।

प्रवास के कारण –

- कोविड–19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के चलते शहरी क्षेत्र बंद होने के कारण लाखों प्रवासी कामगार बेरोजगार हो गए।
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरे ओवरफ्लो होने लगे और आपूर्ति कम होने लगी।
- इन प्रवासियों के पास अपने गृहनगर की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
- सरकारें इस मत की हैं कि प्रवासन संकट विशुद्ध रूप कोविड–19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितयों के परिणामस्वरूप है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि ग्रामीण–शहरी प्रवासन की सार्वजनिक समझ में कुछ संरचनात्मक अपर्याप्तताएं हैं।
- चक्राकार प्रवास, आमतौर पर रोजगार के उद्देश्य के लिए घर और मेजबान क्षेत्रों के बीच एक प्रवासी श्रमिक का अस्थायी और आमतौर पर दोहराव वाला गमनागमन होता है।

संरचनात्मक अपर्याप्तता –

- सबसे पहले इन समुदायों के आकार और महत्व को पहचानने में असमर्थता है।
- दूसरा उन प्रवासियों को सही ढंग से गिनने में असमर्थता है, क्योंकि वे अनौपचारिक परिस्थितियों में रहते हैं, तथा वे गांवों और शहरों के बीच यातायात करते रहते हैं।
- इन अक्षमताओं की वास्तविक लागत है, जो महत्वपूर्ण क्षणों में प्रवासी समुदायों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने के लिए सरकारों की खराब तैयारी के रूप में सामने आती है।
- यह कहा जा रहा है कि नीति निर्माता लॉकडाऊन घोषित होने के बाद प्रवासियों के घर लौटने के प्रयास की गति और हताशा का अंदाजा लगाने में असफल रहे।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना है, जिसमें उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी, बिस्तर और आपूर्ति के साथ–साथ आश्रयों द्वारा चलाए जा रहे आवासों में मनोसामाजिक परामर्श प्रदान करना शामिल है, न कि उन पर सुरक्षा बलों का उपयोग करना।

आगे को राह –

- भारत की शहरी आबादी के हिस्से के रूप में चक्रीय प्रवासियों की पहचान। यह अधिकारियों को कम से कम यह विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है कि प्रस्तावित नीतियां इन समुदायों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।
- यदि लॉकडाउन एक मजबूरी है, तो सरकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों की दुर्दशा पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राहत के स्तरों को उठाना आवश्यक है और समाज के उन क्षेत्रों को भी कवर किया जाना चाहिए जो पहले से शामिल नहीं हैं– प्रवासी श्रम, उदाहरण के लिए।
- वे न तो घर जा सकते हैं और न ही रोजगार या आय प्राप्त कर सकते हैं।
- इन श्रमिकों को नकद हस्तांतरण उतना आसान नहीं हो सकता है क्योंकि उनमें से कई में बैंक खाते नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, हमारे पास इन श्रमिकों की रजिस्ट्री नहीं है। कई के पास स्थानीय राशन कार्ड नहीं हो सकते हैं और इसलिए, उन्हें स्थानीय या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है।
- कार्रवाई का सबसे अच्छा कोर्स भोजन और आश्रय को व्यवस्थित तरीके से प्रदान करना है। स्थानीय अधिकारियों को इसे प्राप्त करने के लिए एक तंत्र खोजना होगा। भूख समाज पर एक धब्बा है और इससे किसी वायरस की तरह ही लड़ने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में, इस तरह की पूर्व जागरूकता ने सरकार को यह तय करने की अनुमति दी होगी कि सुरक्षित वापसी को सक्षम करने के लिए दुर्लभ संसाधनों को लक्षित करें या गंतव्य शहरों में प्रवासियों को रखें।
- उन प्रतिबंधों को शिथिल करना जो प्रवासियों को उनके गंतव्य शहरों में खाद्य राशन जैसे महत्वपूर्ण लाभों तक पहुँचने से रोकते हैं। अधिवास केन्द्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से संगठित करने से प्रवासियों को मदद मिल सकती है।
- प्रवासियों के लिए समर्पित परिवहन विकल्पों को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से उच्च तीव्रता वाले प्रवास गलियारों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए।
- विशेष उपायों में प्रवासी महिलाओं की विशेष स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो उन आर्थिक रूप से कमजोर और स्थिति से प्रभावित हैं।
- सरकार का ध्यान दो गुना होना चाहिए। उसे वायरस को नियंत्रित करने के लिए सख्ती से काम करना चाहिए, एक पूर्ण लॉकडाउन के संभावित विकल्पों का पता लगाने और प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। दूसरा, प्रवासी श्रमिकों सहित गरीबों और जरूरतमंदों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए सभी कार्रवाई करनी चाहिए। लॉकडाउन, आवश्यकता के रूप में, एक मानवीय चेहरे के साथ होना चाहिए।
- ऐसे देश में जहाँ कुपोषण व्याप्त है, विशेष रूप से बच्चों में, भूख के व्यापक होने का भी खतरा है। भूख और कुपोषण से भुखमरी को बढ़ावा मिलेगा। टीवी, प्रिंट और सोशल मीडिया कई सबूतों से भरे हुए हैं कि कई परिवार भूखे रह रहे हैं और कुछ भूख से मर रहे हैं।
- हम कभी नहीं जान पाएंगे कि भुखमरी से कितने लोग मारे गए, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार भुखमरी को स्वीकार नहीं करेगी या भुखमरी से मरने वालों की संख्या की गणना नहीं करेगी।

जीआई टैग

समाचार –

- चक–हाओ, मणिपुर के काले चावल, कोविलपट्टिकाडिमलाई और गोरखपुर के टेराकोटा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिला है।
- मणिपुर काला चावल और गोरखपुर टेराकोटा सदियों से प्रचलन में हैं और आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

चक–हाओ

- चक–हाओ, एक सुगंधित लसदार चावल जो सदियों से मणिपुर में उगाया जा रहा है, इसकी विशेष सुगंध इसकी विशेषता है। यह आम तौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान इसे खाया जाता है, इसे चक–हाओ खीर के रूप में परोसा जाता है।
- चक–हाओ का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सकों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के हिस्से के रूप में भी किया गया है। दायर जीआई आवेदन के अनुसार, यह चावल एक रेशेदार चोकर परत और उच्च क्रूड फाइबरेक्स्टेंट की उपस्थिति के कारण इसे पकाने में 40–45 मिनट का लंबा समय लगता है।
- वर्तमान में, मणिपुर की कुछ हिस्सों में चाक–हाओ की खेती की पारंपरिक प्रणाली प्रचलित है। पहले से लदे हुए बीजों की सीधी बुवाई और पौधे वाले खेतों में नर्सरी में उगाए गए चावल के बीजों की रोपाई का व्यापक रूप से राज्य की आद्रभूतियों में अभ्यास किया जाता है।

कोविलपट्टि कदलीमित्तई

- यह कोविलपट्टी और आस–पास के शहरों और गांवों में थूथुकुडी जिले में निर्मित है।
- टैग अब इस ब्रांड को एक अंतरराष्ट्रीय उपभोक्तओं तक पहुंचने में मदद करेगा। इस उत्पाद की एक लंबी शैल्फ लाइफ है और इसमें एक बड़ी निर्यात क्षमता है।
- कोविलपट्टि कदलीमित्तई एक कैंडी है जो मूंगफली से बनी हुई है, जिसे सिरप के साथ मिलाया जाता है, रंगे हुए गुलाबी, हरे और पीले किसे नारियल से सजाया जाता है।
- कोविलपट्टी में, इसे एकल आयताकार विखंडू के रूप में बेचा जाता है, या क्यूबिड्स, पैकेट में सील किया जाता है। यह सभी प्राकृतिक अवयवों जैसे कि पारंपरिक और विशेष 'वेल्लम' (गुड़) और मूंगफली का उपयोग करके बनाया गया है और थामीबरनानी नदी के पानी का उपयोग उत्पादन में किया जाता है, जो स्वाद को बढ़ाता है।
- कोविलपट्टि कदलीमित्तई तमिलनाडु में चुनिंदा विशिष्ट स्थानों से सावधानीपूर्वक चयनित मात्रा में मूंगफली और गुड़ (जैविक गुड़) दोनों का उपयोग करके बनाई जाती है। मूंगफली देशी काली मिट्टी में और कोविलपट्टी के आसपास उगाई जाती है। सोर्सिंग के बाद, मूंगफली को भुना जाता है। इस तरह से इस कोविलपट्टि कदलीमित्तई में एक अद्वितीय पारंपरिक व्यंजन है।
- दशकों से, कोविलपट्टि कदलीमित्तई को पारंपरिक रूप से आस–पास के जिलों से ताड़ के गुड़ और मूंगफली का उपयोग करके ग्रामीण त्योहारों के दौरान तैयार किया गया था। आजादी के पूर्व के युग में, 1940 के आसपास गन्ने के गुड़ का उपयोग शुरू हुआ, जब बाजार में किराने की दुकान रखने वाले पोन्नमलबा नादर ने कदलीमित्तई बनाने के लिए अपने स्टोर में गन्ने के गुड़ और मूंगफली का उपयोग करने का फैसला किया।

गोरखपुर का टेराकोटा कार्य –

- यह एक सदियों पुराना पारंपरिक कला रूप है, जहाँ कुम्हार विभिन्न जानवरों की आकृतियाँ बनाते हैं, जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊँट, बकरी, बैल आदि।
- शिल्प कौशल के कुछ प्रमुख उत्पादों में हौदा हाथी, महावतदार घोड़ा, हिरण, ऊँट, पाँच मुँह वाले गणेश, एकल–सामने वाले गणेश, हाथी की मेज, झाड़, लटकती हुई घंटियाँ शामिल हैं। पूरा काम नंगे हाथों से किया जाता हैं। कारीगर प्राकृतिक रंग, जो लंबे समय तक तेज रहता है का उपयोग करते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा डिजाइन की गई टेराकोटा की 1,000 से अधिक किस्में हैं।
- शिल्पकार मुख्य रूप से औरंगाबाद, भरवलिया, लंगड़ीगुलेरिया, बुधाडीह, अमावा, एकलेत, भटहट और पादरी बाजार, बेलवा रायपुर, जंगल एकला नंबर–1, चरगवां ब्लॉक के गोरखपुर में जंगल एकला नंबर–2। गांवों में फैले हुए हैं।

जीआई टैग क्या है?

- जीआई टैग अनिवार्य रूप से कानून में एक ट्रेडमार्क या बौद्धिक संपदा की तरह काम करता है, जिसमें एक उत्पाद विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, और 'दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता इसके भौगोलिक मूल के कारण होती है'।
- यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) के व्यापार–संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार है।

- जीआई टैग 10 साल की अवधि तक रहता है, और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

जीआई क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- कुछ समुदाय पूरी तरह से अपने स्वदेशी उत्पादों की बाजार की सफलता पर निर्भर करते हैं, और एक जीआई टैग आर्थिक आजीविका की मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है। उत्पाद भी समय के साथ सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान का पर्याय बन जाते हैं, शिल्प कौशल, समुदाय और सभ्यता के इतिहास को मूर्त रूप देते हैं।
- प्रामाणिकता का एक मार्कर यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कारीगरों, रसोइयों, किसानों, और अन्य पेशेवरों की पीढ़ियों के हितों और प्रयासों को प्रतिस्पर्धी कीमतों और कारखाने प्रक्रियाओं से प्रोत्साहित और सुरक्षित रखा गया है।
- जीआई टैग बिक्री और निर्यात को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उत्पादन और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की आधिकारिक मान्यता पर मांग बढ़ने से विरासत बनती है।
- दार्जिलिंग चाय 'भारत का पहला जीआई–टैग वाला उत्पाद था, जिसने 2004– 2005 में इसका लेबल हासिल किया।

अंबेडकर जयंती

समाचार –

- डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है।

विवरण –

- भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में हुआ था। वह रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरबादकर की 14 वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार हिंदू म्हार जाति का था और उन्हें अछूत माना जाता था।
- उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे।
- भारत की संविधान सभा ने उन्हें 29 अगस्त 1947 को अपने नए संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। लाखों भारतीय टीम के सदस्य उन्हें 'बाबासाहेब' के रूप में मानते थे।
- डॉ. अम्बेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद्, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद्, विद्वान और तुलनात्मक धर्मों के विचारक थे।
- उन्होंने उन महान हिंदुओं के खिलाफ 1927 में महा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो नगरपालिका के फैसले का विरोध कर रहे थे।
- 1926 में, म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ महद (महाराष्ट्र) ने सभी समुदायों के लिए खुले टैंक को फेंकने का आदेश पारित किया। इससे पहले, अछूतों को महादटन के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।
- उन्होंने सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया।
- 1932 में, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने पिछड़े वर्गों (सांप्रदायिक पुरस्कार) के लिए अलग निर्वाचकों के विचार को छोड़ दिया।
- हालांकि, अवसादग्रस्त वर्गों के लिए आरक्षित सीटें प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल का 18 प्रतिशत थी।
- हिल्टन यंग कमीशन के सामने उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नींव के रूप में कार्य किया।
- 1936 में, वे एक विधायक (MLA) के रूप में बॉम्बे विधान सभा के लिए चुने गए।
- उन्हें 1942 में एक कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था।
- 1947 में, डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए पीएम नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया।
- उन्होंने हिंदू कोडबिल पर मतभेदों को लेकर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
- अंबेडकर ने बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, थांथी पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर, नारायण गुरु, रबीदास और छत्रपति शाहू महाराज के कार्यों और शिक्षाओं से प्रेरित होकर, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा के आधार पर हिंदू धर्म की स्थापना के लिए हिंदू धर्म की पुरानी प्रथाओं के खिलाफ सामाजिक सुधार आंदोलनों का आयोजन किया।
- वे एकमात्र नेता थे जो जनवरी 1919 से 1946 से शुरू होने वाले औपनिवेशिक भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे।
- जीवन के उतरार्द्ध में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। चैत्यभूमि मुंबई में स्थित बी. आर. अम्बेड़कर का स्मारक है।

पुस्तकें
a) जाति का विनाश
b) बुद्ध या कार्ल मार्क्स
c) अछूत – वे कौन हैं और वे अछूत क्यों बन गए हैं
d) बुद्ध और उनके धम्म
e) हिंदू महिलाओं का उदय और पतन

पत्रिकाओं
a) मूकनायक (1920)
b) बहिष्कृत भारत (1927)
c) समता (1929)
d) जनता (1930)

संगठन
a) बहिश्तिक हितकारिणी सभा (1923)
b) स्वतंत्र लेबर पार्टी (1936)
c) अनुसूचित जाति महासंघ (1942)

सामान्य अध्ययन II
(शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) एवं वेतन में कटौती

समाचार –
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MPLAD योजना को दो साल के निलंबन को मंजूरी दे दी है, ताकि बचाई गई राशि (7900 करोड़ रुपये) भारत के समेकित कोष में खर्च किया जा सके, जिसे महामारी कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर खर्च किया जा सकता है।
- इस संबंध में, इसने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद सहित सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी।
- भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ–साथ सभी राज्य राज्यपालों ने भी 30 प्रतिशत वेतन कटौती का फैसला किया है।
- हालांकि, संशोधन केवल सांसदों के वेतन में कटौती करेगा, पूर्व सांसदों के पेंशन और भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी।

MPLAD योजना
- इसे दिसंबर 1993 में शुरू किया गया था, ताकि संसद सदस्यों के लिए टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए विकासात्मक प्रकृति के कामों की सिफारिश करने और स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर सामुदायिक बुनियादी सुविधाओं सहित बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान किए जा सके।
- यह शुरू में ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में था। बाद में, अक्टूबर 1994 में, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
- MPLADS भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक योजना है। निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक MPLADS फंड पात्रता प्रति सांसद 5 करोड़ रूपये हैं।

विश्लेषण –
- कोविड–19 के लिए उपलब्ध धनराशि को बढ़ावा देने के लिए MPLADS को दो साल का निलंबन सही दिशा में एक कदम है।
- पहली नजर में ऐसा प्रतित हो सकता है कि निर्णय स्थानीय वित्त पोषण के विकेंद्रीकृत तरीके को कमजोर कर सकता है। हालाँकि, पिछला अनुभव यह रहा है कि कुछ सदस्य अपने पूर्ण अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं और इस योजना के तहत प्रशासन द्वारा सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश और कार्यान्वयन के बीच एक अंतर है।
- MPLADS के बारे में यह दूसरी घोषणा है जो केंद्र ने बीमारी के प्रकोप के बाद की है। पिछले महीने, इसने प्रत्येक सांसद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए कम से कम रूपये 5 लाख तक की सीमा तक MPLADS धन के उपयोग की अनुमति दी।
- कई सदस्यों ने N95 मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, और वेंटिलेटर की खरीद की सिफारिश करने के लिए एक बार के डिस्पेंशन का तत्काल उपयोग किया।
- अब जब पूरी योजना को निलंबित कर दिया गया है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले से की गई सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जबकि भारत के समेकित कोष में इन रकमों के हस्तांतरण से देश में कहीं भी विवेकपूर्ण तैनाती में मदद मिलेगीं।

- इसे यह भी देखना चाहिए कि आवंटन गैर–भेदभावपूर्ण तो नही हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि निलंबन पर काफी नाराजगी है – 5 करोड़ रूपये प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध है चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए बहुत सद्भावना का स्रोत है।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले सांसद पहचान करते हैं और सहानुभूति और सतर्कता के साथ स्थानीय विकास की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। हालाँकि, योजना की प्रकृति की काफी आलोचना भी होती है।
- विशेषज्ञों द्वारा योजना में बताई गई एक वैचारिक कमजोरी यह है कि यह शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है। यह व्यक्तिगत विधायकों को प्रशासन के नियोजन और कार्यान्वयन कर्तव्यों का अतिक्रमण करने की अनुमति देता है। न्यायविदों ने इंगित किया है कि संविधान एक व्यक्ति विधायक पर सार्वजनिक धन खर्च करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द करने का फैसला करते हुए एक मजबूत जवाबदेही व्यवस्था का आह्वान किया है।
- MPLADS सांसदों को पैसों के संरक्षण के रूप में उपयोग करने की गुंजाइश देता है जो वे अपनी इच्छा के अनुसार वितरित कर सकते हैं। MPLADS , सांसदो को वित्तीय कुप्रबंधन के उदाहरणों से भरी पड़ी है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसे पूरी तरह से निरस्त करने की सिफारिश की। योजना की पुनरावृत्ति की समग्रता में कुछ हद तक एकांतरता की गुंजाइश है।

केरल और कर्नाटक के बीच राजमार्ग युद्ध

समाचार –

- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कर्नाटक और केरल के बीच अंतर–राज्यीय सीमा पर आवश्यक चिकित्सा उपचार के लिए रोगियों के पारित होने के लिए सीमा सड़कों की नाकाबंदी उठाने पर कर्नाटक और केरल के बीच समझौता हुआ है।
- इससे पहले, केरल सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि कर्नाटक कोरोनोवायरस के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और सीमा मार्गों को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे लोगों के चिकित्सा उपचार और आवश्यक सामानों की आवाजाही को रोका जा सके, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अलगाव हुआ।
- केरल ने कहा कि केंद्र सरकार, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है, का कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को निर्देश जारी करने के लिए बाध्य हो ताकि चिकित्सा की आवश्यकता वाले रोगियों के साथ–साथ केरल तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए ऐसी नाकाबंदी को हटाया जा सके।
- कोविड–19 के प्रकोप ने 'राजमार्ग के अधिकार' पर एक अंतरराज्यीय विवाद को जन्म दिया है। इससे पहले, केरल में मामलों के तेजी से बढ़ने पर चिंता के साथ, पड़ोसी कर्नाटक ने दक्षिण कन्नड़, कोडागु और मैसूरु जिलों में सभी सड़कों को बंद कर दिया था।
- इसके बाद, केरल उच्च न्यायालय ने कर्नाटक को प्रतिबंध हटाने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया क्योंकि यह संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। राज्य सरकारें राजमार्ग बंद करने का फैसला नहीं कर सकती हैं।
- बदले में, कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।
- सड़कों के बंद होने से दोनों राज्यों के बीच सामाजिक संबंध प्रभावित होंगे। उच्चतम न्यायालय बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें सड़कों को खोलने का निर्देश दिया गया था ताकि कासरगोड के मरीज मंगलुरु में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की सुविधा हासिल कर सकें। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक के सीमावर्ती केरल के जिलों के बारे में यह माना जाता है कि वहाँ स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे अविकसित है।
- सामान्य समय में, मंगलुरु केरल के कासरगोड और कन्नूर के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है, क्योंकि इसमें कई बार, पब और जीवंत नाइटलाइफ हैं। सप्ताहांत के दौरान केरल के युवा भी अक्सर मंगलुरु जाते हैं। केरल के निवेशकों ने यहां अस्पताल, स्कूल और होटल भी बनाए हैं।
- उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में, कर्नाटक ने तर्क दिया कि सड़कों के खुलने से कानून–व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्थानीय निवासी कासरगोड के लोगों से सावधान रहते हैं, यह देखते हुए कि जिले में देश के सबसे ज्यादा कोविड–19 मामले हैं।

केरल उच्च न्यायालय का आदेश

- केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया था कि कर्नाटक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाई जाने वाली नाकेबंदी को हटा दिया जाए।

- दो राज्यों के बीच तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए लोगों को ले जाने वाले वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा की जाए।
- केरल उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मंगलौर से कासरगोड को जोड़ने वाली धमनी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा बनाए। इसलिए, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि सड़कें नाकाबंदी मुक्त हों।
- स्वास्थ्य सेवाओं का खंडन अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए होता है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकार को भी प्रभावित करता है।

न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार –

- उच्च न्यायालय के सामने, कर्नाटक ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय कोई निर्देश जारी करता है तो यह न्यायालय के अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे होगा।
- लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर लिया और कहा कि जब किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी अन्य राज्य की सरकार की कार्रवाइयों को अवैध और असंवैधानिक पाता है और घोषित करता है, तो उक्त राज्य सरकार कानून की उक्त घोषणा को स्थगित करने के लिए बाध्य होगी, इस बात की परवाह किए बिना कि उक्त न्यायालय उक्त राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं से परे स्थित है।
- न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक सरकार के तर्क की, वह 'किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वह उसकी क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर रहता है', को नही माना जा सकता।

विधान परिषद के चुनाव

समाचार –

- नौ रिक्त महाराष्ट्र विधान परिषद सीटों के चुनाव 21 मई 2020 को होंगे।
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 2019 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उनके पद को बनाए रखने के लिए विधायिका का सदस्य बनने के लिए 27 मई 2020 की समयसीमा है। विधायिका का सदस्य बनने के लिए छह महीने की खिड़की 28 मई 2020 को समाप्त होती है।
- 3 अप्रैल 2020 को, भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र और बिहार विधान परिषदों में से प्रत्येक में नौ रिक्त सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिए।
- इससे पहले, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से सिफारिश की थी कि मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के उम्मीदवार के लिए आरक्षित सीटों में से एक के लिए नामित किया जाना चाहिए – तब भी जब कि मुख्यमंत्री का पद कार्यकाल समाप्ति की ओर हो।
- महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्य की विधान परिषद के लिए चुने नहीं जाने पर अपनी सीट हार सकते हैं। लेकिन, उसे राज्य विधान सभा के किसी भी सदन में निर्वाचित होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 (4) में ऐसे प्रावधान है।

संविधान के प्रावधान

- अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, 'एक मंत्री जो लगातार छह महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री बनने के लिए अयोग्य होगा', अतः आवश्यकता को पूरा करने का एकमात्र तरीका, राज्यपाल द्वारा उच्च सदन में मुख्यमंत्री को नामित किया जाना है।
- एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2001), सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि "संविधान किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, को स्वयं चुने जाए बिना बार–बार छह लगातार महीनों के कार्यकाल के लिए मंत्री नियुक्त करने की अनुमति नही देगा, यह संवैधानिक योजना के अनुचित, अलोकतांत्रिक और अमान्य है।

नामांकन मार्ग

- ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है, सरकार का मुख्य कार्यकारी बन जाता है, अपने आप में काफी सामान्य है। एचडी देवगौड़ा तब संसद सदस्य नहीं थे जब उन्हें जून 1996 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।
- गैर–सदस्य मंत्रियों के लिए नामांकन मार्ग कम सामान्य है – लेकिन असंवैधानिक नहीं है। 1952 में, सी राजगोपालाचारी को राज्यपाल द्वारा मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था।
- अनुच्छेद 171 (5) के तहत, राज्यपाल 'साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं'।

- इससे पहले, राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत किया, भले ही उनके पास इन निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने के बारे में संदेह था, और हरशरण वर्मा बनाम के चंद्र बोस गुप्ता और अन्य (15 फरवरी, 1961) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार, यहां तक कि राजनीति को भी 'समाज सेवा' के रूप में देखा जा सकता है, का निर्णय आया था।

राज्यपाल की भूमिका –

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 ए, रिक्ति को भरने से रोकती है यदि 'रिक्ति के संबंध में सदस्य के कार्यकाल का शेष एक वर्ष से कम है'। हालांकि, यह राज्यपाल के लिए नामांकन को अस्वीकार करने का एक कारण नहीं हो सकता है – क्योंकि बार एक उपचुनाव को भरने के लिए उपचुनाव के संबंध में है, नामांकन नहीं। बेशक, राज्यपाल यह तर्क दे सकते हैं कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर तेजी से कार्य करने के लिए संविधान के तहत बाध्य नहीं हैं तथा उसे क्यों नामांकित किया जाना चाहिए।

नामांकन में राज्यपाल के विवेक की सीमाएं क्या हैं?

- बमन चंद्र बोस बनाम डीआर एच सी मुखर्जी (1952) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि विधायिका के नौ नामित सदस्यों में से कोई भी आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, और यह माना कि राज्यपाल परिषद में सदस्यों को नामित करने में अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकते। उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से जाना होगा।
- संविधान का अनुच्छेद 163 (1) यह स्पष्ट करता है कि राज्यपाल को सभी परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सिफारिशों का पालन करना चाहिए 'सिवाय इसके कि वह इस संविधान के तहत या अपने कार्यों या उनमें से किसी में भी उसका विवेक आवश्यक है।'
- यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्यपाल अनुच्छेद 162 में परिभाषित किए गए कार्यकारी मामलों में केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं (वे 'जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है') – और नामांकन के बाद से सदस्यों की एक कार्यकारी शक्ति नहीं है, वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है।
- हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 169 के तहत, जबकि संसद को एक विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति है, यह राज्य विधानसभा द्वारा उस आशय का प्रस्ताव पारित करने के बाद ही ऐसा कानून पारित कर सकता है। इस प्रकार, विधानसभा की विधायी शक्ति को इस प्रावधान से निकाला जा सकता है।
- साथ ही, संविधान उन स्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख करता है जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं, जैसे, अनुच्छेद 239 (केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन), अनुच्छेद 371 (महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान), अनुच्छेद 371 ए (नागालैंड)), अनुच्छेद 371 एच (अरुणाचल प्रदेश), और छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में प्रावधान), आदि।
- राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने में एक सामान्य विवेक होता है, लेकिन इस तरह के विवेक के अभ्यास को नियंत्रित करने वाले अच्छी तरह से स्थापित परंपराएं हैं। यहां तक कि राज्यपाल की क्षमा शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है (मारू राम बनाम भारत संघ, 1980)।
- हरगोविंद पंत बनाम डॉ. रघुकुल तिलक एंड ऑर्म्स (1979) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है। वह न तो इसके नियंत्रण में है और न ही इसके प्रति जवाबदेह है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है।

पालघर लिंचिंग

समाचार –

- 16 अप्रैल 2020 को, महाराष्ट्र के पालघर जिले में तीन लोगों को कथित तौर पर बाल–अपहरणकर्ता और अंग हार्वेस्टर होने का संदेह होने पर भीड़ द्वारा मार दिया गया। तीनों सूरत में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, जब पालघर के एक दूरदराज के एक आदिवासी गांव गडचिंचल में ग्रामीणों के एक समूह ने उनकी कार को रोका और उन पर पत्थर, लॉग और कुल्हाड़ियों से हमला किया।
- यह घटना आदिवासी बहुल पालघर जिले के दहानुतालुका में स्थित गडचिंचल गांव में हुई, जो मुंबई से 140 किलोमीटर उत्तर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार, गांव की आबादी 1,298 निवासियों की है, जिनमें से 93 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं।

लिंचिंग और भारत में इसकी स्थिति

- लिंचिंग एक समूह द्वारा पूर्व–निर्धारित गैरकानूनी हत्या है। इसका उपयोग अक्सर एक कथित दोषी को दंडित करने या एक समूह को धमकाने के लिए एक भीड़ द्वारा अनौपचारिक सार्वजनिक निष्पादन की विशेषता से किया जाता है।
- यह अनौपचारिक समूह के सामाजिक नियंत्रण का एक चरम रूप भी हो सकता है, और यह अक्सर अधिकतम डराने के लिए सार्वजनिक तमाशे (अक्सर फांसी के रूप में) के प्रदर्शन के साथ भी आयोजित किया जाता है।
- भारत में, लिंचिंग जातीय समुदायों के बीच आंतरिक तनाव को दर्शाता है। समुदाय कभी–कभी आरोपियों या संदिग्ध दोषियों को दोषी ठहराते हैं।
- 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को 'भीड़तंत्र के भयानक कार्य' के रूप में वर्णित किया। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष रूप से लिंचिंग के अपराध से निपटने के लिए कानूनों को फ्रेम करने के लिए प्रेरित किया और इन कानूनों में फास्ट ट्रैक ट्रायल, पीड़ितों को मुआवजा और लक्स कानून के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित कुछ दिशानिर्देशों को शामिल किया।
- निस्संदेह मॉब लिंचिंग भारत के अवधारणा के सार के खिलाफ है। इसलिए, भीड़ को रोकने के लिए प्रयास करना होगा। इस दृष्टि से, भीड़ को रोकने के लिए एक केंद्रीय नीति आवश्यक है। इसे रोककर भारत को अपनी लोकतांत्रिक नीति का पालन करना होगा।

- मणिपुर सरकार ने 2018 में लिंचिंग के खिलाफ पहला बिल पेश किया, जिसमें कुछ तार्किक और प्रासंगिक धाराएं शामिल हैं। विधेयक ने निर्दिष्ट किया कि ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी होंगे।
- पुलिस अधिकारी जो अपने अधिकार क्षेत्र में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहते हैं, उन्हें एक से तीन वर्ष तक के कारावास या 50,000 रूपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की किसी भी तरह की सहमति के लिए उन पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है।
- यह राज्य की हिंसा के शिकार लोगों और गवाहों को किसी भी उत्पीड़न या जबरदस्ती से बचाने के अलावा पुनर्वास के लिए योजनाएँ शुरू करने और राहत शिविर स्थापित करने के लिए समर्पित करता है जहाँ एक समुदाय विस्थापित होता है।
- कानून पीड़ितों या उनके तत्काल परिजनों को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा प्रदान करता है।

NEET अल्पसंख्यक–संचालित मेडिकल कॉलेजों के लिए आवश्यक है – उच्चतम न्यायालय

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो कॉलेज धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाए जाते हैं में मेडिकल में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (NEET) अनिवार्य है।
- स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए केवल NEET के माध्यम से प्रवेश अल्पसंख्यकों के किसी भी मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
- NEET अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए लागू होगा।
- कुछ ने यह कहकर इसका विरोध किया कि इससे 'व्यापार और व्यवसाय' के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
- NEET को लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, अपने संस्थानों का प्रशासन करने इत्यादि का का उल्लंघन करेगा।
- उन्होंने कहा कि राज्य अल्पसंख्यकों के हित में कार्य करने के लिए अपने दायित्व निभा रहे हैं।

फैसले की मुख्य विशेषताएं –

- अदालत ने माना कि व्यवसाय और व्यवसाय या धार्मिक अधिकारों के अधिकार 'प्रवेश के मामले में पारदर्शिता और योग्यता की मान्यता हासिल करने के तरीके में नहीं आते हैं'।
- शैक्षणिक मानकों का विनियमन और शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतिबंध लगाना राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में था।
- व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है। यह योग्यता, उत्कृष्टता की मान्यता को बढ़ावा देने और कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए छात्रों के समुदाय के हित में उचित प्रतिबंध के अधीन है।
- एक समान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता के परीक्षण को उत्तीर्ण करती है और उचित है।
- अदालत ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान कानून के तहत लागू शर्तों का पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य हैं।
- NEET के माध्यम से प्रवेश सहित विनियम, न तो विभाजनकारी है और न ही विघटनकारी वरन् वे आवश्यक हैं।

- एक जैसी प्रवेश परीक्षा भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करेगी ताकि संविधान में निहित निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में योग्यता को प्रोत्साहित किया जा सके।

संवैधानिक प्रावधान –

- अनुच्छेद 30 (1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है लेकिन नस्ल, जातीयता के आधार पर नहीं।
- यह शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को मान्यता देता है।
- यह विभिन्न संस्कृति के संरक्षण में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका को मान्यता देता है।
- एक बहुसंख्यक समुदाय भी शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकता है लेकिन उन्हें अनुच्छेद 30 (1) (ए) के तहत विशेष अधिकारों का आनंद नहीं मिलेगा।
- अनुच्छेद 15 (5) के तहत, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) को आरक्षित नहीं माना जा सकता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, MEI को समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत नामांकन तक 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- सेंट स्टीफेंस बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय मामले में, 1992, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि MEI में अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो सकती हैं।
- टी एम ए पाई और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, 2002 के मामले में, उच्चतम न्यायायल ने फैसला सुनाया कि MEI में अलग–अलग प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित है।
- वे शुल्क संरचना को भी अलग कर सकते हैं लेकिन कैपिटेशन शुल्क नहीं लेना चाहिए।

अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पूर्ति पर रोक

समाचार –

- यूएसए ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर वायरस के मुद्दे में पारदर्शिता के लिए चीन की प्रशंसा करने का आरोप लगाकर इसके वित्तपोषण को रोक दिया है।
- हालांकि, यूएसए अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता राष्ट्र रहा है जो कुल धन का 14.67 प्रतिशत अर्थात लगभग $553.1 मिलियन प्रदान करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और वित्तपोषण –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- 26 मार्च 2020 को, कोविड–19 से निपटने के लिए वर्चुअल जी–20 शिखर सम्मेलन में, भारत के पीएम ने विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर–सरकारी संगठनों को मजबूत करने और सुधारने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड–19 प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं में समय–समय पर सलाह दी जाती है।
- यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कोविड–19 के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें निम्न कार्य शामिल हैं –
  - निगरानी और संपर्क अनुरेखण।
  - प्रयोगशाला और अनुसंधान प्रोटोकॉल।
  - जोखिम संचार।
  - अस्पताल की तैयारी।
  - संक्रमण की रोकथाम पर प्रशिक्षण।
  - नियंत्रण और क्लस्टर नियंत्रण योजना।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन वित्तपोषण चार तरिकों से किया जाता है –
  a) **स्वीकृत योगदान** – ये संगठन के सदस्य होने के लिए बकाया राशि का भुगतान करते हैं।

प्रत्येक सदस्य राज्य को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना देश की धन और जनसंख्या के सापेक्ष की जाती है। हाल के वर्षों में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मूल्यांकित योगदान में गिरावट आई है। यह अब इसके वित्तपोषण के एक–चौथाई से भी कम हिस्सा है। ये फंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे एक स्तर पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और संकीर्ण दाता आधार पर निर्भरता को कम करते हैं।

b) **निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान** – वे सदस्य राज्यों (उनके मूल्यांकन योगदान के अलावा) या अन्य भागीदारों से आते हैं।

c) **कोर स्वैच्छिक योगदान** – वे संसाधनों के बेहतर प्रवाह एवं जब तत्काल वित्तपोषण की कमी होती है तब आने वाली अड़चनों को हल करने में कम वित्तपोषण वाली गतिविधियों को हल करने मदद करते हैं।

d) **महामारी इन्फ्लुएंजा की तैयारी (पीआईपी) योगदान** – इनकी शुरुआत 2011 में विकासशील देशों की वैक्सीन और अन्य महामारी संबंधी आपूर्ति की पहुँच बढ़ाने के लिए की गई थी।

ऐसे उदाहरण जहां भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन क निर्णय से असहमत रहा–

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को यात्रा प्रतिबंधों की सिफारिश नहीं की। ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम आपात समिति द्वारा 30 जनवरी 2020 को नियंत्रण, निगरानी, पहचान, अलगाव और यहां तक कि संपर्क ट्रेसिंग की आवश्यकता पर एक वैश्विक अलर्ट जुटाने के बावजूद हुआ।
- लेकिन, चीन की गैर–आवश्यक यात्रा से बचने के लिए भारत की पहली सलाह 25 जनवरी 2020 को जारी की गई थी।
- 16 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य संदेश 'परीक्षण परीक्षण परीक्षण ....'(अंधाधुंध परीक्षण) था।
- लेकिन 22 मार्च को, ICMR ने कहा कि कोई भी अंधाधुंध परीक्षण नही होगा और केवल अलगाव रखा जाएगा।
- घंटे बाद, भारत लॉकडाउन में चला गया, 75 जिलों और फिर 24 मार्च की आधी रात से पूरे देश में शुरू हुआ।
- निर्णय ICMR द्वारा एक कागज पर आधारित था कि संगरोध (क्वारंटाईन) हवाई अड्डे स्क्रीनिंग की तुलना में वायरस युक्त का एक अधिक प्रभावी तरीका है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के नैदानिक देखभाल दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रोगियों के लिए किसी भी विशिष्ट एंटी–कोविड–19 उपचार की सिफारिश उपलब्ध नहीं है।
- भारत, हालांकि, नए कोरोनवायरस वायरस के रोगियों के लिए अपने नैदानिक देखभाल दिशानिर्देशों में, पहले अपने दो एरियल एंटीवायरल – लोपिनवीर और रेटनवीर के साथ सामने आया।
- बाद में इसने हाइड्रोविक्लोरोक्वाइन और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के संयोजन के साथ एंटीवायरल को बदलने के लिए प्रबंधन दिशानिर्देशों को संशोधित किया।
- इसकी, हालांकि, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सर्मथित एक वैश्विक दवा परीक्षण के रूप में घोषणा की जा चुकी है।

अमेरिका द्वारा आव्रजन आदेश

समाचार –

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ग्रीन कार्ड की मंजूरी को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
- निलंबबन, जिसमें कई छूट हैं, 60 दिनों तक चलना है और फिर इसे बढ़ाया जा सकता है।
- आदेश को कोरोनोवायरस द्वारा खतरे में पड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिकी श्रमिकों की नौकरियों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
- कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच 20 मिलियन से अधिक अमेरिकियों ने अपनी नौकरी खो दी है।
- अमेरिका ने कहा है कि सरकार का 'कर्तव्य' है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे फिर से काम करें।
- जो लोग देश में हैं और अपने आव्रजन की स्थिति को बदलने की मांग कर रहे हैं, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
- नीति 'पूरे देश में परिवारों और नियोक्ताओं के लिए वास्तविक दर्द का कारण बनेगी'।
- अमेरिका के इस कदम के कानूनी चुनौतियों का सामना करने की संभावना है।

किन्हें इन निलंबनों से छुट मिलेगी?

- यह उपाय ग्रीन कार्ड धारकों के स्थायी अमेरिकी निवास के लिए उनके विस्तारित परिवारों को प्रायोजित करने के अभ्यास को रोकने के लिए अपेक्षित है। राष्ट्रपति ट्रम्प इसे चेन माइग्रेशन कहते हैं।

- ग्रीन कार्ड अप्रवासियों को कानूनी स्थायी निवास और अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अवसर देते हैं।
- लेकिन यह 21 वर्ष से कम आयु के अमेरिकी नागरिकों के पति/पत्नी और अविवाहित बच्चों के लिए एक अपवाद होता है।
- यह आदेश विविधता वीजा लॉटरी को भी निलंबित करता है, जो सालाना 50,000 ग्रीन कार्ड जारी करता है।
- यह छूट भी अमेरिका में पहले से ही रह रहे और काम कर रहे सैकड़ों हजारों ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए है।
- ये लोग डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के रूप में काम करने के लिए प्रवेश की मांग कर रहे हैं।
- एक अन्य अपवाद एच–1 बी वीजा कार्यक्रम में ऐसे आवेदकों को खेत मजदूरों और कुशल श्रमिकों के रूप में हर साल जारी किए गए हजारों–हजारों अस्थायी अतिथि वीजा हैं।

भारतीय नागरिकों पर क्या असर होगा?

- स्थायी निवास की स्थिति वाले या ग्रीन कार्ड वाले लोग जो अमेरिका से बाहर हैं उन्हें वापस आने में सक्षम होना चाहिए। अमेरिका में उनके प्रवेश को रोकना असंवैधानिक होगा।
- कार्यकारी आदेश ग्रीन कार्ड धारकों के अलावा अन्य भारतीयों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, जिन्हें अभी तक गैर–आप्रवासी वीजा या अप्रवासी वीजा प्राप्त करना है।
- पहले से ही एक गैर–आप्रवासी स्थिति पर अमेरिका में लोग संभवतः तब तक प्रभावित नहीं होंगे जब तक वे विदेश यात्रा नहीं करते हैं और यूएस में रहते हुए भी स्थिति का विस्तार और परिवर्तन करने में सक्षम हो सकते हैं।
- वर्तमान आदेश भारतीय आईटी कंपनियों को प्रभावित नहीं करता है जो एच–1 बी और एल 1 वीजा का उपयोग करके अत्यधिक कुशल श्रमिकों को अमेरिका में स्थानांतरित करते हैं।
- पर्यटन पर, वर्तमान समय में इस बात पर थोड़ी चिंता है कि भारत ने कोरोनोवायरस फैलने के जोखिमों के कारण वाणिज्यिक उड़ानों को रोक दिया है।
- दुनिया भर में कई एयरलाइनों ने भी परिचालन को निलंबित कर दिया है।
- इसके अलावा, कई देशों में, संगरोध प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर लागू होती है। यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा से कई आगंतुकों को निराश करेगा।
- अंत में, अमेरिकी विदेश विभाग ने मार्च 2020 में घोषणा की कि वह विदेश में अपने वाणिज्य दूतावासों और दूतावासों में सभी नियमित वीजा प्रसंस्करण को निलंबित कर देगा।
- इससे न केवल वीजा जारी करने की गति में कमी आई है, बल्कि इसने कानूनी आव्रजन को भी काफी धीमा कर दिया है।
- एक तुलनित्र के रूप में, पिछले साल विदेश में अमेरिकी राजनयिक मिशनों में 9.2 मिलियन से अधिक वीजा जारी किए गए थे।
- जब अमेरिका और भारत में महामारी के सबसे बुरे चरण बीत चुके हैं, तो वायुमार्ग की बहाली हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के पास एक बार फिर से अमेरिका की यात्रा करने का विकल्प हो सकता है। वर्तमान में, ऐसी स्थितियाँ सामने आने की कोई दृश्यता नहीं है।
- अब तक H-1B वीजा प्राप्त करने वाले कुशल श्रमिकों का संबंध है, ऐसी ही स्थिति लागू होती है।
- भारत में ही नहीं, सभी देशों में अमेरिकी वीजा जारी करने का काम रुक गया है।
- इसने भारत में कई एच –1 बी वीजा चाहने वालों को निराश कर दिया है।
- यह भारतीय आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (ITeS) क्षेत्रों पर आर्थिक रूप से दुर्बल प्रभाव डाल सकता है। हालाँकि, यह महामारी के समग्र प्रभाव से अधिक है, और श्री ट्रम्प के आव्रजन प्रतिबंध से नहीं।

भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों को कड़ा किया

समाचार –

- भारत ने हाल ही में अपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को संशोधित किया है, जो कोविड–19 प्रकोप से प्रेरित लॉकडाउन द्वारा प्रभावित फर्मों के 'अवसरवादी अधिग्रहण' को रोकने के उद्देश्य से किया गया है।
- इस कदम ने चीन को परेशान किया है, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है।
- सरकार ने कहा कि पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों को पहले इसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी।

- एक देश जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है, अब यहां 'केवल सरकारी मार्ग के तहत' फर्मों में निवेश कर सकती है।
- यह 'लाभकारी' मालिकों पर भी लागू होता है – भले ही निवेश कंपनी पड़ोसी देश में स्थित न हो या यदि इसका मालिक एक नागरिक या ऐसे देश का निवासी है।
- इस संदर्भ में वर्तमान में किसी भी देश का नाम नहीं था, विश्लेषकों ने संशोधन को संभव चीनी निवेश के परिप्रेक्ष्य में देखा है।
- यह फैसला चीन के केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) द्वारा HDFC में अपनी हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से अधिक करने के कुछ दिनों बाद हुआ।
- चीन का एफडीआई 2014 से दिसंबर 2019 तक पांच गुना बढ़ गया है।
- भारत में इसका संचयी निवेश $ 8 बिलियन से अधिक हो गया। यह भारत के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य देशों के निवेश से कहीं अधिक है।

चीन की प्रतिक्रिया –

- चीन ने भारत से इन 'भेदभावपूर्ण प्रथाओं' को संशोधित करने का आह्वान किया है। चीन ने भारत को विभिन्न देशों के निवेश के प्रति समान व्यवहार करने के लिए भी कहा है।
- विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए भारतीय पक्ष द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अवरोध डब्ल्यूटीओ के गैर–भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।
- यह व्यापार और निवेश की उदारीकरण और सुविधा की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ है।
- भारत ने एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर–भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, पूर्वानुमान और स्थिर व्यापार और निवेश वातावरण का एहसास करने के लिए जी 20 नेताओं और व्यापार मंत्रियों की आम सहमति के अनुरूप नहीं था।

भारत का तर्क –

- भारत का कहना है कि नीति किसी एक देश के उद्देश्य से नहीं है और यह कदम भारतीय कंपनियों के 'अवसरवादी' अधिग्रहण को रोकने के उद्देश्य से है, जिनमें से कई तनाव में हैं।
- संशोधन निवेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं। भारत ने इन निवेशों के लिए अनुमोदन मार्ग को बदल दिया है। भारत में कई क्षेत्र हैं जो पहले से ही इस अनुमोदन मार्ग के अधीन हैं।
- कई अन्य देश भी ऐसे उपाय कर रहे हैं।

अन्य देशों ने क्या किया है? –

- भारत से पहले, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह के उपायों की शुरुआत की थी।
- ये, फिर से, चीनी निवेश पर लक्षित होने के रूप में देखे गए। मार्च 2020 में, यूरोपीय आयोग ने दिशानिर्देश जारी किए।
- दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि ऐसे समय में विदेशी निवेश स्क्रीनिंग के लिए एक मजबूत 'यूरोपीय संघ व्यापक दृष्टिकोण' हो।
- इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ की कंपनियों और महत्वपूर्ण संपत्तियों को संरक्षित करना था, विशेष रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में।
- यह विदेशी निवेश के लिए यूरोपीय संघ के सामान्य खुलेपन को कम किए बिना संरक्षण सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए था।
- ऑस्ट्रेलिया ने अस्थायी रूप से विदेशी अधिग्रहणों पर नियम कड़े कर दिए हैं। ऐसा इस चिंता से अधिक था कि रणनीतिक परिसंपत्तियों को सस्ते में बेचा जा सकता है।
- इसने चेतावनी के बाद ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को विमानन, माल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में परेशान किया।
- ये कंपनियां राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, खासकर चीन द्वारा खरीद के लिए असुरक्षित हो सकती हैं।
- सभी विदेशी अधिग्रहण और निवेश प्रस्तावों की अब ऑस्ट्रेलिया के विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी।
- स्पेन, इटली और अमेरिका ने भी निवेश से संबंधित प्रतिबंधों को लागू किया है।

क्या इस तर्क के लिए कोई आधार है कि भारत का कदम भेदभावपूर्ण है?

- कुछ विशेषज्ञ ध्यान देते हैं कि संशोधन केवल सीमावर्ती देशों पर लागू होते हैं।
- अब, निवेश के एक ही सेट के लिए अलग–अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसके आधार पर कंपनी किस देश से निवेश कर रही है यह वह जगह है जहां भेदभाव का संभावित मुद्दा उठता है।
- जबकि भारत घरेलू निवेश के पक्ष में भेदभाव कर सकता है, गैर–सुरक्षा कारणों से कुछ देशों के खिलाफ भेदभाव वैश्विक स्तर पर अनुकूल नहीं देखा जा सकता है।
- यदि संबंधित क्षेत्रों में सेवाएं शामिल हैं, तो व्यापार में सामान्य समझौते के तहत गैर–भेदभावपूर्ण दायित्वों का संभावित उल्लंघन भी हो सकता है।

- अधिकांश अन्य देशों ने अपने निवेश नियमों को कड़ा कर दिया है, उन्होंने सर्वसम्मति से ऐसा किया है।
- इसका अर्थ है कि यह सभी देशों पर लागू होगा।

क्या भारत ने पहले भी ऐसा किया है?

- कुछ देशों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को लागू करने का भारत का कदम अभूतपूर्व है।
- अब तक, भारत ने कुछ क्षेत्रों में निवेश पर ऐसे उपाय किए हैं।
- उदाहरण के लिए, जबकि 2011 तक स्वचालित मार्ग के तहत फार्मास्यूटिकल्स में एफडीआई की अनुमति दी गई थी, सरकार ने उस वर्ष नवंबर से इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी निवेश के लिए अनुमोदन अनिवार्य कर दिया था।
- ऐसा कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश बढ़ाने के इरादे से इन संस्थाओं को संभावित रूप से लेने के इरादे से सतर्क किए जाने के बाद हुआ था।
- यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ लिया गया था।

सामान्य अध्ययन III
(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन)

भारत में आर्थिक संकुचन

समाचार –

- कोविड–19 महामारी और ग्रेट लॉकडाउन ने विश्व अर्थव्यवस्था पर एक गंभीर प्रभाव डाला क्योंकि देशों ने कोविड–19 का सामना करने के लिए आवश्यक संगरोध और सामाजिक दूरी प्रथाओं को लागू किया।
- 2020 वैश्विक उत्पादन में –3 प्रतिशत का संकुचन अपेक्षित है।
- यह 2008–09 के वित्तीय संकटों से बहुत बदतर है।
- भारत की वृद्धि 2020 में घटकर 1.9 प्रतिशत और 2021 में 7.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- 2020 तक देश की वृद्धि का अनुमान 3.9 प्रतिशत है जो जनवरी 2020 में लगाए गए अनुमान से काफी कम है।
- भारत में पिछले 40 वर्षों में पहली बार 2020–21 में आर्थिक संकुचन हुआ।
- वैश्विक आर्थिक विकास में संकुचन 2009 के क्रेडिट संकट से तेज होगा।
- विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की है।
- रिपोर्ट में भारत के विकास में 2020–21 में 1.5–2.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सबसे धीमी है।
- इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) ने चुनिंदा वित्तीय संस्थानों भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), विश्व बैंक और IMF के अनुमानों की तुलना की और रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच ने पाया कि 2020–21 के लिए औसतन 2–3 प्रतिशत जीडीपी विकास दर है।

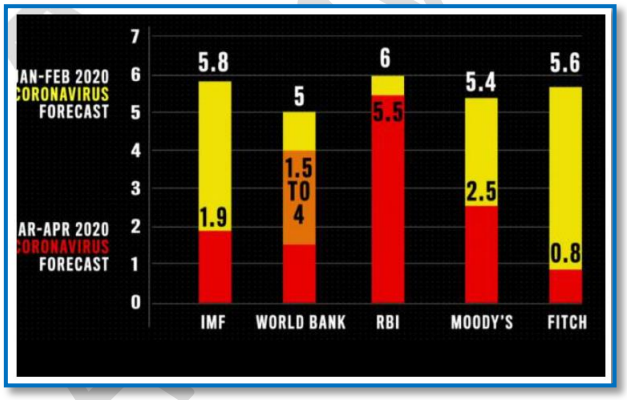

दुनिया भर में विकास के अनुमान –

- महामारी संकट से 2020–2021 तक वैश्विक जीडीपी को नुकसान जापान और जर्मनी की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के बराबर अर्थात 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है।
- विश्व बैंक के अनुसार, छह महीने पहले अनुमानित 6.3 प्रतिशत से विपरित अब 2020 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 1.8–2.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।
- यह माना गया है कि महामारी 2020 की दूसरी छमाही में धीमी हो जाएगी, विश्व अर्थव्यवस्था को 2020 में 5.8 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है क्योंकि आर्थिक गतिविधि सामान्य है, नीति द्वारा सहायता प्राप्त है।
- अगर इस अवधि में महामारी नहीं रूकती है, तो 2020 में वैश्विक जीडीपी में 3 प्रतिशत की गिरावट होगी।
- इमर्जिंग एशिया के विश्व का एकमात्र क्षेत्र होने का अनुमान है जो 2020 में 1.0 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा – जिसकी दर अभी भी पिछले दशक के औसत से 5 प्रतिशत अधिक है।

- चीन में, पहली तिमाही की आर्थिक गतिविधि 8 प्रतिशत तक संकुचित हो सकती है। चीन को 2020 में 1.2 प्रतिशत और 2021 में 9.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- अमेरिका के 2020 में 5.9 प्रतिशत तक संकुचित होने और 2021 में 4.7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। यूरोप 2020 में 7.5 प्रतिशत तक बढ़ेगा और 2021 में 4.7 प्रतिशत बढ़ेगा।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को 2020 में – 6.1 प्रतिशत के उत्पादन परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद 2021 में 4.5 प्रतिशत होगा।
- एशिया–पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) क्षेत्र में 2020 में 2.7 प्रतिशत आर्थिक गिरावट की उम्मीद है, जो 2009 में लगभग शून्य विकास दर के बाद से सबसे महत्वपूर्ण गिरावट होगी।
- इस क्षेत्र की बेरोजगारी दर 2020 में 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 3.8 प्रतिशत या 2020 में बेरोजगार होने वाले 23.5 मिलियन अतिरिक्त कर्मचारियों के बढ़ने का अनुमान है।

भारत की वर्तमान स्थिति –

- कोविड–19 का प्रकोप ऐसे समय में हुआ जब भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय क्षेत्र में लगातार कमजोर होने के कारण पहले से ही धीमी थी।
- एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के साथ, आय में गिरावट आई है और इसलिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो गई है।
- तेल की कीमतें गिर गई हैं, वास्तव में भारत के BoP की मदद कर रही है।
- हाल के आईएमएफ अनुमानों से पता चलता है कि भारत में 2020 में दुनिया में सबसे अधिक विकास दर होगी क्योंकि खाद्य भंडार भरपूर मात्रा में हैं, रबी की फसल अच्छी रही है, और मानसून का पूर्वानुमान सकारात्मक है।
- हालांकि, कुल मांग कम है लेकिन इससे मुद्रास्फीति की आवक कम हो जाएगी।
- 2020–21 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर नकारात्मक होगी।
- विकसित देश मंदी के दौर से गुजर सकते हैं।
- इस स्थिति में, बाहरी क्षेत्र से बहुत मदद नहीं मिल सकती है।
- 2020–21 की दूसरी तिमाही से वी–प्रकार की आर्थिक वसूली करना काफी संभव है।
- इस धारणा पर वर्ष के लिए समग्र विकास दर 3 प्रतिशत हो सकती है।
- 'नए आरबीआई' ने दरों को कम करने, तरलता बढ़ाने, विवेकपूर्ण मानदंडों को समायोजित करने, स्थगन की अनुमति देने और वित्तीय संस्थाओं की रक्षा करने के लिए त्वरित कार्रवाई करके साहसपूर्वक और दृढ़ता से काम किया है।
- कमजोर रुपया भारत के निर्यात और लगभग 73 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के साथ ऋण में मदद करेगा, साथ ही बेहतर विकास की संभावनाओं के साथ, भारत कई अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है।
- भारत 1991 के उदारीकरण के बाद से 2020–21 में अपने सबसे खराब विकास प्रदर्शन को रिकॉर्ड कर सकता है क्योंकि कोविड–19 का प्रकोप और लंबे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह बाधित किया है।
- विश्व बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में आपातकाल से निपटने के लिए भारत को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की मंजूरी दी है।
- कोविड–19 का सामना करने के लिए, भारत सरकार ने लॉकडाऊन लागू किया। इससे घरेलू आपूर्ति और मांग में व्यवधान आया। हाल की स्मृति में यह पहला गैर–आर्थिक कारक है जिस कारण आर्थिक संकट आया है। इसने लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है।

लॉकडाउन का प्रभाव –

- वित्त वर्ष 2021 में विकास मंदी
- सेवा क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित होगा।
- वैश्विक स्तर पर जोखिम में वृद्धि के कारण घरेलू निवेश में पुनरुद्धार में देरी होने की सबसे अधिक संभावना है
- इसमें देरी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन को लेकर चिंताओं का नवीनीकरण किया गया है।
- विकास की दर में 2021–22 में 5 प्रतिशत तक पलटाव की उम्मीद है
- स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाने और बेरोजगारों को मुआवजा देने के कार्यक्रमों के लिए भारत ने जीडीपी के सिर्फ 1 प्रतिशत से अधिक को अलग रखा है।
- यह नकद हस्तांतरण, मुफ्त भोजन और गैस सिलेंडर, और ब्याज मुक्त ऋण की ओर जा रहा है।

विश्व बैंक के सुझाव –

- भारत को रोग के प्रसार को कम करने पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर किसी के पास भोजन हो।

- इसमें अस्थायी नौकरियों के कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से स्थानीय स्तरों पर। इन पहलों का समर्थन किया जाना चाहिए।
- यह दिवालिया होने से बचना चाहिए, खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से।

उठाए जाने वाले अन्य कदम –

- नीति निर्माताओं को प्रभावित घरों और व्यवसायों का समर्थन करने के लिए लक्षित राजकोषीय, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ता है।
- बड़े केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन और प्रणालीगत तनाव को कम करने के लिए तरलता की सुविधा सदमे को सीमित करने में मदद करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को एक बेहतर पुनर्प्राप्ति के लिए स्थिति मिलेगी।
- आर्थिक रूप से विवश देशों की मदद के माध्यम से कोविड–19 महामारी के प्रभावों को दूर करने के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग इस समय की आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य और वित्त पोषण में दोहरे झटके का सामना कर रहे हैं।
- सरकार को 'प्रिंटिंग मनी' जैसी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।
- मध्यम मुद्रास्फीति महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को जन धन खातों में तीन महीने तक हर महीने 2,000 रुपये का अतिरिक्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रदान करने के साथ–साथ में खाद्यान्न पर लगभग 65,000 करोड़ रुपये में जारी करने चाहिए।
- इसे एमएसएमई को सीधे कार्यशील पूंजी (आरबीआई बैकस्टॉप के साथ) प्रदान करके और यूके की तरह, "जीएसटी–भुगतान करने वाले एमएसएमई" के कर्मचारियों को छह महीने के लिए वेतन का 80 प्रतिशत (फरवरी में उनके रोल पर) प्रदान करना होगा।
- इसे बजट के बाहर एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम (FDR की नई डील की प्रकृति में) लॉन्च करने की आवश्यकता है।
- इस फंड को बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और इसके बजट का एक चौथाई हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत और उन्नत बनाने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- आवंटन 200,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए।
- सरकार को कृषि (विशेषकर एपीएमसी से संबंधित), बिजली (मूल्य निर्धारण और डिस्कॉम), बैंकों (30 प्रतिशत और खराब बैंकों में सरकारी स्वामित्व) में बहुत जरूरी लंबित सुधारों के माध्यम से संकट का लाभ उठाना चाहिए।
- कर राजस्व की कमी को देखते हुए, सरकार को पैसा छापने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- लेकिन यह पीएम को लोगों और मंदिरों से निजी सोने की अपील करने पर भी विचार कर सकता है। (कोई सवाल नहीं पूछा गया)
- यह $30 बिलियन के 1,000 टन सोने को लक्षित कर सकता है और 10 वर्षों के बाद, रुपये या सोने में पांच प्रतिशत कर–मुक्त वापसी योग्य ($1.5 बिलियन प्रति वर्ष) की पेशकश कर सकता है।
- अगर अब कार्रवाई की जाए तो भारत आगे निकल सकता है।
- सुपर–पावर प्रतिद्वंद्विता चीन को अमेरिका और जापान को एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलने के अवसर पैदा करेगी।
- लेकिन सबसे पहले, भारत को जीवित रहना चाहिए तभी भारत फिर से कल्पना कर सकता है और रोमांचित कर सकता है।

सेवा क्षेत्र में संकुचन

- IHS मार्किट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (सर्विस पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI)) मार्च में 49.3 पर था, जो फरवरी के 85 महीने के उच्च स्तर 57.5 से नीचे था।
- IHS मार्किट द्वारा दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए सूचकांक संकलित किया गया है।
- यह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिए सूचना, विश्लेषण और समाधान में विश्व प्रमुख है।
- गिरावट मार्च के दौरान मूल रूप से कोविड–19 के कारण भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधि में संकुचन का कारण बनी है, जिससे मांग में कमी आई है, खासकर विदेशी बाजारों में।
- राष्ट्रव्यापी स्टोर बंद होने और घर छोड़ने की मनाही के कारण सेवाओं की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा।
- PMI में, 50 से ऊपर का स्कोर विस्तार को बताता है, जबकि इससे नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
- कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को मैप करता है, मार्च में 50.6 तक गिर गया, फरवरी के 57.6 से 7 अंक नीचे था।
- यह निजी क्षेत्र के उत्पादन में तेजी से मंदी का संकेत देता है और हाल ही में तेजी से बढ़ रहे विस्तार की प्रवृत्ति का अचानक अंत ले आया है।

परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स

- पीएमआई निर्माण और सेवा क्षेत्र में आर्थिक रुझानों का एक सूचकांक है।
- इसमें एक प्रसार सूचकांक होता है जो संक्षेप में बताता है कि बाजार की क्या स्थिति है जैसा कि क्रय प्रबंधकों द्वारा देखा जाता है, अर्थात उसमें विस्तार होगा, वह एक सी रहेगी या उसमें संकुचन होगा।
- पीएमआई का उद्देश्य कंपनी के निर्णय के लिए निर्माता, विश्लेषक और निवेशकों को व्यापार की स्थिति की वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)से अलग है जो अर्थव्यवस्था में गतिविधि के स्तर को नापता है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष फरवरी में IIP पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत बढ़ा।
- आईआईपी वृद्धि का कारण खनन, बिजली और विनिर्माण क्षेत्र में उच्च उत्पादन रहा।
- हाल ही में, आठ कोर सेक्टर के उद्योग में भी 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो फरवरी, 2020 जो 11 महिनों में सर्वाधिक है।
- खनन क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बिजली सेक्टर में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि 3.2 प्रतिशत की दर से हुई।
- हालांकि, ऑटो सेक्टर, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि देखी गई।
- दिसंबर में संकुचन के बाद बेहतर औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से फरवरी ने दूसरा सीधा महीना देखां।
- हालाँकि, कोविड–19 महामारी के कारण मार्च 2020 में हुए लॉकडाउन के कारण जिससे अधिकांश व्यवसाय में ठहराव हुआ, IIP के फिर से डुबकी मारने की संभावना है।

फेसबुक और रिलायंस जियो

समाचार –

- फेसबुक ने घोषणा की कि वह 43,574 करोड़ रुपये में रिलायंस जियो की होल्डिंग कंपनी, रिलायंस जियो लिमिटेड की 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।
- सौदा, जीयो प्लेटफार्म के मूल्य को 4.62 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाता है, यह रिलायंस समूह को अपने कर्ज के बोझ को कम करने में मदद करेगा, जिसके लिए तेल–टू–टेलीकॉम समूह पहले से ही सक्रिय रूप से काम कर रहा हैं।
- दोनों कंपनियों को रिलायंस के विभिन्न हथियारों – खुदरा और दूरसंचार – और व्हाट्सएप जैसे फेसबुक के प्लेटफार्मों के बीच साझेदारी द्वारा बनाई गई सहक्रियाओं से लाभ होने की उम्मीद है।
- कोविड –19 के मद्देनजर देश में लॉकडाउन के साथ ही स्थानीय किराना स्टोर के महत्व की पुर्नपुष्टि की गई।
- इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए प्रमुख ऑनलाइन वितरण चैनलों ने संघर्ष किया है।
- एकीकरण एक मोहक प्रस्ताव होने के लिए बाध्य है।
- इस मॉडल का एक स्केलिंग क्रॉस–सेलिंग के अवसर भी प्रदान करेगा।
- जो फर्मों की वृद्धि करेगा और अपने खुदरा हथियारों का मूल्यांकन बढ़ाएगा।
- वर्तमान में, हालांकि, व्हाट्सएप पे की पहुंच सीमित है – केवल एक मिलियन से अधिक भारतीयों को वर्तमान में भुगतान सुविधा तक पहुंचने की सूचना है।
- लेकिन इस तरह का मॉडल चीन, कोरिया और जापान जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में लोकप्रिय है, जहां वीचैट जैसे ऐप में उत्पाद प्रसाद की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो उपभोक्ता को प्रेरित करती है।
- यह व्यवस्था जीयो को अपने उत्पाद की पेशकश का विस्तार करने की अनुमति देती है ताकि इसके 370 मिलियन से अधिक ग्राहक आधार हो।
- यह सौदा पूरे व्हाट्सएप उपभोक्ता आधार को भी खोल सकता है – निकट सर्वव्यापी चैटिंग ऐप के पास लगभग 400 मिलियन का उपभोक्ता आधार है – रिलायंस के लिए, जिसमें एयरटेल और वोडाफोन जैसे अन्य दूरसंचार प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

इस सौदे का महत्व –

- इसके मूल में, जीयोमार्ट के आसपास एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का विचार है, जो ग्राहकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन खुदरा दोनों के संयोजन से व्हाट्सएप का उपयोग करते हुए स्थानीय किराने की दुकानों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- लाखों स्थानीय व्यवसायों को अंतिम उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने की क्षमता है, और उन्हें एक सहज ऑनलाइन लेनदेन अनुभव प्रदान करता है और यह

देश के खुदरा परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल सकता है।

- यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे देखते हुए सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक और रिलायंस जियो ने कई खुदरा विक्रेताओं की योजनाओं में एक नया योगदान दिया है।
- फेसबुक–जीयो सौदा, किराना दुकानों को रिलायंस के जीयोमार्ट तथा फेसबुक के व्हाट्सएप का उपयोग करके करोड़ों उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
- दोनों फर्मों ने सभी आकारों के व्यवसायों के लिए और विशेष रूप से देश भर में लाखों छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसरों पर जोर दिया है।
- रिलायंस जियो ने डेटा दरों को इतना कम लॉन्च किया कि वे दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बाजारों में से एक में उद्योग मानक बन गए।
- रिलायंस के साथ साझेदारी फेसबुक को भारत में नियामक वातावरण को नेविगेट करने में मदद कर सकती है।
- यह सौदा भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुलीन निवेशकों के बीच फेसबुक के प्रवेश को चिह्नित करता है।
- यह सौदा वित्तीय समावेशन को व्हाट्सएप के 400 मिलियन उपयोगकर्ताओं के रूप में गहरा करने में मदद कर सकता है, फेसबुक के व्हाट्सएप पे–यूपीआई प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकता है।
- इसके अलावा, फेसबुक की तुला क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा के कारण, यह सौदा भारत में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो–आधारित भुगतान और ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने के लिए एक कदम आगे हो सकता है।
- रिलायंस के साथ सौदा फेसबुक के बाद के गुलदस्ते जैसे जीयो Money, जीयो TV, आदि के लिए फेसबुक का उपयोग कर सकता है।
- यह रिलायंस या उसकी सहायक कंपनियों जैसे कि लॉजिस्टिक्स, ई–कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी श्रेणियों द्वारा हासिल किए गए युवा स्टार्टअप्स तक भी पहुंच प्रदान करेगा।

चिंता का विषय –

- किसी के लिए भी दोनो कंपनियो की बाजार में प्रमुख स्थिति को देखते हुए, बाजार संरचना पर चिंताएं और उपभोक्ता कल्याण के लिए इसके निहितार्थ उत्पन्न होने के लिए बाध्य हैं।
- दूसरा, टाई–अप भी तरजीही उपचार की संभावना के साथ शुद्ध तटस्थता पर सवाल उठाता है।
- भारतीय स्टार्टअप ने बड़ी तकनीकी कंपनियों और भारतीय बाजार के पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई, या अक्षमता के बारे में अपनी चिंताओं को दिखाया है।
- यह प्रमुख जोड़ी आसानी से एक एकाधिकार इकाई बन सकती है जो सभी प्रतियोगिता को मिटा देती है।
- तीसरा, कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण द्वारा अतीत में उजागर किए गए डेटा गोपनीयता मुद्दों को देखते हुए।
- उदाहरण के लिए, इन संस्थाओं द्वारा एकत्र किए जाने वाले डेटा की भारी मात्रा पर आशंकाएं हैं, खासकर जब भारत में अभी भी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून नहीं है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

समाचार –

- कच्चे तेल के लिए अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) की कीमतें शून्य से 37.63 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गईं। अब विक्रेताओं को अपने क्रूड से छुटकारा पाने के लिए खरीदारों को भुगतान करना होगा।

पृष्ठभूमि –

- कोविड–19 प्रेरित वैश्विक लॉकडाउन से पहले भी, कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ महीनों से गिर रही थीं। कारण सीधा था, मांग से अधिक होने पर एक कमोडिटी की कीमत गिर जाती है।
- ऐतिहासिक रूप से, सऊदी अरब के नेतृत्व में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक), सऊदी अरब दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है (वैश्विक मांग का 10 प्रतिशत निर्यात अकेले करता है), यह तेल उत्पादन बढ़ाकर कीमतों में कमी ला सकता है और उत्पादन में कटौती करके कीमतें बढ़ा सकता है।
- यह समझना चाहिए कि उत्पादन में कटौती या तेल के कुएं को पूरी तरह से बंद करना एक कठिन निर्णय है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे पुनः आरंभ करना महंगा और बोझिल दोनों है।
- इसके अलावा, यदि कोई देश उत्पादन में कटौती करता है, तो यह बाजार में हिस्सेदारी खोने का जोखिम रखता है यदि अन्य सूट का पालन नहीं करते हैं।

- सऊदी अरब और रूस कीमतों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक उत्पादन कटौती पर असहमत थे।
- परिणामस्वरूप, देशों ने तेल की समान मात्रा का उत्पादन जारी रखते हुए एक–दूसरे को मूल्य पर कम करना शुरू कर दिया।

कोविड–19 दर्ज करें –

- जब तक, तेल निर्यातक देशों ने उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया, तब तक आपूर्ति की मांग में कमी आई और लगभग सभी भंडारण क्षमता समाप्त हो गई।
- रेलगाड़ियों और जहाजों, जो आमतौर पर तेल परिवहन के लिए उपयोग किए जाते थे, का उपयोग केवल तेल भंडारण के लिए किया गया था।
- यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका 2018 में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।
- और यह एक कारण है कि, पिछले सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विपरीत, जिन्होंने हमेशा कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए धक्का दिया, खासकर एक चुनावी वर्ष में, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति उच्च तेल की कीमतों पर जोर दे रहे हैं।
- कई तेल उत्पादक ऐसे थे, जो उत्पादन बंद करने के बजाय दूसरा विकल्प चुनने के बजाय अपने तेल को अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर निकालना चाहते थे, जो कि मई की बिक्री पर मामूली नुकसान की तुलना में फिर से शुरू करना महंगा होगा।
- उपभोक्ता पक्ष की ओर से, उन्हें लगा कि तेल वितरण को स्वीकार करना, उसके परिवहन के लिए भुगतान करना और फिर उसे स्टोर करने के लिए भुगतान करना संभवतः (परिस्थितियों को देखते हुए, लंबी अवधि के लिए) भुगतान करना अधिक महंगा होगा।
- यह विशेष रूप से तब होता है जब अनुबंध मूल्य पर हिट लेने के लिए कोई भंडारण उपलब्ध नहीं होता है।
- दोनों ओर से यह हताशा – खरीदार और विक्रेता – तेल से छुटकारा पाने का मतलब था कि तेल की कीमतें न केवल शून्य तक गिर गईं, बल्कि नकारात्मक क्षेत्र में भी गहराई तक चली गईं।

इस मूल्य दुर्घटना से भारत कैसे लाभान्वित हो रहा है? –

- सबसे पहले, तेल आयात बिल इस वित्तीय वर्ष में तेजी से गिर जाएगा, जिससे बाहरी खाते के मोर्चे पर सरकार को काफी राहत मिलेगी।
- पश्चिम में लॉकडाउन के कारण भारत से माल का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, विदेशी मुद्रा की कमाई दबाव में है।
- तेल की कीमतें गिरने और विदेशी मुद्रा आउटगो को कम करने के साथ, चालू खाते के शेष पर दबाव बंद है।
- दूसरा, भारत सस्ते कीमतों का लाभ उठाते हुए चुपचाप अपने रणनीतिक भंडार का निर्माण कर रहा है।
- भारत में उडुपी के पास विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडुर में अपने रणनीतिक भंडार पर 39 मिलियन बैरल से अधिक तेल रखने की क्षमता है।
- ये कच्चे तेल को संग्रहीत करने के लिए परिवर्तित और निर्मित भूमिगत नमक की गुफाएँ हैं।
- रणनीतिक भंडारण क्षमता अब भी बढ़ाई जा रही है क्योंकि मौजूदा भंडारण स्थल भरते जा रहे हैं।

बेंचमार्क क्रूड –

- यह एक कच्चा तेल है जो कच्चे तेल के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करता है।
- तीन प्राथमिक बेंचमार्क हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI), ब्रेंट ब्लेंड और दुबई क्रूड।
- अन्य प्रसिद्ध मिश्रणों में ओपेक द्वारा उपयोग की जाने वाली ओपेक संदर्भ टोकरी, टेपिस क्रूड शामिल हैं जिसका सिंगापुर में कारोबार किया जाता है, नाइजीरिया में बोनी लाइट, रूस में इस्तेमाल किया जाने वाला उर्स तेल और मैक्सिको का इस्तमुस।

बौद्धिक संपदा अधिकार

समाचार –

- यूएसटीआर ने अपनी वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट में कहा है कि भारत पर्याप्त बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के अभाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की पजल प्राथमिकता वॉच लिस्ट 'पर कायम है।
- भारत आईपी प्रवर्तन और संरक्षण के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा, रिपोर्ट में कहा गया है, भाषा का उपयोग करते हुए इसका उपयोग पहले किया गया है।
- अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हैं।

- भारत ने पिछले वर्ष में कुछ क्षेत्रों में आईपी संरक्षण और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए 'सार्थक प्रगति' की।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि लेकिन इसने हाल ही में और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान नहीं किया, और नए लोगों को बनाया।
- एक ही आकलन 2019 की रिपोर्ट में किया गया था।
- ये लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के बारे में थे कि इनोवेटर्स विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पेटेंट प्राप्त करने, बनाए रखने और लागू करने में सक्षम थे। सामग्री के निर्माण और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित न करने वाले कॉपीराइट कानूनों पर चिंता। और एक पुराना ट्रेड सीक्रेट फ्रेमवर्क।
- भारत ने राज्य द्वारा जारी किए गए फार्मास्युटिकल विनिर्माण लाइसेंसों पर दी गई जानकारी की पारदर्शिता को और भी सीमित कर दिया है, फार्मास्युटिकल पेटेंट को अस्वीकार करने के लिए प्रतिबंधात्मक पेटेंटबिलिटी मानदंड लागू करता है।
- इसने अभी भी अनुचित वाणिज्यिक उपयोग, साथ ही अनधिकृत परीक्षण या अन्य डेटा (फार्मास्युटिकल्स और कुछ कृषि रासायनिक उत्पादों के लिए विपणन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्पन्न) के खिलाफ अनुचित वाणिज्यिक उपयोग से बचाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की है।
- रिपोर्ट में चिकित्सा उपकरणों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर उच्च सीमा शुल्क का भी उल्लेख किया गया है।
- प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में आईपी सुरक्षा को सीमित करने के भारत के औचित्य के बावजूद, भारत आईपी को निर्देशित अत्यधिक उच्च सीमा शुल्क रखता है – चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों, सौर ऊर्जा उपकरणों, जैसे गहन उत्पादों पूंजीगत वस्तुएं।
- भारत में ऑनलाइन आईपी प्रवर्तन में सुधार हुआ है, रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन प्रगति अदालतों और पुलिस द्वारा कमजोर प्रवर्तन, खोजी तकनीकों के साथ परिचितता की कमी और कोई केंद्रीकृत आईपी प्रवर्तन एजेंसी सहित कारकों से कम है।
- यूएसटीआर ने यह भी कहा कि 2019 में आर्थिक विकास और सहयोग संगठन (ओईसीडी) द्वारा नकली सामानों के लिए भारत को शीर्ष पांच स्रोत अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया गया था।
- सरकार के 2019 के मसौदे पर कॉपीराइट संशोधन नियम लागू होने पर, इंटरनेट–सामग्री अधिकार धारकों के लिए 'गंभीर' परिणाम होंगे, क्योंकि प्रस्तावित नियमों ने रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से ऑनलाइन प्रसारण के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के दायरे को व्यापक बना दिया था।
- ट्रेडमार्क की नकल के स्तर 'समस्याग्रस्त' थे और परीक्षा की गुणवत्ता में कमी के कारण ट्रेडमार्क प्राप्त करने में 'अत्यधिक विलंबित' थे।
- अमेरिका ने भारत को ट्रेडमार्क संधि के कानून पर सिंगापुर संधि में शामिल होने का आग्रह किया, जो एक संधि है जो ट्रेडमार्क पंजीकरण में सामंजस्य स्थापित करती है।
- विश्व बौद्धिक संपदा हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है।
- इस वर्ष, यह उत्सव के लिए एक दिन नहीं था, बल्कि प्रतिबिंब और समर्पण के लिए एक दिन था।
- इसने हमें चल रहे स्वास्थ्य संकट में बौद्धिक संपदा (आईपी) की भूमिका को प्रतिबिंबित करने और एक समाधान खोजने के लिए आईपी समर्पित करने का अवसर प्रदान किया।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर 'PPP–पेंडमिक पेटेंट पूल' का निर्माण, सभी नवाचारों को पूल करने के लिए, आगे बढ़ने का रास्ता है।
- पेटेंट संसाधनों की पूलिंग भी सार्वजनिक उपचार पर दोहा घोषणा के अनुरूप है जो ट्रिप्स समझौते का एक हिस्सा है।
- यह घोषणा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा' और 'दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने' के उपाय करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है।

अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट –

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि चीन दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए सबसे बड़ा अनुप्रयोग बन गया है।
- चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान से धकेल दिया है जो कि वैश्विक प्रणाली 40 साल से अधिक समय पहले स्थापित किया गया था।
- अमेरिका ने हर साल दुनिया में सबसे अधिक आवेदन दायर किए क्योंकि पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) प्रणाली 1978 में स्थापित की गई थी।
- चीन ने अमेरिका द्वारा दायर 57,840 आवेदनों को पिछे छोड़ते हुए 58,990 आवेदन दायर किए।
- चीन के आंकड़े में केवल 20 वर्षों में 200 गुना वृद्धि थी।
- चीन की सफलता को नवाचारों को आगे बढ़ाने की जानबूझकर रणनीति और देश की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर संचालित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- वर्तमान समय में, आधे से अधिक पेटेंट आवेदन, लगभग 52.4 प्रतिशत, एशिया से आते हैं।
- जर्मनी और दक्षिण कोरिया के बाद जापान तीसरे पायदान पर है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन –

- यह बौद्धिक संपदा (आईपी) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है।
- यह 193 सदस्य राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व–वित्त पोषण एजेंसी है।
- **मिशन** – एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय आईपी प्रणाली के विकास का नेतृत्व करने के लिए जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
- इसका जनादेश, शासी निकाय और प्रक्रियाएं WIPO कन्वेंशन में स्थापित की गई हैं, जिसने 1967 में WIPO की स्थापना की।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) –

- यह 150 से अधिक संविदा राज्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- यह एक बड़ी संख्या में देशों में से प्रत्येक में एक साथ एक पेटेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल करके पेटेंट संरक्षण प्राप्त करना संभव बनाती है।
- इस तरह का आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जो एक राष्ट्रीय या पीसीटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का निवासी हो।
- यह आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टिंग राज्य के राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय या आवेदक के विकल्प पर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ डब्ल्यूआईपीओ के साथ जिनेवा में दायर किया जा सकता है।
- पेटेंट का अनुदान राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालयों के नियंत्रण में रहता है जिसे राष्ट्रीय चरण कहा जाता है।

PCT द्वारा उपयोग किया जाता है –

- विश्व के प्रमुख निगम, शोध संस्थान और विश्वविद्यालय जब अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण चाहते हैं।
- लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) और व्यक्तिगत आविष्कारक।

साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम (CSS)

समाचार –

- साक्ष्य संचय करके, यह सुझाव दिया गया है कि गंभीर कोविड–19 वाले रोगियों में CSS हो सकता है, जो एक ट्रिगर घटना के लिए अत्यधिक तीव्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, अक्सर कुछ वायरल संक्रमणों में।

शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कार्य –

- हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को हमारी प्रणाली से निकालकर हमारी रक्षा करती है।
- इम्यूनसिस्टम उन चीजों से सक्रिय हो जाता है जिन्हें शरीर अपनी पहचान नहीं देता। इन चीजों को एंटीजन कहा जाता है।
- एक प्रभावी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया में सूजन, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा शामिल है। उदाहरण के लिए, किसी के घुटने या टखने में चोट लगने पर सूजन दिखाई देती है – इस बाहरी चोट का क्षेत्र लाल हो जाता है और सूज जाता है।
- इम्यून सिस्टम मरम्मत के काम शुरू करने के लिए घायल क्षेत्र में सफेद रक्त कोशिकाओं को तैनात करता है।

साइटोकिन्स की भूमिका –

- साइटोकिन्स भड़काऊ प्रतिरक्षाविज्ञानी प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण से लड़ने और कैंसर को दूर करने के लिए होते हैं।
- भड़काऊ मध्यस्थों की रिहाई से क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जो बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को घायल ऊतक तक ले जाने की अनुमति देता है, जिससे मरम्मत की प्रक्रिया की सहायता मिलती है। इस प्रकार, सूजन का एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कार्य है।
- हालांकि, अगर इस भड़काऊ प्रतिक्रिया को विनियमित नहीं किया जाता है, तो बहुत खतरनाक परिणाम का पालन कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब वा साइटोकाइन स्टॉर्म 'को ट्रिगर किया जा सकता है।

साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम –

- सीएसएस को प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अतिप्रवाह और इस प्रक्रिया में शिथिलता के कारण साइटोकिन्स की विशेषता है।

- **कारण** – एक साइटोकिन तूफान एक संक्रमण, ऑटो–प्रतिरक्षा स्थिति (जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है, जैसे कि सीलिएक रोग– एक प्रतिरक्षा विकार जो मुख्य रूप से छोटी आंत को प्रभावित करती है), या अन्य बीमारियों के कारण हो सकती है।
- लक्षण और लक्षणों में तेज बुखार, सूजन (लालिमा और सूजन), गंभीर थकान और मतली शामिल हैं।
- किसी भी फ्लू संक्रमण के मामले में, एक साइटोकिन तूफान फेफड़ों में सक्रिय प्रतिरक्षा कोशिकाओं की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है
- यह एंटीजन से लड़ने के बजाय, फेफड़ों की सूजन और तरल पदार्थ के निर्माण और श्वसन संकट की ओर जाता है।

नुकसान –

- एक गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, रक्तप्रवाह में बहुत अधिक साइटोकिन्स के स्राव के लिए अग्रणी, हानिकारक हो सकती है क्योंकि प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अधिकता स्वस्थ ऊतक पर भी हमला कर सकती है।
- आसपास की कोशिकाओं को नुकसान भयावह हो सकता है, जिससे सेप्सिस और संभावित मौत हो सकती है।
- सेप्सिस तब होता है जब संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया संतुलन से बाहर हो जाती है, जिससे कई अंग प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

CSS और कोविड–19 –

- साइटोकाइन तूफान कोरोनोवायरस रोगियों के लिए विशेष नहीं हैं। यह एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो अन्य संक्रामक और गैर–संक्रामक रोगों के दौरान भी हो सकती है।
- SARS-CoV-1 (जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम – SARS), SARS-CoV-2 (जो वर्तमान कोविड–19 महामारी के लिए जिम्मेदार है), और मध्य पूर्व श्वसन के लिए मानव कोरोनावायरस जैसे प्रो–भड़काऊ साइटोकिन प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। सिंड्रोम (MERS) के परिणामस्वरूप तीव्र फेफड़े में चोट लग सकती है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) हो सकता है।
- यदि सीएसएस की नैदानिक विशेषताओं को मान्यता नहीं दी जाती है और पर्याप्त उपचार तुरंत नहीं दिया जाता है, तो कई अंग विफलता हो सकते हैं।

स्वास्थ्य प्रदाता प्लाज्मा थेरेपी

समाचार –

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, प्लाज्मा थेरेपी कोविड–19 के लिए अनुमोदित उपचार नहीं है और वर्तमान में खोजी जा रही कई उपचारों में से केवल एक है।
- चिकित्सा अभी भी एक प्रायोगिक स्तर पर है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) वर्तमान में इसकी प्रभावकारिता का अध्ययन कर रही है।
- ICMR ने निर्धारित उपचार के रूप में इसके उपयोग के लिए कोई मंजूरी नहीं दी है और दुरुपयोग रोगियों के लिए घातक परिणाम हो सकता है।
- एक बड़ी चुनौती बरामद व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडी स्तर की जांच के लिए किट की अनुपलब्धता है।
- यह भारत में उपलब्ध नहीं है और इसे अन्य देशों से लाया जाना है।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने से वांछित संख्या में किट के आयात में देरी हो रही है।

विवरण –

- यह एक नई चिकित्सा नहीं है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की पुरानी अवधारणा पर आधारित हैं।
- यह कोरोनावायरस के खिलाफ रोगी में विकसित एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है।
- ऐसे लोगों से पूरा रक्त या प्लाज्मा लिया जाता है।
- प्लाज्मा को या तो गंभीर बीमारी या व्यक्तियों में वायरस होने का अधिक खतरा होता है, ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जाए और वायरस के खिलाफ उनकी लड़ाई को बढ़ावा मिले।
- संक्रामक रोगों के एक अध्ययन द लांसेट में कहा गया है कि किसी कोविड–19 रोगी आमतौर पर वायरस के खिलाफ 10–14 दिनों में प्राथमिक प्रतिरक्षा विकसित करता है।
- इसलिए, यदि प्रारंभिक अवस्था में प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है, तो यह संभवतः वायरस से लड़ने और गंभीर बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है।
- हालांकि, जबकि प्लाज्मा प्रतिरक्षा को एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित करता है, यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह कोविड– 19 संक्रमण में जीवन बचा सकता है।
- उपचार 40–60 वर्ष की आयु के रोगियों के लिए प्रभावी हो सकता है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कम प्रभावी हो सकता है।

पिछले प्रयोग –

- यूएसए ने स्पेनिश फ्लू (1918–1920) के रोगियों के इलाज के लिए मरीजों के प्लाज्मा का इस्तेमाल किया।
- हांगकांग ने इसका उपयोग 2005 में SARS (सीवयर एक्युट रेस्पीरेटरी सिंड्रोम) के रोगियों के इलाज के लिए किया था।
- 2009 में, स्वाइन फ्लू (H1N1) के रोगियों का इलाज प्लाज्मा से किया गया था।
- इसका उपयोग इबोला के दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए भी किया जाता है।

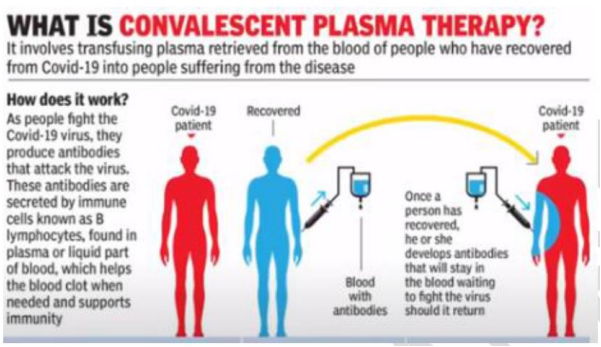

प्लाज्मा क्या है?

- रक्त में, तत्व प्लाज्मा (55 प्रतिशत), श्वेत रक्त कोशिकाएं (4 प्रतिशत), प्लेटलेट्स (0.01 प्रतिशत) और लाल रक्त कोशिकाएं (41 प्रतिशत) हैं।
- प्लाज्मा मानव रक्त का एकमात्र सबसे बड़ा घटक है। इसमें पानी, लवण, एंजाइम, एंटीबॉडी और अन्य प्रोटीन होते हैं।
- 90 प्रतिशत पानी से बना, प्लाज्मा कोशिकाओं और मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण पदार्थों की एक किस्म के लिए एक परिवहन माध्यम है।
- यह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जैसे रक्त का थक्का बनाना, रोगों से लड़ना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य।

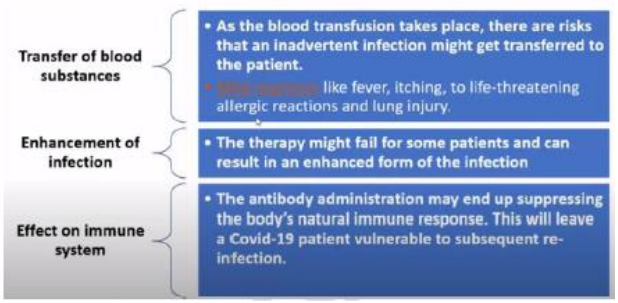

इस थेरेपी और टीकाकरण के बीच अंतर?

- यह चिकित्सा निष्क्रिय टीकाकरण के समान है। जब एक टीके का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करती है।
- यहां, प्रभाव केवल उस समय तक रहता है जब इंजेक्शन लगाए एंटीबॉडी रक्तप्रवाह में रहते हैं। दी गई सुरक्षा अस्थायी है। जबकि, टीकाकरण आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

सिपरी रिपोर्ट

समाचार –

- SIPRI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, 2019' जारी की है, जो 2019 के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सैन्य व्यय डेटा और 2010–19 के दशक के रुझानों पर प्रकाश डालती है।
- डेटा अद्यतन SIPRI सैन्य व्यय डेटाबेस से है, जो 1949–2019 के वर्षों के लिए देश द्वारा सैन्य व्यय डेटा प्रदान करता है।
- SIPRI ने कहा कि पिछले वैश्विक आर्थिक मंदी के आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट संभवतः भविष्य के सैन्य खर्च को बाधित करेगा।

मुख्य विचार –

- वैश्विक सैन्य व्यय 2019 में $1917 बिलियन होने का अनुमान है, जो 1988 के बाद का उच्चतम स्तर है। 2018 की तुलना में वास्तविक रूप में कुल 3.6 प्रतिशत अधिक था और 2010 की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक था।
- विश्व सैन्य खर्च 2015 से पाँच वर्षों में से प्रत्येक में बढ़ा, 2011 से 2014 तक वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के बाद लगातार कम हुआ।

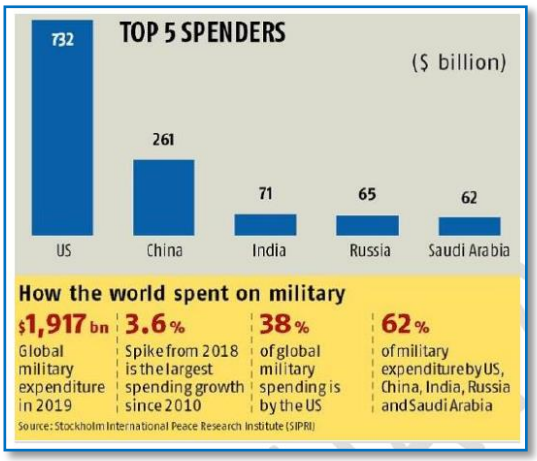

- यह पहली बार है कि दो एशियाई दिग्गज शीर्ष तीन देशों में से एक हैं, जो आयुध पर अधिक खर्च करते हैं।
- चीन के सैन्य खर्च में 2018 की तुलना में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत का 6.8 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर $ 71.1 बिलियन हो गया।
- पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ भारत के तनाव और प्रतिद्वंद्विता इसके बढ़ते सैन्य खर्च के लिए प्रमुख चालकों में से हैं।
- चीन और भारत के अलावा, जापान (47.6 बिलियन डॉलर) और दक्षिण कोरिया (43.9 बिलियन डॉलर) एशिया और ओशिनिया सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश थे। इस क्षेत्र में सैन्य व्यय कम से कम 1989 के बाद से हर साल बढ़ रहा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा 2019 में सैन्य खर्च में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वैश्विक सैन्य खर्च का 38 प्रतिशत हिस्सा है।
- 2019 में अकेले अमेरिका के खर्च में वृद्धि जर्मनी के कुल सैन्य खर्च के बराबर थी।
- यह 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से खर्च का उच्चतम स्तर है और संभवतः व्यय में एक शिखर का प्रतिनिधित्व करता है।
- कई उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य राज्यों द्वारा साझा किए गए, रूस से बढ़ते खतरे की धारणा से जर्मन सैन्य खर्च में वृद्धि को आंशिक रूप से समझाया जा सकता है।
- इसी समय, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सैन्य खर्च अपेक्षाकृत स्थिर रहा।

कोविड–19 के बीच डेटा सुरक्षा

समाचार –

- अरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था जो उन लोगों के संपर्कों को पता लगाने में मदद करता है जो कोविड–19 महामारी से संक्रमित हो सकते हैं। यह सहयोग ऐप का पूरक होगा। लेकिन हाल ही में, कानूनी विशेषज्ञों ने इस ऐप की गोपनीयता नीति पर चिंता जताई।
- इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (DoT) ने कोविड–19 संगरोध चेतावनी प्रणाली (CQAS) नामक एप्लिकेशन के बारे में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) साझा की है।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय में DoT और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने एप्लिकेशन का विकास और परीक्षण किया है।

आरोग्य सेतु ऐप

- दोनों Android फोन और iPhones के लिए उपलब्ध है।
- यह जांचने के लिए कि किसी व्यक्ति ने कोविड–19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया हो सकता है या नहीं, यह जांचने के लिए फोन के ब्लूटूथ, स्थान और मोबाइल नंबर का उपयोग करता है।
- कोविड–19 सहायता केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है और ऐप पर एक स्व–मूल्यांकन परीक्षण होता है जो यह जांचता है कि आपके पास अनजाने में कोरोनोवायरस रोग होने का मौका है या नहीं।
- इस ऐप के पूरक के लिए, भारत के सर्वोच्च मानचित्र निर्माता, सर्वे ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक रूप से नक्शों की एक टुकड़ी बनाई थी।
- इससे भू–स्थानिक डेटा में सुधार किया जा सकता है और ऐसे मानचित्र विकसित किए जा सकते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के 'कोविड– संबंधित अनुप्रयोगों' जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं, संक्रमण समूहों को आपदा प्रबंधन में अनुकूलित किया जा सकता है।
- राज्य और केंद्र सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करने और बाद में स्वास्थ्य, सामाजिक–आर्थिक संकट और आजीविका संबंधी चुनौतियों से संबंधित नागरिकों और एजेंसियों को आवश्यक भू–स्थानिक सूचना सहायता प्रदान करने का उद्देश्य।
- उपयोगकर्ता, पहचान का खुलासा किए बिना, सतर्क रहेंगे, यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास हैं, जो कोविड सकारात्मक है। यह सरकार को उन लोगों के संपर्कों को ट्रेस करने में मदद करता है जो संगरोध को अंजाम देते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित 11 भाषाओं में उपलब्ध है।
- ऐप में कार्यात्मकताओं पर जोड़ा गया है जैसे कि पीएम केयर्स फंड को दान करना, और आवश्यक सेवा प्रदाताओं के लिए ई–पास की मेजबानी करना।

सहयोग ऐप –

- सामुदायिक कार्यकर्ताओं की मदद से स्थान विशिष्ट डेटा एकत्र करता है।
- क्राऊड सोर्स डेटा को जल्दी से मदद कर सकते हैं।
- कोविड–19 मामलों के लिए बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान, नियंत्रण क्षेत्रों और उपलब्ध अस्पतालों के बारे में जानकारी, ICMR परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगरोध शिविरों को उनके अक्षांश और अनुदैर्ध्य मापदंडों के साथ इस मंच पर एकीकृत किया जाएगा।
- सहयोग एप्लिकेशन का उपयोग करके एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सभी के उपयोग के लिए विभिन्न एप्लिकेशन बनाने के लिए किया जाएगा और भारत के अंदर बने रहने वाले डेटासेट के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।
- आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे जमीन पर काम करने वाले स्वयंसेवकों द्वारा दिया गया डेटा सरकार और जमीन पर डॉक्टरों के लिए एक अच्छा समर्थन प्रणाली का निर्माण करेगा।
- यह स्वास्थ्य, सामाजिक–आर्थिक संकट और आजीविका परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने वाले श्रमिकों को आवश्यक सूचना समर्थन प्रदान करके केंद्र और राज्य सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा।

कोविड–19 संगरोध चेतावनी प्रणाली (CQAS) –

- CQAS एक सामान्य सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर फोन डेटा, स्थान एकत्र करता है, और अलगाव के तहत कोविड रोगियों द्वारा उल्लंघन के मामले में स्थानीय एजेंसियों को अलर्ट करता है।
- CQAS मोबाइल नंबर की एक सूची तैयार करता है, उन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार कंपनियों द्वारा जियो–फेंसिंग लगाने के लिए प्रदान किए गए स्थान डेट के आधार पर अलग करता है।
- जियो–फेंसिंग एक स्थान–आधारित सेवा है।
- जिसमें एक ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जीपीएस–आरएफआईडी, वाई–फाई या सेल्युलर डेटा का उपयोग करता है जब एक मोबाइल डिवाइस या आरएफआईडी टैग एक भौगोलिक स्थान के चारों ओर स्थापित एक आभासी सीमा में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, जियो–फेंसिंग के रूप में जाना जाता है।
- जियो–फेंसिंग केवल तभी काम करेगी जब उपयोगकर्ता व्यक्ति के पास एयरटेल, वोडाफोन–आइडिया या रिलायंस जियो का मोबाइल फोन हो, क्योंकि 'बीएसएनएल / एमटीएनएल' स्थान आधारित सेवाओं का समर्थन नहीं करते क्योंकि वे सरकार के स्वामित्व वाले हैं।
- स्थान की जानकारी 'प्राप्त डेटा की उचित सुरक्षा' के साथ अधिकृत मामलों के लिए समय–समय पर एक सुरक्षित नेटवर्क पर प्राप्त की जाती है।
- सिस्टम किसी अधिकृत सरकारी एजेंसी को ई–मेल और एसएमएस अलर्ट चलाता है अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के सेल टॉवर स्थान के आधार पर अलगाव से बच गया है। 'जियो–फेंसिंग' 300 मीटर तक सटीक है।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत शक्तियों का उपयोग –

- केंद्र देश भर में कोविड–19 मामलों को ट्रैक करने के लिए हर 15 मिनट में दूरसंचार कंपनियों से 'सूचना प्राप्त' करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग कर रहा है।
- राज्यों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) के प्रावधानों के तहत जियो–फेंसिंग' के उल्लंघन होने पर निर्दिष्ट मोबाइल फोन नंबरों के लिए DoT को ईमेल या एसएमएस द्वारा जानकारी देने का अनुरोध करने के लिए अपने मोबाइल सचिवों की मंजूरी लेने के लिए कहा गया है।
- अधिनियम की धारा 5 (2) राज्य या केंद्र को 'किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में' के मामले में उपयोगकर्ता के फोन डेटा की जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

चुनौतियाँ –

- एकत्र किए गए डेटा का उपयोग केवल कोविड–19 के संदर्भ में स्वास्थ्य प्रबंधन के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
- यह कड़ाई से किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है।
- इस संबंध में कोई भी उल्लंघन संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।
- पुट्टस्वामी निर्णय (2017) में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- व्यक्तिगत डेटा को सूचनात्मक गोपनीयता के आवश्यक पहलू के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है।

- भारत की स्थिति सिंगापुर जैसे देशों से भिन्न है, जहाँ अच्छी संख्या में लोगों के पास स्मार्टफोन हैं।
- भारत में इसकी आबादी की तुलना में, स्मार्टफोन उपयोगकर्ता बहुत कम हैं जिसका अर्थ है कि बहुत कम लोग ऐप डाउनलोड कर पाएंगे।
- अरोग्य सेतु और सहयोग जैसे अनुप्रयोग जो इसे लिंक करते हैं, गोपनीयता का उल्लंघन कर सकते हैं क्योंकि दोनों अनुप्रयोगों के बीच डेटा कैसे साझा किया जाएगा, इस पर स्पष्टता नहीं थी।
- अरोग्य सेतु के उपयोग की शर्तें कई पहलुओं पर स्पष्ट नहीं थीं कि कब तक डेटा संग्रहीत किया जाएगा, एक बार महामारी बंद हो जाने के बाद इसका क्या होगा, और कौन से डेटा को स्थानांतरित किया जा रहा है।
- नीति के अनुसार, 'कोविड19 के संबंध में आवश्यक चिकित्सा और प्रशासनिक हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों' के पास डेटा तक पहुंच होगी।
- इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एक वर्किंग पेपर के अनुसार, यह 'लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के अंतःविषय आदान–प्रदान का सुझाव देता है' और 'सिंगापुर और यहां तक कि इजराइल जैसे देशों की तुलना में अधिक है'।
- भारत सरकार के साथ डेटा साझा करने पर सरकार डेटा का उपयोग कैसे करेगी, इस मुद्दे पर कोई विनिर्देश नहीं।
- इसके अतिरिक्त, ऐप के साथ आनुपातिकता का भी सवाल था और क्या यह प्रचलित प्रकोप को ध्यान में रखते हुए उतना ही प्रभावी होगा।
- ऐप भारत के गोपनीयता कानून वैक्यूम वातावरण में मौजूद है।
- कोई भी कानून जो विस्तार से नहीं बताता है कि भारतीयों की ऑनलाइन गोपनीयता को कैसे संरक्षित किया जाए, आरोग्यसेतु उपयोगकर्ताओं के पास सरकार द्वारा प्रदान की गई गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के अलावा बहुत कम विकल्प हैं।
- कानूनी खामियों से परे, तकनीकी खामियां भी हैं।
- आरोग्यसेतु में अद्वितीय डिजिटल पहचान एक स्थिर संख्या है, जिससे पहचान के उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है।

आगे का रास्ता –

- ऐप गोपनीयता नीति को डेटा संग्रह, इसके भंडारण और उपयोग पर विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। भारत सरकार को यह बताना होगा कि वह ऐप के डेटा से कैसे निपटेगा और कब तक यह सर्वर साइड डेटा को बनाए रखेगा।

कोविड–19 डेटा की सुरक्षा ऑडिट

- स्प्रिंकलर सौदे को लेकर हुए विवाद के मद्देनजर, केरल सरकार ने एक सिक्यूरिटी ऑडिट लेने का निर्णय किया है।
- सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा ऑडिट–19 से संबंधित एकत्र किए गए विभिन्न आंकड़ों के लिए साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार सीईआरटी–इन एजेंसी द्वारा नोडल सुरक्षा पर ऑडिट किया जाएगा।
- केरल स्टेट आईटी मिशन (केएसआईटीएम) डायरेक्ट या ऑडिट के काम को अंजाम देने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीईआरटी–इन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) के तहत सूचीबद्ध एजेंसी को सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है।
- एजेंसी को सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अमेजॅन क्लाउड प्लेटफॉर्म में संग्रहीत डेटा के सेक्युररी टीआई ऑडिट को निष्पादित करना होगा।

आर्मीवर्म हमला

समाचार –

- कृषि निदेशालय ने असम के पूर्वोत्तर धेमाजी जिले में खड़ी फसलों पर आर्मीवर्म के एक हमले की सूचना दी है और इस कोविड–19 महामारी के बीच पहले से ही चिंतित किसानों के दुखों को और बढ़ा दिया है।

चुनौतियाँ –

- अप्रैल–मई वह समय होता है जब असम में धान के किसान खरपतवार को साफ करते हैं और नर्सरी से सर्दियों की फसल की रोपाई के लिए खेतों की जुताई करते हैं। प्रक्रिया में 35–40 दिन लगते हैं।
- कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, यदि चक्र को एक महीने से अधिक समय तक पीछे धकेल दिया जाता है, तो इससे उपज पर असर पड़ सकता है क्योंकि फसलों की बुवाई और रखरखाव का चरण असम के बाढ़ के समय के बहुत करीब होगा।
- एक और प्रमुख मुद्दा किसानों तक पहुंच रहा है। कोरोनावायरस द्वारा संक्रमण के डर के कारण सभी सड़कों और अंतराल को अवरुद्ध कर दिया गया है।
- मौसम एक कारक है क्योंकि असम में अभी तक प्री–मॉनसून वर्षा नहीं हुई है और अभी तापमान बहुत अधिक है। बारिश के अभाव में आर्मीवर्म के कीटाणु अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आर्मीवम –

- वैज्ञानिक नाम – स्पोडोप्टेरा फ्रुगुइपरदा
- आमतौर पर फॉल आर्मीवॉर्म (FAW) के रूप में जाना जाता है।
- एक खतरनाक बाउन्ड्री कीट।
- इसकी प्राकृतिक वितरण क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रस्तुत अवसरों के कारण तेजी से फैलने की उच्च क्षमता है।
- आर्मीवाटर कैटरपिलर कीटों की कई प्रजातियों का लार्वा चरण है। इसकी एक बड़ी भूख है और एंटोमोलॉजिस्ट के अनुसार पौधों की 80 से अधिक प्रजातियों पर फीड कर सकते हैं।
- एफएडब्ल्यू खाद्य सुरक्षा और लाखों छोटे किसानों की आजीविका के लिए एक वास्तविक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है, जो उप–सहारा अफ्रीका, निकट पूर्व और एशिया के सभी क्षेत्रों में फैल रहा है।

आगे को राह –

- किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) गतिविधियों के माध्यम से अपने फसल प्रणालियों में एफएडब्ल्यू को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता होती है।
- फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) ने सेना के कीड़ों द्वारा उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में एफएडब्ल्यू नियंत्रण के लिए एक वैश्विक कार्रवाई शुरू की है।

ग्राउंड वॉटर में यूरेनियम संदूषण –

समाचार –

- यूरेनियम सांद्रता मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम–दक्षिण पूर्व क्षेत्रों और गंडक नदी के पूर्व में और झारखंड की ओर गंगा नदी के दक्षिण में बढ़ रही है, विशेष रूप से गोपालगंज सीवान, सारण, पटना, नालंदा और नवादा जिलों में।
- यह सांद्रता गंगा के दक्षिण में भी बढ़ी है और विशेष रूप से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा और नवादा के दक्षिण–पश्चिमी जिलों में बढ़ी है।
- सुपौल में अधिकतम यूरेनियम की मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पानी में पाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अनुमेय सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है।
- यूरेनियम के संपर्क में आने से अस्थि विषाक्तता और गुर्दे की कई बिमारीयों जैसे कई नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं।
- यह पहली बार है जब भूजल में यूरेनियम सामग्री का पता चला है। यह बहुत खतरनाक है और इससे कैंसर भी हो सकता है।
- पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक संदूषण (26 मिलियन), बिहार (9 मिलियन), उत्तर प्रदेश (3 मिलियन), असम (1.2 मिलियन), मणिपुर (1 मिलियन) और झारखंड (0.4) के बाद सबसे अधिक अनुमानित जनसंख्या है। मिलियन)।

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (IDSA)

RMB (Renminbi) डिजिटल हा गइ–

- पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBC) ने शंघाई, चोंगकिंग, शेन्जेन, हांग्जो, सूजौ और Xiong'an New Area के साथ अपनी डिजिटल मुद्रा की पायलट ट्रायल शुरू की है।
- चीन अपने मौजूदा मौद्रिक आधार या नकदी को संचलन में आंशिक रूप से डिजिटल करने का इरादा रखता है – ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला राष्ट्र होगा।
- मौद्रिक प्रणाली के साथ डिजिटल मुद्रा के एकीकरण के साथ शुरुआत करते हुए पहला कदम खुदरा क्षेत्र में वेतन का भुगतान, परिवहन और सब्सिडी को अपनाना है।

पृष्ठभूमि –

- जैसे ही चीन कोविड–19 महामारी से बाहर निकलता है, नकद उपयोग के लिए भुगतान के संपर्क रहित मोड में बदल रहे लोगों के साथ डुबकी लगाई जाती है।
- महामारी ने उन अनुप्रयोगों के लिए डिजिटल मुद्रा रोलआउट को तोड़ दिया हो सकता है जो स्पष्ट रूप से अल्पविकसित हैं, लेकिन विचार के बीज आधा दशक पहले बोए गए थे।

एक डिजिटल आरएमबी (रेनमिनबो)

- पीबीसी ने 2017 में एक डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की और दिसंबर 2019 में बीजिंग में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया।
- चीन की डिजिटल मुद्रा/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (डीसी/ईपी) ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है, लेकिन आगामी डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरंसी नहीं है।

- डिजिटल मुद्रा, जिसका उपयोग किसी भी बैंक खाते से लिंक किए बिना किया जा सकता है, से अपेक्षा की जाती है कि वह उच्च–आवृत्ति में भौतिक नकदी की जगह लेगी, लेकिन कम जारी करने की लागत, दक्षता और उपयोगिता पर धुरी देने वाले छोटे मूल्यवर्ग के लेनदेन के साथ।
- डिजिटल मुद्रा का प्रचलन PBC के दायरे में होगा, जबकि वाणिज्यिक बैंक भुगतान और जमा की प्रक्रिया करेंगे।

निष्कर्ष –

- कोविड–19 महामारी के बाद में, डिजिटल साधन लेन–देन के अनुकूल साधन होने जा रहे हैं।
- भौतिक नकदी के विपरीत, डिजिटल वॉलेट या डिजिटल मुद्रा पर डिजिटल लेनदेन ट्रेस करने योग्य हैं।
- चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के व्यापक विस्तार के कारण, चीन की क्षमता और घुसपैठ निगरानी कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने की मंशा निर्विवाद बनी हुई है।

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के बीच कोविड–19 महामारी

- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में कोविड–19 महामारी का प्रसार भारत के लिए चिंता का कारण है।
- अपनी ओर से, भारत ने बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन टैबलेट प्रदान करके इस क्षेत्र के देशों को समर्थन बढ़ाया है। अपनी सरकार के अनुरोध पर कुवैत में 15 सदस्यीय मेडिकल टीम भेजनाय देश को महामारी के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए यूएई के 88 मेडिकल और हेल्थकेयर पेशेवरों की एक और टीम।
- GCC 2018–19 में लगभग 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का एक प्रमुख व्यापार भागीदार है। जीसीसी देशों में, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत के दो प्रमुख व्यापार भागीदार हैं, जिनका वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- जीसीसी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था पर महामारी के शुरुआती प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है और कई तपस्या उपायों को अपना रहे हैं। तेल की कीमतों में गिरावट के कारण राज्य को अपने राजस्व का 50 प्रतिशत खो दिया है।
- तेल की कीमतें गिरने के समय खाड़ी में कोविड–19 का प्रसार स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता को और अधिक बाधित करता है।
- वर्तमान परिदृश्य में, नौ मिलियन मजबूत भारतीय प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को जीसीसी देशों में अपनी नौकरी खोने का खतरा है। उनमें से कई जल्द से जल्द भारत लौटना चाहते हैं।
- भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, जो 2018 में यूएस $ 79 बिलियन प्राप्त कर रहा है।
- इसके कुल प्रेषण के आधे से अधिक अकेले जीसीसी देशों से आते हैं।
- आर्थिक गतिविधियों में गड़बड़ी और खाड़ी में रोजगार के नुकसान से भारत के लिए प्रेषण की आमद प्रभावित होगी।
- विश्व बैंक ने पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी है कि कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में वैश्विक प्रेषण में सबसे तेज गिरावट देखी जा रही है। खाड़ी से हजारों भारतीयों के वापस आने की स्थिति में, भारत में प्रेषण की आमद काफी प्रभावित होगी।
- इस प्रकार, कोविड–19 महामारी द्वारा संचालित, खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली भारत के लिए आर्थिक चुनौतियां अत्यधिक आसन्न और विवेकी हैं।

कुरुक्षेत्र अप्रैल 2020

ग्रामीण रोजगार परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन

- ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी कई योजनाओं के माध्यम से गांवों के समावेशी विकास के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है।
- इन योजनाओं के तहत, गाँव के गरीब और युवाओं के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने और उन्हें रोजगार या स्व–रोजगार से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

याद रखने योग्य तथ्य –

- वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के एक अनुमान के अनुसार, नियमित वेतन/वेतन की हिस्सेदारी में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी 2011–18 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 23 प्रतिशत हो गई है।

- नियमित वेतन/वेतन–आधारित रोजगार की श्रेणी में महिला श्रमिकों के अनुपात में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अर्थात वर्ष 2011.12 के दौरान यह 13 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया।
- उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2019 में 14.59 लाख नौकरियों और दिसंबर 2019 में लगभग 12.67 लाख नौकरियों का सृजन हुआ।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 1.49 करोड़ नए कर्मचारियों/श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नामांकित किया गया था।
- सितंबर 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान ईएसआईसी की योजना में लगभग साढ़े तीन करोड़ नए व्यक्ति शामिल हुए।

ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम –

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 'कुशल भारत कार्यक्रम' में, हर साल एक करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बेहतर और आकर्षक आजीविका तक अपनी पहुंच बढ़ा सकें।
- सेवा क्षेत्र का विस्तार करने, प्रशिक्षुता और उसके प्रचार के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में अपरेंटिस अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) अगस्त 2016 में शुरू की गई थी, ताकि नियोक्ताओं को यथासंभव अधिक शिक्षार्थियों को संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश के 24 लाख युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू कर रहा है।
- यह बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका के लिए उद्योग संगत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- सभी मौजूदा श्रम कानूनों को केवल 4 श्रम कोडों में समाहित किया गया है और उन्हें वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार सरलीकृत और तर्कसंगत बनाया गया है।
- असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा के लाभों के साथ–साथ बुढ़ापे से सुरक्षा के लिए दो बड़ी पेंशन योजनाएं भी शुरू की गई हैं।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- 12 सितंबर, 2019 को व्यवसायियों, दुकानदारों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना भी शुरू की गई है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय विभिन्न रोजगार से संबंधित सेवाएं जैसे कि कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी, प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय कैरियर सेवा को लागू कर रहा है।
- रोजगार महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, 21 राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र भी अलग–अलग तरीके से संचालित किए जा रहे हैं।
- देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विशेष सेवाएँ प्रदान कर रही है।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) के तहत व्यवसाय शुरू करने से 3 साल तक के लिए नए नियोक्ताओं को सहायता।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम– मनरेगा सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा के अपने मूल उद्देश्यों के अनुरूप ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन का एक कार्यक्रम है।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना** – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विविध और लाभकारी स्वरोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार के कुशल अवसरों के माध्यम से गरीबी को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी आधार पर ग्रामीण गरीबों की आय में सराहनीय वृद्धि हुई है।

- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना कार्यक्रम के तहत, 15 से 25 वर्ष के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो प्रमाणन–आधारित है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप है।

एमएसएमई – नए युग को उद्यमिता

- एमएसएमई क्षेत्र 100 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 45 प्रतिशत विनिर्माण उत्पादन के साथ–साथ देश के निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है। एमएसएमई क्षेत्र वर्तमान में देश की जीडीपी में 29 प्रतिशत का योगदान देता है। 2015–16 के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73 वें दौर के अनुसार, भारत में असिंचित गैर–कृषि एमएसएमई में श्रमिकों की अनुमानित संख्या 11.10 करोड़ थी।
- 2019 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, MSME पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ा नौकरी निर्माता है, खासकर आतिथ्य और पर्यटन, वस्त्र और परिधान, धातु उत्पाद, मशीन भागों और रसद जैसे क्षेत्रों में।

एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावित करने वाले आर्थिक सुधार –

- सरकार ने तेजी से आर्थिक परिवर्तन के लिए नींव रखने और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक उच्च विकास प्रक्षेपवक्र पर ले जाने के लिए कई प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को लागू किया है।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता का अधिनियम।
- अनुकूल, पूर्वानुमान और पारदर्शी कराधान प्रणाली। (जीएसटी का परिचय)।
- डिजिटल कनेक्टिविटी। दुनिया के सबसे बड़े अद्वितीय डिजिटल पहचान कार्यक्रम आधार के तहत लगभग 1.2 बिलियन भारतीय पंजीकृत हैं।
- स्मार्टफोन की पहुंच और कनेक्टिविटी में वृद्धि – वर्तमान में 530 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं – 2024 तक 1 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) एप्लिकेशन डिजिटल पैसे के लेनदेन को भारी बढ़ावा दे रहा है।
- सरकारी खरीद को सरकारी ई–बाजार (GeM) के माध्यम से भी डिजिटल किया गया है।
- एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धि कार्यक्रम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।
- इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है जो भारत, भारत की उपस्थिति, कम, कागज रहित और कैशलेस सेवा वितरण की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए सरकारों, व्यवसायों, स्टार्ट–अप और डेवलपर्स को अनुमति देता है।
- सरकार ने कई क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है, जिसमें एकल ब्रांड खुदरा व्यापार और निर्माण विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

एमएसएमई के विकास की पहल –

- औपचारिक ऋण तक पहुंच, चाहे वह कार्यशील पूंजी या पूंजी निवेश वित्त के लिए हो।
- सरकार ने विलंबित भुगतान की समस्या से निपटने के लिए MSMEs की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के साथ–साथ समधन पोर्टल को संबोधित करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) लॉन्च किया।
- सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं को लागू कर रही है।
- हाल ही में, नवंबर, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एमएसएमई के लिए ब्याज सबमिशन योजना में कुछ अनुकूल संशोधन किए गए हैं।
- एमएसएमई मंत्रालय देश में मौजूदा 18 टीसीएस को अपग्रेड करने के साथ–साथ यूओ 15 नए टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है।
- खादी को लोकप्रिय बनाने और ग्रामोद्योग को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।
- फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देना रहा है। 2024 तक $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए, भारत में विभिन्न राज्यों की निर्यात क्षमता को समझना और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
- एमएसएमई के संबंध में, सरकार ने भारत के निर्यात में सेक्टर का हिस्सा मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख बजट घोषणाएँ और आवंटन –

- केंद्रीय बजट 2020–21 में, सरकार ने रुपये की एक सर्वकालिक उच्च राशि निर्धारित की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए 7,572.20 करोड़।
- मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, को 2,500 करोड़ रुपये के सभी समय की उच्च राशि भी आवंटित की गई है।
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण आवंटन में खादी विकास योजना और ग्रामोदय विकास योजना के लिए 472 करोड़ रुपये के साथ–साथ गांवों में खादी आधारित उद्यमों का एक स्थायी मॉडल विकसित करने के लिए एमएसई–क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए 391 करोड रुपये (पिछले वर्ष की तुलना में 71 प्रतिशत की वृद्धि)
- कारीगरों के लिए अधिक उत्पादक, लाभदायक और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने वाले पारंपरिक उद्योगों को लैस करने के लिए पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (SFURTI) ने 465 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष में 125 करोड़ की तुलना में उच्च आवंटन भी देखा है।
- इसके अलावा, एमएसएमई को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, क्रेडिट–लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के तहत आवंटन को बढ़ाकर 805 करोड़ रुपये किया गया है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब को 150 करोड़ रुपये
- अन्य प्रमुख बजटीय घोषणाओं में ऐप–आधारित इनवॉइस वित्तपोषण ऋण उत्पाद, निर्माण शामिल है।

सुक्ष्म विकास के लिए सूक्ष्म और छोटे ग्राहक

- क्लस्टरिंग एमएसएमई को वैश्वीकरण द्वारा प्रदान की गई चुनौतियों का मुकाबला करने की सुविधा प्रदान करता है।
- क्लस्टर नीतियां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अंतर–फर्म सहयोग, व्यवसाय नेटवर्किंग और संगठनों के निर्माण सुदृढ़ीकरण को मजबूत करने की दिशा में काम करती हैं।
- क्लस्टर न केवल प्रतिस्पर्धा में सुधार करने का एक साधन है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, स्थायी रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने, बेहतर क्रेडिट प्रवाह को सक्षम करने और पर्यावरण के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से और लगातार बनाए रखने के लिए है।
- वास्तव में, हाल के दिनों में दुनिया भर के देश एक क्लस्टर दृष्टिकोण पर भरोसा कर रहे हैं, जो सहायक कंपनियों और नीतिगत ढांचे के साथ छोटी कंपनियों और उनके बाहरी वातावरण में नेटवर्क सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है।
- कच्चे माल, भागों और घटकों, मशीनरी, कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ–साथ अन्य सहायक सेवाओं की विशेष आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति के कारण उद्यम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बना सकते हैं।
- समूहों पर अनुसंधान स्पष्ट रूप से हितधारकों के बीच सकारात्मक अंतर्संबंधों के साथ समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के फायदों को दर्शाता है।
- क्लस्टर विकसित करना न केवल उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने का एक साधन है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, स्थायी रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और बेहतर, प्रभावी और स्थायी ऋण प्रवाह को सक्षम करने का साधन भी है।

क्लस्टर विकास पहल

1. पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (SFURTI)

- समूहों का चयन उनकी भौगोलिक सांद्रता पर आधारित होगा जो एक जिले में एक या दो राजस्व उपखंडों में स्थित कारीगरों/सूक्ष्म उद्यमों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं आदि के लगभग 500 लाभार्थी परिवारों (सन्निहित जिलों में) के लिए होना चाहिए।
- यह समूह चमड़े और मिट्टी के बर्तनों सहित खादी, कॉयर और ग्राम उद्योगों से होगा।
- SFURTI के तहत समूहों के चयन में उत्पादन और रोजगार के अवसरों के सृजन में वृद्धि की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित कम से कम 10 प्रतिशत के साथ पूरे देश में समूहों का भौगोलिक वितरण, समूहों का चयन करते समय भी ध्यान में रखा जाएगा।

2. सौर चरखा क्लस्टर

- भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने 2018 में सौर चरखा मिशन की शुरुआत की।
- सौर चरखा समूहों की 11 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्कीम संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3. सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)

- MSME ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) और उनके सामूहिकों की क्षमता निर्माण के साथ–साथ उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए क्लस्टर रणनीति दृष्टिकोण को एक प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है।
- एक क्लस्टर एक पहचान योग्य और जहाँ तक व्यावहारिक संवादात्मक क्षेत्र या एक मूल्य श्रृंखला के भीतर स्थित उद्यमों का एक समूह है, जो एक भौगोलिक क्षेत्र से परे जाता है और समान/समान उत्पादों/पूरक उत्पादों/सेवाओं का उत्पादन करता है, जिन्हें आम भौतिक बुनियादी ढांचे द्वारा एक साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसी सुविधाएं जो उनकी आम चुनौतियों का समाधान करने में मदद करती हैं।

एक क्लस्टर में उद्यमों की आवश्यक विशेषताएं हैं –

(a) उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, ऊर्जा की खपत, प्रदूषण नियंत्रण, आदि के तरीकों में समानता या संपूरकता।
(b) प्रौद्योगिकी और विपणन रणनीतियों/प्रथाओं के समान स्तर, क्लस्टर के सदस्यों के बीच संचार के लिए समान चौनल,
(c) आम बाजार और कौशल की जरूरत और/या
(d) सामान्य चुनौतियां और अवसर जो क्लस्टर का सामना करते हैं।

4. कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना

- इस योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढाँचे और सामान्य सुविधाओं का विकास करना है।
- इस योजना का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करना है।
- यह योजना आधुनिक अवसंरचना के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों / किसानों के समूहों को प्रोसेसर और बाजारों से जोड़कर वही चाहती है।
- इकाइयों को एक साथ स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ बुनियादी ढाँचे का निर्माण भी किया जाता है।
- परियोजना निष्पादन एजेंसी (PEA)/संगठन जैसे सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/संयुक्त उपक्रमों/गैर सरकारी संगठनों/सहकारी संस्थाओं/SHGs/FPOs /निजी क्षेत्र/व्यक्तियों, आदि द्वारा स्थापित कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और नियम और शर्तों के अधीन वित्तीय सहायता के पात्र हैं। योजना के दिशानिर्देशों के तहत।

1. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) इसका उद्देश्य मेगा हैंडलूम क्लस्टर विकसित करना है जो स्पष्ट रूप से पहचान योग्य भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं।
ये हथकरघा समूह विशिष्ट उत्पादों के विशेषज्ञ होते हैं, जिनमें निकट संबंध और क्लस्टर में प्रमुख खिलाड़ियों के बीच अंतर–निर्भरता होती है।
वे बेहतर भंडारण सुविधाओं, प्री–लूम / ऑन–लूम / पोस्ट–लूम ऑपरेशंस, बुनाई शेड, कौशल उन्नयन, डिजाइन आदानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आदि में बेहतर भंडारण सुविधाओं के साथ बुनियादी सुविधाओं में सुधार करके ऐसा करते हैं।
यह अंततः घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझदार और बदलते बाजार की मांग को पूरा करने में सक्षम होगा और हथकरघा उद्योग में लगे लाखों बुनकरों के जीवन स्तर को बढ़ाएगा।

2. फार्मा क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी–पीएस)

- फार्मा सेक्टर (सीडीपी–पीएस) के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम के रूप में करार दी गई योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है और अगली पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया है।
- योजना का कुल आकार 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सीडीपी–पीएस के लिए 15 करोड़ रुपये के रूप में प्रस्तावित है।
- इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रारूप पर लागू किया जाएगा, जो कि पहचान के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों में जारी की जाने वाली सहायता के लिए एकमुश्त अनुदान के माध्यम से और विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के उद्देश्य से स्थापित की गई है।
- यह योजना नए क्लस्टर स्थापित करने और मौजूदा क्लस्टर के उन्नयन के लिए है।
- हालांकि, अनुदान का उद्देश्य सामान्य सुविधाओं की गतिविधियों के लिए है।
- योजना के विभिन्न पहलुओं और परिणामों की समीक्षा इसके शुरू होने की तारीख से तीन साल बाद की जाएगी।

3. मेगा लेदर क्लस्टर

- मेगा लेदर क्लस्टर्स में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर (मशीनरी / उपकरण के लिए प्लग इन फैक्ट्री शेड का उपयोग करने के लिए तैयार), एचआरडी और सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्षमता निर्माण आदि होंगे।
- प्रत्येक एमएलसी को एक एसपीवी द्वारा लागू किया जाएगा।
- प्रत्येक एसपीवी एक कॉर्पोरेट निकाय होगा, जो कि हितधारकों द्वारा गठित कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होगा, विशेष रूप से इच्छुक उद्यमियों का समूह (न्यूनतम 7 कानूनी रूप से स्वतंत्र कंपनियां)।
- ये उद्यमी चमड़े की टैनिंग, चमड़े के सामान और घटकों के विनिर्माण और अन्य में लगे हुए हैं और जो प्रस्तावित एलएलसी में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने का इरादा रखते हैं।
- एसपीवी आधारभूत संरचना की अवधारणा, निर्माण, वित्तीय समापन को प्राप्त करने, कार्यान्वयन और प्रबंधन करेगा।

4. अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास योजना (AHVY)

- भारत भर में क्लस्टर कारीगरों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन के लिए विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल।
- इन कारीगरों के उत्थान के लिए डीसी, हस्तशिल्प के साथ भागीदारी करने वाली एजेंसियों को लागू करके इन उत्पादों को बनाने के लिए कारीगरों को तकनीकी/विपणन जानकारी प्रदान की जाती है।

5. अनुसंधान और विकास योजनाएं (क्लस्टर)

- नियमित आधार पर आरएंडडी गतिविधियों की आवश्यकता को देखते हुए नए उत्पादों को विकसित करने और कॉटेज इंडस्ट्रीज के मौजूदा उत्पादों को संशोधित करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए फंड के प्रावधान के लिए एक नई योजना का सुझाव दिया है।

6. औद्योगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने परियोजना की प्रत्येक परियोजना के लिए 6 करोड़ रूपये की लागत के अधीन, 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के साथ सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को प्रदान करके उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2003 में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना शुरू की।

7. आयुष समूह

- कोर हस्तक्षेप जैसे कि परीक्षण, प्रमाणन, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य क्षमता निर्माण उपायों के लिए सामान्य सुविधाओं की स्थापना से संबंधित, और ऐड–ऑन हस्तक्षेप जो विपणन/ब्रांडिंग से संबंधित हैं, उत्पादन इकाइयों को सामान्य बुनियादी ढांचे के समर्थन का प्रावधान आदि।

12. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)

- मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करके, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से नियोजित उपनगरीय समूहों का निर्माण करके इन समूहों को बदलना है।
- इससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

13. शिल्प क्लस्टर

- निफ्ट में क्राफ्ट क्लस्टर पहल को निफ्ट के छात्रों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने और क्षेत्रीय संवेदनशीलता और विविधताओं, संसाधनों और पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- इस पहल के माध्यम से, निफ्ट फैशन और इसके विपरीत शिल्प को आत्मसात करने में व्यापक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने में सफल रहा है।
- क्राफ्ट क्लस्टर पहल कार्यक्रम भारत के विविध समृद्ध और अद्वितीय हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए हर साल NIFT के छात्रों को व्यवस्थित, निरंतर और नियमित प्रदर्शन प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है।
- इस गतिशील पहल के तहत, निफ्ट के छात्र भारत के समूहों में कारीगरों और बुनकरों के साथ मिलकर काम करते हैं और नैदानिक अध्ययन, डिजाइन हस्तक्षेप और प्रोटोटाइप विकास जैसी गतिविधियां करते हैं।

- कारीगरों और बुनकरों को एक्सपोजर कार्यशालाओं, प्रदर्शन कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और शिल्प बाजारों के लिए निफ्ट परिसरों में भी आमंत्रित किया जाता है, जहाँ उन्हें शिल्प विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने, अपने उत्पाद को डिजाइन करने और ज्ञान प्राप्त करने और शहरी बाजारों में उपभोक्ताओं को समझने का अवसर मिलता है।

निष्कर्ष –

- एक स्थायी और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए, समग्र क्लस्टर विकास दृष्टिकोण गुणन इंजन होगा।
- यह उद्यम विकास के लिए उत्प्रेरक होगा और उनके निर्वाह के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा।
- ध्यान केंद्रित क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों पर होना चाहिए।

भारत में रोजगार सृजन के लिए योजनाएँ

सरकार ने हाल ही में कई कदम उठाए हैं जो रोजगार सृजन के लिए मददगार साबित हुए हैं।

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

- MGNREGS एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो सामाजिक विषमताओं पर काबू पाने और स्थायी और दीर्घकालिक विकास के लिए आधार बनाकर समग्र रूप से गरीबी को संबोधित करता है।
- MGNREGS ग्रामीण भारत को अधिक उत्पादक, न्यायसंगत और जुड़े हुए समाज में बदल रहा है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) को ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य 2022 तक कच्चे और जीर्ण घरों में रहने वाले सभी आवासहीन गृहस्वामियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।

3. कौशल उन्नयन और महिला सहयोग योजना

- यह योजना कॉयर विकास योजना के तहत आती है और घरेलू और निर्यात बाजार, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं के सशक्तीकरण, रोजगार ६ उद्यमिता निर्माण और विकास, कच्चे माल का उपयोग, व्यापार–संबंधित सेवाओं, कॉयर श्रमिकों की कल्याणकारी गतिविधियों का विकास प्रदान करती है।
- महिला कौशल योजना विशेष रूप से उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण के बाद रियायती दरों पर कताई उपकरण के प्रावधान के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से है।

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लघु उद्यमियों को 10 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान करने और सूक्ष्म–वित्त संस्थानों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करने के दोहरे उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी।
- मुद्रा, युवा शिक्षित या कुशल श्रमिकों और महिलाओं के उद्यमियों सहित उद्यमियों को लक्षित करती है।
- यह योजना गैर–कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है जो उन्हें जीडीपी विकास और रोजगार सृजन के साधनों में बदल देगी।
- ऋण तीन श्रेणियों में आसानी से सुलभ हैं – शिशु, किशोर और तरुण लाभार्थी सूक्ष्म इकाई / उद्यमी की वृद्धि /विकास और धन की जरूरतों के चरण को दर्शाने के लिए और स्नातक / विकास के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान करते हैं।

2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना।
- इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेंगे।
- पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी आकलन और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के तहत प्रमाणित किया जाएगा।

3. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना

- डीडीयू–जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है, जो ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता को जोड़ने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम करता है और ग्रामीण युवाओं के कैरियर की आकांक्षाओं को पूरा करता है।

4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रेखांकित, SPMRM स्थानिक योजना के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर केंद्रित है।
- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पगड़ी के समूहों की पहचान शहरीकरण के बढ़ते संकेत यानि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, गैर–उच्च रोजगार के उच्च स्तर, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और अन्य सामाजिक–आर्थिक मापदंडों की उपस्थिति से होती है।
- मिशन का उद्देश्य इन रूर्बन समूहों को स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से नियोजित रुर्बन समूहों का निर्माण करना है।

बजट 2020–2021 और ग्रामीण रोजगार –

- तदनुसार, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए ष्सोलह एक्शन पॉइंट्सष के तहत, केंद्र सरकार ने ग्रामीण कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इसमें कृषि, सिंचाई और संबद्ध गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।
- इसी तरह, सरकार ने वर्ष 2020– 21 के लिए कृषि ऋण के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।
- इसने 100 जल–तनावग्रस्त जिलों के लिए एक व्यापक उपाय भी प्रस्तावित किया है।
- इसने 20 लाख किसानों को स्टैंड–अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए और 15 लाख किसानों को अपने ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सोलराइज करने के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया।
- इसने ब्लॉक/तालुक स्तर पर और बागवानी क्षेत्र में कुशल गोदामों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें बेहतर विपणन और निर्यात के लिए "एक उत्पाद, एक जिला" पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो उस दिशा में कुछ कदम हैं।
- सरकार ने चारा खेतों को विकसित करने के लिए MGNREGS को विकसित करने की योजना बनाई है।
- इसका लक्ष्य 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है।
- इसी प्रकार, ब्लू इकोनॉमी पर 2022–23 तक मछली उत्पादन को 200 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- चालू वित्त वर्ष में, युवा 3477 सागर मित्र और 500 मछली उत्पादक उत्पादक संगठनों के माध्यम से मत्स्य विस्तार में शामिल होंगे।
- सरकार को उम्मीद है कि 2024–25 तक मत्स्य निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

योजना अप्रैल 2020

मानवाधिकारों की सुरक्षा –

मानवाधिकार –

- मानव अधिकार नैतिक सिद्धांत हैं जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और म्युनिसिपल और अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्राकृतिक और कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित हैं।
- ये ऐसे अधिकार हैं जो हर इंसान के पास होते हैं, भले ही वह किसी राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि का हो।
- वे हमारे स्वभाव में निहित हैं और उनके बिना हम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते।

वैश्विक समुदाय द्वारा किए गए सार्वभौमिक घोषणाएं

- 1966 तक, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो महत्वपूर्ण वाचाएं अपनाईं जो एक ही समय में सामान्य और सार्वभौमिक दोनों हैं, एक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ और दूसरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 और वैकल्पिक प्रोटोकॉल समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति, अनिवार्य व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश का प्रशासन में भाग लेने का अधिकार आदि से संबेधित है।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 में काम करने का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, व्यापार या पेशे पर ले जाने का अधिकार, संस्थाओं के संरक्षण के लिए संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार आदि से संबंधित है।

भारतीय संविधान मानव अधिकारों के बारे में

- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

- भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों के लिए कई अधिकारों की गारंटी दी है जिन्हें संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है।
- जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- धार्मिक स्वतंत्रता के अलावा, जिसमें किसी व्यक्ति के अपने विश्वास, विश्वास और पूजा का अधिकार, अभ्यास और प्रचार करना और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल है।
- संस्कृति के प्रति अल्पसंख्यकों के अधिकारों और शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने के कुछ लागू करने योग्य अधिकार हैं, जिन्हें कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से राज्य द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
- संविधान सभी नागरिकों को, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, बुनियादी अधिकारों की रक्षा करके मानव अधिकारों की रक्षा करता है।
- इन्हें संविधान में मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों के रूप में गारंटी दी गई है, जो उचित हैं। संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है।

भारत में मानवाधिकार उल्लंघन –

भारत के सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक ढांचे और उसके औपनिवेशिक अतीत ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए कई प्रयासों को चुनौती दी है।

भारत में अधिकांश मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुख्य मुद्दे निम्नानुसार हैं।

- पुलिस द्वारा कार्रवाई करने में विफलता
- गैरकानूनी हिरासत
- गलत फहमी
- कस्टोडियल हिंसा
- अवैध गिरफ्तारी
- कस्टोडियल मौतें
- एनकाउंटर में हुई मौतें
- कैदियों का उत्पीड़नय जेल की स्थिति
- एससी और एसटी पर अत्याचार
- बंधुआ मजदूर। बाल श्रम
- बाल विवाह
- सांप्रदायिक हिंसा
- दहेज हत्या या उसका प्रयासय दहेज की मांग
- महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न और आक्रोश
- महिलाओं का शोषण
- विकलांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव
- एचआईवी/एड्स वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव
- यौनकर्मियों के खिलाफ भेदभाव आदि।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग –

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित किया गया था। जिस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई है, वह मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 है, जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित है। एनएचआरसी मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत की चिंता का एक प्रतीक है।

कार्य –

- मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना।
- मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी अधिनियम के तहत या उसके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की समीक्षा करना।
- मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित किसी भी मामले पर मंत्री को कोई राय, सिफारिश, प्रस्ताव या रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- मानव अधिकारों के आनंद को बाधित करने वाले कारकों या कठिनाइयों की समीक्षा करना।
- विशेष रूप से सूचना और शिक्षा के माध्यम से और सभी प्रेस अंगों का उपयोग करके, सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाकर सभी प्रकार के भेदभाव से निपटने के लिए मानव अधिकारों और प्रयासों का प्रचार करना।
- मानव अधिकारों के शिक्षण और अनुसंधान के लिए कार्यक्रमों के निर्माण में सहायता करने के लिए और स्कूलों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर हलकों में उनके निष्पादन में भाग लेते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के साथ राष्ट्रीय कानून और प्रथाओं के सामंजस्य को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए।
- सामान्य रूप से मानवाधिकारों और अधिक विशिष्ट मामलों के संबंध में राष्ट्रीय स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना।

CHAHAL ACADEMY

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हालिया नवाचार

- HRCNet पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करना।
- मामलों की नकल से बचने के लिए HRCNet पोर्टल में SHRCs पर बोर्ड लगाना।
- रिपोर्ट को सीधे HRCNet पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिकारियों के लिए प्रावधान।
- शिकायतों के पंजीकरण के लिए लगभग तीन लाख आम सेवा केंद्रों को शामिल करना।
- उस वेबसाइट को फिर से खोलना जहां स्थिति और मामलों के सभी आदेश अपलोड किए जाते हैं।
- एक समर्पित MADAD काउंटर जो शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने में सहायता करता है।

भारत के संविधान का निर्माण

भारत का संविधान

- भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान इसका मूल स्थान है यानी देश के सभी कानूनों का जनक।
- भारतीय राज्य (विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के तीन स्तंभ संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं।
- भारत का संविधान हमारी विविध आबादी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अनूठा और सबसे व्यापक दस्तावेज है। इसने विभिन्न सिद्धांतों को बहुत खूबसूरती से निर्धारित किया है और इस पर कार्य करता है कि किसी देश की सरकार के अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए।

भारतीय संविधान का विकास –

- भारतीय संविधान की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास का अध्ययन दो व्यापक प्रमुखों के तहत किया जा सकता है –

1. कंपनी नियम (1773 – 1858)
2. द क्राउन रूल (1858 – 1947)

- व्यापार उद्देश्य के लिए 17 वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए और उसके बाद, उन्होंने धीरे–धीरे अधिक शक्ति प्राप्त की। बाद में, उन्होंने राजस्व और स्वदेशीकरण एकत्र करने के अधिकार प्राप्त किए। ऐसा करने के लिए, उन्होंने विभिन्न कानून और नियम बनाए।
- 1833 के चार्टर एक्ट के साथ, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा एक केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया।
- कंपनी का शासन अंततः भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियमन के साथ समाप्त हुआ।
- 1861, 1892 और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियमों ने वायसराय की परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने कुछ प्रांतों (राज्यों) में विधायी शक्तियां बहाल कर दीं।
- बाद में, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन के साथ, सभी राज्यों में विधान परिषदें अस्तित्व में आईं।
- अंग्रेजों ने अलग–अलग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ द्विसदनीय संरचना को अपनाया। यह पहली बार था जब लोग प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे।
- भारत के संविधान ने बाद में शासन के इस अर्ध–संघीय और द्विसदनात्मक ढांचे को अपनाया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियमन संविधान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था क्योंकि इस कानून ने शासन की शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया था। मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार भारत की संविधान सभा अस्तित्व में आई।
- दो साल से अधिक समय तक विचार–विमर्श के बाद, संविधान सभा ने अंततः 26 नवंबर, 1949 को संविधान को मंजूरी दी, जिसे अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1948 की संवैधानिक प्रक्रिया में प्रमुख समयरेखा –

1946	ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया और सत्ता हस्तांतरण के लिए तौर–तरीकों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।
अगस्त 14, 1947	समितियों के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया।
अगस्त 29, 1947	प्रारूपण समिति की स्थापना की जाती है।
दिसंबर 6, 1947	संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव के बाद संविधान सभा ने पहली बार औपचारिक रूप से बैठक की।
नवंबर 4, 1947	ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया और प्रस्तुत किया जाता है।
1948–1949	संविधान सभा जनता के लिए खुले सत्रों में मिलती है।
नवंबर 26, 1949	संविधान सभा ने अंतिम मसौदे को आधिकारिक बना दिया है।
जनवरी 26, 1950	नया संविधान लागू।

भारतीय संसद – प्रदर्शन और चुनौतियां

संसद प्रतिनिधि शासन की भारतीय प्रणाली में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इसने सत्तर वर्षों तक उल्लेखनीय कार्य किया है। इसने ऐसा विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक विविधता वाले देश में आंतरिक तनाव को प्रबंधित करने में मदद करके किया है। कई सामाजिक सुधारों और आर्थिक प्रगति का नेतृत्व संसद द्वारा किया गया है।

भारत में केंद्रीय विधायी निकाय के रूप में, संसद की चार मुख्य भूमिकाएँ हैं। पहला, यह कानून बनाती है। दूसरा, अपने कार्यों के लिए इसमें कार्यपालिका शामिल होती है। तीसरा यह सरकारी वित्त आवंटित करता है और चौथा यह नागरिकों के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय संसद का कामकाज

- वर्षों से, संसद कम दिन के लिए बैठक कर रही है।
- 1950 के दशक में पिछले बीस वर्षों में बैठने के दिनों की संख्या 125–140 से घटकर लगभग 70 दिन रह गई है।
- 15 वीं लोक सभा की अवधि के दौरान, निर्धारित समय का एक तिहाई भाग खो गया था।
- संसद शायद ही पहले या तीसरे पढ़ने पर किसी बिल पर चर्चा करती है।

सुधार का क्षेत्र –

- संसद की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कुछ संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इनमें दलबदल–रोधी कानून को निरस्त करना और सभी मतों को विधेयकों और प्रमुख वाद–विवादों में दर्ज करना शामिल है।
- इनमें समितियों के लिए सभी बिलों का हवाला देना और समितियों के लिए समर्थन प्रणाली को मजबूत करना भी शामिल है।

1. दल–बदल विरोधी कानून

- संविधान की दसवीं अनुसूची को 1985 में पचासवें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
- यह एक सांसद की अयोग्यता के लिए प्रदान करता है
  – यदि वह अपनी पार्टी से दोष लगाता है या
  – अगर वह अपनी पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप के अनुसार वोट नहीं देता है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि दलबदल विरोधी कानून ने कार्यपालिका के काम की निगरानी करने के लिए संसद की शक्ति को कमजोर कर दिया है।
- इसलिए, इस प्रावधान को संविधान में फिर से लाने और विचार करने का समय है कि क्या इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

2. रिकॉर्डेड वोटिंग

- हमारी संसद में, अधिकांश विधेयकों और गतियों को ध्वनि मतों द्वारा पारित किया जाता है।
- अध्यक्ष The aye कहने के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों से पूछता है, और फिर पदहदव कहने का विरोध करने वाले, और फिर वह/वह न्याय करता है कि किस पक्ष में अधिक आवाजें हैं।
- इसका अर्थ है कि मतदाता अपने सांसदों से उनके मतदान व्यवहार पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।

3. समिति प्रणाली

- काम और विषयों की विशाल मात्रा को देखते हुए, 500 से अधिक सदस्यों के घर में सभी मुद्दों पर विस्तार से जांच करना मुश्किल हो जाता है।
- इसलिए, संसद ने कई समितियों का गठन किया है।
- प्रत्येक समिति में आम तौर पर 20–35 सदस्य होते हैं, जो विभिन्न मुद्दों की छानबीन करते हैं और पूरे सदन को सिफारिशें देते हैं।
- इनमें वित्तीय समितियाँ, विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs), और विभिन्न अन्य समितियाँ शामिल हैं।
- ये स्थायी समितियाँ विशेषाधिकार और नैतिकता को देखने वाले, दोनों सदनों के दैनिक एजेंडे को निर्धारित करने और अधीनस्थ कानून को देखने जैसी हैं।
- संसदीय समितियों के कामकाज को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- सदस्यों की सहायता के लिए उनके पास विशेषज्ञ अनुसंधान कर्मचारी नहीं हैं।
- अक्सर महत्वपूर्ण बिल इन समितियों को संदर्भित नहीं किए जाते हैं।
- टीटी यह अनिवार्य कदम बनाने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने का समय हो सकता है।
- इन समितियों के सदस्यों की उपस्थिति 50 प्रतिशत के करीब है, सदन में 80 प्रतिशत से अधिक पतली है।

CHAHAL ACADEMY

निष्कर्ष

संसद प्रतिनिधि शासन की भारतीय प्रणाली में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। कई सामाजिक सुधारों और आर्थिक प्रगति का नेतृत्व संसद द्वारा किया गया है। हालांकि, ऐसे तरीके हैं जिनसे इसकी प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है। इनमें दलबदल विरोधी कानून को रद्द करना, रिकॉर्ड मतदान को अनिवार्य बनाना और समिति प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

पंचायती राज व्यवस्था

भारत में, पंचायती राज अब एक शासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इस प्रणाली में ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयाँ हैं। प्रणाली के तीन स्तर हैं – ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मंडलपरिषद या ब्लॉक समिति या पंचायतसमिति (ब्लॉक स्तर) और जिलापरिषद (जिला स्तर)।

संविधान सभा और पंचायती राज

संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1993 के पूर्व की स्थिती

- स्वतंत्रता और भारत के संविधान को अपनाने के बाद, 1952 में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- ये सामुदायिक विकास परियोजनाएं शांतिनिकेतन, वडोदरा और नीलोखेड़ी में प्रयोगों के अनुरूप थीं।
- 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया।
- बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की कि, सांविधिक प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से सामुदायिक कार्यों में सार्वजनिक भागीदारी का आयोजन किया जाना चाहिए।
- यह वैधानिक प्रतिनिधि निकाय ग्राम स्तर पर एजेंसियां हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।
- ये एजेंसियां जिम्मेदारी ग्रहण कर सकती हैं और सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं।
- जयप्रकाश नारायण समिति ने पंचायती राज के विचार को और मजबूत किया।
- 1971 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के तहत सामुदायिक विकास मंत्रालय लाया गया था।
- शब्द 'सामुदायिक विकास' को 'ग्रामीण विकास' से बदल दिया गया।
- 1978 की अशोक मेहता समिति ने संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक संस्था के रूप में पेश करने की सिफारिश की थी।
- पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 एक अनिवार्य प्रावधान के रूप में नियमित अंतराल पर प्रत्यक्ष चुनाव लाया।
- इन चुनावों ने चुनाव स्थगित करने में राज्य की विवेकाधीन शक्ति को नष्ट कर दिया।
- 64 वें संशोधन विधेयक को यह कहते हुए पेश किया गया कि – पंचायत राज लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- 64 वें संशोधन विधेयक में यह भी कहा गया है कि – पंचायत राज का संवैधानिक संरक्षण लोगों के प्रतिनिधि संस्थानों के रूप में उनके कामकाज के लिए होना चाहिए।
- बाद में, 64 वें संशोधन विधेयक के बाद 65 वां संशोधन विधेयक लाया गया।
- 65 वें संशोधन विधेयक ने पंचायत राज की तरह शहरी स्थानीय निकायों को स्थापित करने की मांग की गई।

संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1993

- वर्ष 1992–93 में 73 वें और 74 वें संशोधन को भारतीय संविधान में लाया गया।
- इन संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी।
- 73 वें संशोधन अधिनियम ने पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की।
- इसने एससी और एसटी के लिए पंचायतों की सदस्यता के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण भी शुरू किया।
- इसके अलावा 73 वां संशोधन अधिनियम पेश किया
  – अध्यक्षों का कार्यालय,
  – महिलाओं के लिए एक तिहाई से कम सीटों का आरक्षण नहीं,
  – पंचायतों के लिए पांच साल का निश्चित कार्यकाल और किसी भी पंचायतों के दमन की पूर्व संध्या पर छह महीने के भीतर चुनाव कराने,
  – पंचायत की सदस्यता की अयोग्यता,
  – राज्य विधानमंडल की शक्तियों को शासन के तीसरे स्तर के रूप में डिफैक्टो मान्यता पर अधिकार।
- राज्य की समेकित निधि से सहायता के माध्यम से पंचायतों के लिए वित्तीय अधिकार अनुदान के माध्यम से बनाए गए हैं।

- राज्य द्वारा पंचायतों को असाइनमेंट या निर्दिष्ट करों, कर्तव्यों, टोलों और शुल्क की पंचायतों द्वारा राजस्व का विनियोजन, वित्त आयोग की स्थापना आदि।

73 वं संशोधन के बाद –

- ग्राम पंचायतों की डिजिटलकरण प्रक्रिया द्वारा पारदर्शिता लाई गई
- सुशासन के सिद्धांतों को पंचायती राज व्यवस्था में शामिल किया गया है।
- लोकपाल, सामाजिक लेखा परीक्षा, मॉडल लेखा प्रणाली, पंचायत प्रदर्शन आकलन पहल संस्था के भीतर अनुशासन और प्रगति विकसित करने के लिए शुरू की गई थी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी नीतियां पेश की गईं, जो पंचायतों को योजना और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अनिवार्य करती हैं।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF) को पंचायतों के लिए वित्तीय बैकअप के रूप में पेश किया गया है।
- बीआरजीजे को विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने, योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करने और पंचायतों की क्षमता का निर्माण करने के लिए पेश किया गया था।
- 13 वें केंद्रीय वित्त आयोग पुरस्कार ने पंचायत राज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं। इसके द्वारा पंचायतों के लिए विभाज्य कर पूल का एक हिस्सा उन्हें अनुदान देकर बनाया गया है।
- पर्याप्त धन की कमी एक कमजोर क्षेत्र है। पंचायतों के अपने स्वयं के धन जुटाने में सक्षम होने के लिए विस्तार करने की आवश्यकता है।
- पंचायतों के कामकाज में क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के हस्तक्षेप ने भी उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
- 73 वें संशोधन ने केवल स्थानीय स्वशासी निकायों के निर्माण को अनिवार्य किया।
- 73 वें संशोधन शक्तियों, कार्यों और वित्त को सौंपने का निर्णय ने राज्य विधानसभाओं पर छोड़ दिया, जिसमें पीआरआई की विफलता है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी के प्रावधान जैसे विभिन्न शासन कार्यों का स्थानांतरण अनिवार्य नहीं था।
- इसके बजाय संशोधन ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है।
- यह वास्तव में कार्यों को विकसित करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए छोड़ दिया गया था।
- संशोधन की प्रमुख विफलता पीआरआई के लिए वित्त की कमी है।
- स्थानीय सरकारें या तो स्थानीय करों के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ा सकती हैं या अंतर–सरकारी हस्तांतरण प्राप्त कर सकती हैं।
- पीआरआई के दायरे में आने वाले विषयों के लिए भी कर लगाने की शक्ति, विशेष रूप से राज्य विधायिका द्वारा अधिकृत की जानी चाहिए।
- 73 वें संशोधन ने इसे राज्य विधानसभाओं के लिए खुला विकल्प होने दिया – एक ऐसा विकल्प जो ज्यादातर राज्यों ने प्रयोग नहीं किया है।
- हालांकि वित्त आयोगों, हर स्तर पर, धन का अधिक से अधिक हस्तांतरण के लिए वकालत की है, वहाँ अवक्रमित कोषों के लिए राज्यों द्वारा थोड़ा कार्रवाई की गई है।
- पीआरआई उन परियोजनाओं को लेने के लिए अनिच्छुक हैं जिन्हें किसी भी सार्थक वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता होती है।
- पीआरआई अक्सर सबसे बुनियादी स्थानीय शासन की जरूरतों को हल करने में असमर्थ होते हैं।
- PRIs भी संरचनात्मक कमियों से ग्रस्त हैं जैसे कोई सचिवीय समर्थन नही होना या तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर ।
- इसने नीचे की योजना के एकत्रीकरण को प्रतिबंधित कर दिया।
- तदर्थवाद उपस्थित है यानी ग्राम सभा, ग्राम समिति की बैठकों में कार्यसूची की स्पष्ट सेटिंग का अभाव है और कोई उचित संरचना नहीं है।
- महिलाओं और अनुसूचित जाति हालांकि / अनुसूचित जनजातियों पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिला है जो आरक्षण के माध्यम से 73 वें संशोधन द्वारा सौंपा गया है लेकिन महिलाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के मामले में पंच–पति और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की उपस्थिति क्रमशः है।
- पीआरआई की संवैधानिक व्यवस्था के 26 साल बाद भी जवाबदेही व्यवस्था बहुत कमजोर है।

आगे की राह –

पिछले 17 वर्षों में पंचायती राज प्रणाली की प्रगति के बावजूद, 1993 से, कई एजेंडे हैं, जिन्हें महात्मा गांधी द्वारा वांछित पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए लागू किया जाना बाकी है।

- पर्याप्त स्टाफ, कार्यालय अंतरिक्ष और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
- पंचायती राज संस्थानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना।
- 'विवेक' (अनुच्छेद 243 जी), शब्द को हटाना और 3 एफ के विचलन के लिए राज्यों पर अनिवार्य दायित्व बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम (पीईएसए) के प्रावधानों को लागू करना।
- उत्तर पूर्वी राज्यों, 6 वीं अनुसूची क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
- PRIs के निर्वाह की प्राथमिकता वाले राज्य वित्त आयोग के प्रभावी कामकाज की तत्काल आवश्यकता।

CHAHAL ACADEMY

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in